बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 128

आरामदेह स्थिति

सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़े दिखाते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर मई के 2.8 फीसदी से कम होकर जून में 2.1 फीसदी रह गई। मुद्रास्फीति की दर में यह गिरावट मोटे तौर पर खाद्य कीमतों में कमी की बदौलत आई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में 1.06 फीसदी की गिरावट आई। इसमें सब्जियों की कम कीमत का काफी योगदान रहा जिनमें 19 फीसदी की कमी देखी गई। अच्छे मॉनसून के पूर्वानुमान को देखते हुए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी खाद्य कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। बहरहाल, यह भी ध्यान देने लायक है कि खाद्य क्षेत्र में कीमतों की कमी में एकरूपता नहीं है। उदाहरण के लिए तेल एवं वसा की कीमतों में 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई और इस पर नीतिगत स्तर पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि आने वाले महीनों में समग्र मुद्रास्फीति दर के सहज स्तर पर बने रहने की उम्मीद है।

बहरहाल, उम्मीद से कम मुद्रास्फीति की दर होने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आगामी अगस्त माह में होने वाली बैठक में शायद नीतिगत रीपो दर में फिर कटौती न करे और इसकी कई वजह हैं। पहली बात, मुद्रास्फीति के अनुकूल परिणामों के अनुमान के कारण एमपीसी ने जून की बैठक में ही नीतिगत रीपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर दी थी। मौजूदा चक्र में उसने अब तक नीतिगत दर में 100 आधार अंकों की कटौती कर दी है और वह चाहती है कि व्यवस्था में इसका प्रभाव नजर आए। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ने व्यवस्था में नकदी की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप नकदी अधिशेष की स्थिति बनी है और वेटेड एवरेज कॉल रेट (डब्ल्यूएसीआर यानी मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य) रीपो दर से नीचे बनी हुई है। नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में कमी का प्रभाव नजर आने पर बैंकिंग व्यवस्था में और अधिक नकदी नजर आ सकती है। रिजर्व बैंक ने जून में सीआरआर में 100 आधार अंकों की कटौती की थी जिसे चार चरणों में लागू होना है। अतिरिक्त नकदी और डब्ल्यूए-सीआर के नीतिगत दर से नीचे रहने के कारण शायद एमपीसी समायोजन में तत्काल इजाफा न करना चाहे।

तीसरा, मौद्रिक नीति को दूरदर्शी होना चाहिए और उसे पिछले महीने के मुद्रस्फीति के आंकड़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह ध्यान देना उचित रहेगा कि एमपीसी की जून की बैठक में अनुमान जताया गया था कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति दर 4.4 फीसदी रह सकती है जो चार फीसदी के लक्ष्य से ऊपर है। इसके अलावा अगस्त और उसके बाद की बैठकों में एमपीसी 2026-27 के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों पर केंद्रित हो जाएगी। ऐसे में जब तक अगले वर्ष के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान 4 फीसदी के लक्ष्य से काफी कम नहीं रहते तब तक एमपीसी शायद नीतिगत दरों में कटौती को समझदारी न माने।

रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के शोध के मुताबिक वास्तविक नीतिगत दर, जो न तो बढ़त वाली है और न ही संकुचन वाली, 2023-24 की चौथी तिमाही में 1.4 से 1.9 फीसदी के बीच रही। ऐसे में अगर आगामी समय में मुद्रास्फीति की दर 4 फीसदी के लक्ष्य के करीब बनी रहती है तो एमपीसी संभवतः रीपो दर को वर्तमान स्तर यानी 5.5 फीसदी के स्तर पर बनाए रखेगी। दरों में कटौती की संभावना तब बनेगी जब मुद्रास्फीति अनुमान लक्षित दर से काफी नीचे हो जाए। जहां तक वृद्धि को सहारा देने की बात है तो फिलहाल जो हालात हैं उनमें एमपीसी और रिजर्व बैंक ने अपनी भूमिका निभा दी है। अब सरकार को टिकाऊ सुधारों के साथ कारोबारी जगत तो प्रोत्साहित करना है कि वे निवेश करें।

ऋण वृद्धि का नया वाहक है एमएसएमई क्षेत्र

छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए ऋण वृद्धि अन्य तमाम क्षेत्रों को पीछे छोड़ रही है। परंतु आगे परिसंपत्ति की गुणवत्ता का प्रश्न आएगा। बता रहे हैं टीटी राम मोहन

देश का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत स्थिति में है। विभिन्न मानकों मसलन पूंजी पर्याप्तता, प्रॉविजन कवरेज अनुपात, नकदी कवरेज अनुपात, परिसंपत्ति पर रिटर्न और ऋण के अनुपात में सकल फंसे हुए कर्ज (जीएनपीए) के आधार पर यह क्षेत्र आज ऐसी मजबूती दिखा रहा है जैसी पांच साल पहले सोची भी नहीं जा सकती थी।

व्यवस्था में पूंजी पर्याप्तता 17.3 फीसदी है। सरकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता 16.2 फीसदी है। इसका नियामकीय रूप से तय न्यूनतम स्तर 5 फीसदी से ऊपर रहना समझदारी भरा और स्थिरता प्रदान करने वाला है। परिसंपत्ति पर रिटर्न (आरओए) की बात करें तो वह सभी बैंकों के लिए 1.4 फीसदी रहा। सरकारी बैंकों का आरओए 1.1 फीसदी रहा जो बैंकिंग में 1 फीसदी के मानक से बेहतर है।

जब कोई बैंक 1 फीसदी या अधिक का आरओए उत्पन्न करता है तो वह बाजार से पूंजी हासिल करने को लेकर निश्चिंत रह सकता है। दूसरे शब्दों में सरकारी बैंकों को पूंजी सहायता के लिए सरकार की बाट नहीं जोहनी होती। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सरकारी बैंक उच्च रिटर्न हासिल करने वाले निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करें? इसका जवाब यह है कि जब तक वे बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं, वे अपनी शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र मजबूत कदमों से चलता रहेगा। हमारे पास निजी बैंक हैं जो आम जनता को सेवाएं देते हुए अपने मुनाफे को अधिकतम करना चाहते हैं तो वहीं सरकारी बैंक भी हैं जो मुनाफे के साथ-साथ बाजार और सामाजिक लक्ष्यों का भी ध्यान रखकर चलते हैं। यह पूरा मॉडल तब तक व्यवहार्य बना रहता है जब तक कि मुनाफे का मानक पूरा होता रहता है। लब्बोलुआब यह है कि फिलहाल बैंकिंग मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (जून 2025) से कुछ बिंदु उभरते हैं।

सबसे पहले, 2024-25 में ऋणवृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट आई और यह 2023-24 के 16 फीसदी और 2022-23 के 15.4 फीसदी से कम होकर 11 फीसदी रह गई। 2024-25 में सरकारी बैंकों की ऋण वृद्धि निजी बैंकों से अधिक रही। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्षों की गिरावट के बाद उनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है।

ऋणवृद्धि में धीमापन सोचा समझा था और इसे नियामक ने तय किया था। रिजर्व बैंक की दो चिंताएं थीं। पहली, ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से आगे निकल रही थी और इसका अर्थ यह था कि इसकी भरपाई उच्च लागत वाले अस्थिर फंड्स से की जा रही थी। दूसरा, पर्सनल लोन और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे क्षेत्रों में वृद्धि असहज करने के स्तर तक अधिक थी। अप्रैल 2022 से मार्च 2024 के बीच खुदरा क्षेत्र को बैंक ऋण 25.2 फीसदी की गति से बढ़ा और सेवा क्षेत्र को ऋण,जिसमें एनबीएफसी को दिया गया बैंक ऋण शामिल है, वह 22.4 फीसदी की गति से बढ़ा। यह 16.4 फीसदी की समग्र ऋण वृद्धि से काफी अधिक था आरबीआई ने दोनों क्षेत्रों पर जोखिम भार बढ़ाया जिससे इनमें ऋण वृद्धि में कमी आई।

दूसरा, ऋण वृद्धि में धीमेपन ने मुनाफे में वृद्धि पर विपरीत असर नहीं डाला। सभी बैंकों के लाभप्रदता में मामूली कमी आई लेकिन सरकारी बैंकों की लाभप्रदता 0.9 फीसदी से बढ़कर 1.1 फीसदी हो गई। सभी बैंकों का कर पश्चात लाभ 17 फीसदी बढ़ा। सरकारी बैंकों में यह 32 फीसदी बढ़ा। इसमें परिचालन लाभ का प्रमुख योगदान रहा।

तीसरी बात, 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों यानी एमएसएमई को ऋण ने अन्य सभी क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया। एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण में 14.1 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई जबकि सेवा क्षेत्र में यह वृद्धि 11.2 फीसदी और खुदरा ऋण में 11.7 फीसदी थी। खुदरा ऋण में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा मार्च 2024 के 17 फीसदी से बढ़कर मार्च 2025 में 17.7 फीसदी हो गया।

चौथी बात, व्यवस्था में सकल एनपीए ऋण के 2.3 फीसदी रह गया है जो अब तक का न्यूनतम है। एमएसएमई के एनपीए में भारी कमी आई है। इस क्षेत्र का सकल एनपीए 2022-23 के 6.8 फीसदी से घटकर 2023-24 में 4.5 फीसदी और 2024-25 में 3.6 फीसदी रह गया है।

एमएसएमई क्षेत्र का एनपीए ऐतिहासिक रूप से 9 फीसदी या उससे अधिक रहा है। कुछ वर्ष पहले तक सरकारी बैंकों के बैंकर आश्चर्य जताते थे कि भला एमए-सएमई की ऋण की दिक्कतों से कैसे निपटा जाएगा। 2024-25 में एसएमई क्षेत्र को सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों से अधिक ऋण दिया। इससे पुराना रुझान उलट गया। क्या एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण में कुछ बुनियादी परिवर्तन आया है। उनके फंसे कर्ज में भारी कमी कैसे आई?

रिजर्व बैंक को केवल आंकड़े पेश करने के बजाय इस पर प्रकाश डालना चाहिए था। यह भी सही है कि एमएसएमई की फाइनैंसिंग के लिए बैंकरों को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी टीआरईडीएस जैसे नवाचारी तरीके मिले हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी विभागों से एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल्स यानी व्यापारिक प्राप्तियों पर फाइनैंसिंग की सुविधा प्रदान करता है। इन्हें कम जोखिम वाला माना जाता है।

वर्ष 2023-24 में एमएसएमई के बहीखाते में टीआरईडीएस बुक की हिस्सेदारी 2.7 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 10 फीसदी थी। इससे समूचे एम-एसएमई क्षेत्र के 3.6 फीसदी का एनपीए स्तर समझ नहीं आता। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) में एनपीए का स्तर 5.6 फीसदी है। याद रहे कि इसे मई 2020 में महामारी के दौरान शुरू किया गया था ताकि एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया जा सके। इसकी अहर्ता शर्तें काफी सख्त थीं।

वर्ष 2021-23 के बीच ईसीएलजीएस के तहत दिया गया ऋण करीब 3.68 लाख करोड़ रुपये या 2024-25 में एमएसएमई के बकाया ऋण का 12 फीसदी था। अगर ईसीएलजीएस ऋण का कुल एनपीए 5.6 फीसदी और कुल एम-एसएमई ऋण का एनपीए 3.6 फीसदी है तो यकीनन बाकी 88 फीसदी एमएसएमई ऋण का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसे समझने की जरूरत है। क्या इसकी व्याख्या विगत कुछ वर्षों में एमएसएमई ऋण में आई तेजी से की जा सकती है? अगर ऐसा है तो आने वाले वर्षों में फंसे कर्ज में इजाफा नजर आएगा। ऐसे में रिजर्व बैंक के स्ट्रेस टेस्ट के अनुमान आशावादी साबित हो सकते हैं।

बैंकों ने कर्ज देने में जोखिम से बचने का नजरिया अपनाया है। ऋण वृद्धि उद्योग को दिए गए कार्यशील पूंजी ऋण, खुदरा ऋण और एनबीएफसी सहित सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण के भरोसे हुई है। वर्ष 2024-25 में एमएसएमई को दिया गया ऋण अन्य क्षेत्रों को दिए गए ऋण से कहीं अधिक तेजी से बढ़ा। यह एक बड़ा बदलाव था। इस बदलाव का परिसंपत्ति गुणवत्ता पर प्रभाव देखने के लिए हमें एक दो वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी।

असली परीक्षा की घड़ी तब आएगी जब निजी निवेश बढ़ने पर बैंक साविधि ऋण और परिवोजना वित्त की रफ्तार बढ़ाएंगे। एनपीए में भारी गिरावट का जश्न तब तक नहीं मनाया जाना चाहिए जब तक कि बैंक हाल के वर्षों की तुलना में अधिक जोखिम उठाना न शुरू कर दें।

ट्रंप के बाध्यकारी समझौते से राह कितनी मुश्किल

भारत सरकार और उद्योग पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से टैरिफ या शुल्क में राहत के लिए 9 जुलाई की समय-सीमा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई लोगों को भारत और अमेरिका के बीच आखिरी समय में व्यापार समझौते की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। इसके बजाय अमेरिका ने यह विराम अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी जिससे समय तो मिला लेकिन देशों पर अमेरिका की शर्तों पर सौदे करने का दबाव बढ़ गया।

वास्तव में अमेरिका जिन समझौतों की पेशकश कर रहा है, वे सामान्य व्यापार समझौते नहीं हैं बल्कि दबाव डालकर किए गए पारस्परिक सहमति समझौते हैं। वे एकतरफा समझौते केवल उसी स्थिति में टैरिफ से राहत देते हैं जब दूसरे देश, अमेरिका के लिए निर्यात की गारंटी देने के साथ ही राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी होने वाली जीत पर सहमत हों। इस तरह के समझौते में निष्पक्षता या पारस्परिक लाभ की परवाह बहुत कम की जाती है।

'लिबरल डे' टैरिफ

यह कहानी 2 अप्रैल को शुरू हुई, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 57 देशों पर अलग-अलग आधार पर टैरिफ लगाने की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत, यूरोपीय संघ (ईयू) के निर्यात पर 20 प्रतिशत, और अन्य पर 54 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ कि चीन और जापान ने मिलकर 1 लाख करोड़ डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए जिससे वैश्विक बाजार और वॉल स्ट्रीट दोनों को समान रूप से झटका लगा।

जवाब में व्हाइट हाउस ने भी 9 अप्रैल को अपना रुख नरम कर लिया। टैरिफ को करीब 90 दिन के लिए टाल दिया और चीन को छोड़कर अधिकांश आयातों पर 10 प्रतिशत का एकसमान टैरिफ लगाया। टैरिफ पर लगाई गई इस विराम अवधि को देशों के लिए अमेरिका के साथ तेजी से द्विपक्षीय सौदों पर बातचीत करने के लिए एक 'गुंजाइश' के रूप में पेश किया गया था।

समय-सीमा तक केवल दो करार

अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद, 8 जुलाई की समय सीमा तक केवल दो देशों, वियतनाम और ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। शुरुआत में 46 प्रतिशत टैरिफ का सामना करने वाले वियतनाम ने एक समझौते पर बातचीत की जिसके तहत अमेरिका का सामान, वियतनाम में बिना शुल्क के प्रवेश करता है जबकि वियतनाम के निर्यात पर अमेरिका में अब भी 20 प्रतिशत टैरिफ लगता है। ब्रिटेन ने 2,500 अमेरिकी उत्पादों पर बड़ी टैरिफ कटौती की पेशकश की और इसने न्यूनतम पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने की कोशिश की।

अजय श्रीवास्तव

निराशा में ट्रंप को और देशों को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए टैरिफ विराम को 31 जुलाई तक बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 7 जुलाई को उन्होंने 14 देशों को व्यक्तिगत चेतावनी पत्र भेजे। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाखस्तान और ट्यूनीशिया को बताया गया कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 अगस्त से 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। बोस्निया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के लिए 30-40 प्रतिशत शुल्क की बात की गई। इस सप्ताह ऐसी और भी 'अंतिम चेतावनी' मिलने की उम्मीद है।

लेकिन अमेरिका ने एक शर्त भी रख दी है कि कोई भी देश किसी तरह का बदला लेने की हिम्मत न जुटा पाएं। अमेरिका ने कहा कि जो देश जवाबी कार्रवाई में अपने टैरिफ बढ़ाते हैं उन्हें और भी अधिक अमेरिकी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।

देश क्यों विरोध कर रहे हैं?

अमेरिका 20 देशों के साथ बातचीत कर रहा था। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर केवल दो देशों ने क्यों हस्ताक्षर किए? वे भी वास्तविक व्यापार समझौते नहीं हैं बल्कि यह दबाव में डालकर किए गए पारस्परिक सहमति समझौते हैं। इनमें अस्थायी टैरिफ राहत के बदले में अमेरिकी सामानों की गारंटी वाली खरीद और साझेदारों द्वारा की गई संरचनात्मक रियायतें शामिल हैं। इसमें कोई पारस्परिक लाभ शामिल नहीं है।

उदाहरण के तौर पर, अमेरिका के साथ जापान और दक्षिण कोरिया के औपचारिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हुए हैं जो क्रमशः 2020 और 2012 से लागू हैं। इन दोनों देशों ने 90 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ खत्म कर दिया है। फिर भी दोनों देशों को अब केवल व्यापार अधिशेष के लिए 25 प्रतिशत नए टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप, बाजार तक पहुंच बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि वह गारंटी के साथ मांस, गैस, विमान और अधिक चीजों की खरीद की मांग कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया का मामला भी अजीब है। वर्ष 2005 के एफटीए के तहत 99 प्रतिशत अमेरिकी वस्तुओं को देश में बिना शुल्क के आने देने और अमेरिका के साथ 17.9 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहने के बावजूद, उस पर अधिक अमेरिकी गोमांस और अन्य सामान खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका की गणना में, व्यापार संतुलन, एफटीए और पिछली रियायतें अब मायने नहीं रखतीं हैं।

अहम मोड़ पर भारत

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक खबर नहीं है लेकिन भारत ने अपनी पेशकश कर दी है और इसने अमेरिकी मांगों का जवाब देने के साथ ही अपनी शर्तें भी तय कर दी हैं। अमेरिका का कोई भी जवाब या समझौते की घोषणा अचानक हो सकती है। संभवतः किसी भी दिन ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर देर रात के पोस्ट के माध्यम से भी यह हो सकता है। भारत संयुक्त बयान को तरजीह दे सकता है लेकिन यह सब ट्रंप के मिजाज पर निर्भर करता है। संभावित समझौते के मुख्य बिंदु भी सामने आ रहे हैं। खबरों के अनुसार, भारत ऑटोमो-बाइल और अन्य औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम करने और सीमित मात्रा में एथनॉल, बादाम, सेब और शराब के आयात की अनुमति देने तैयार है। भारत नियामकीय सुधारों पर भी सहमत हो सकता है। बदले में, अमेरिका तरजीही देशों के टैरिफ में कोई कमी नहीं करेगा, केवल 'लिबरेशन डे' शुल्क ही हटाएगा। कटौती के बाद भी, भारतीय निर्यात पर अमेरिकी मूल टैरिफ के ऊपर संभवतः 10-15 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

समझौते के बाद, शांति की गारंटी नहीं

उदाहरण के तौर पर रियो में हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद इसके सदस्य देशों ने अमेरिका की एकतरफा व्यापार नीतियों की आलोचना की और एक साझी मुद्रा शुरू करने पर चर्चा की। इस पर ट्रंप ने 'अमेरिकी-विरोधी' नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सभी ब्रिक्स सदस्य देशों पर नया 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी।

वैश्विक व्यापार पर प्रभाव

मई 2025 में, चीन का कुल निर्यात पिछले साल की तुलना में सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन अमेरिका में चीन का निर्यात 34.5 प्रतिशत कम हो गया जो बढ़ते तनाव का एक स्पष्ट संकेत है। इस नुकसान की भरपाई के लिए, चीन ने अपना ध्यान अन्य बाजारों की ओर देना शुरू किया। ऐसे में यूरोपीय संघ में चीन का निर्यात 12 प्रतिशत, आसियान देशों में 15 प्रतिशत और भारत में 12.4 प्रतिशत बढ़ा। इसके कारण तीसरे देशों के बाजारों में माल की डंपिंग और अनुचित प्रतिस्पर्धा की चिंताएं बढ़ीं जिससे अंदाजा हुआ कि अमेरिकी टैरिफ किस तरह व्यापार को बाधाकारी तरीके से नया रूप दे रहे हैं।

रणनीतिक धैर्य का समय

वियतनाम में निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 93.8 प्रतिशत है, इसके विपरीत भारत का यह आंकड़ा केवल 21.9 प्रतिशत है। यह भारत के लिए काफी राहत की बात है।

(लेखक जीटीआरआई के संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

जटिल है रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) जैसी योजनाएं अपने उद्देश्य में महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अपनी संरचना और क्रियान्वयन के कारण अक्सर जरूरतमंद वर्गों तक प्रभावी रूप से पहुंच पाने के उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहीं। ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के बेरोजगार युवा इस योजना से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग प्रायः असंगठित क्षेत्र में काम करने को विवश होते हैं, जहां कर्मचारी भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध ही नहीं होतीं। जटिल पात्रता मानदंड, जैसे आय सीमा, पहले ईपीएफ से न जुड़ा होना, और नियत तिथि के बाद नियुक्त होना आदि शर्तें, इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में अड़चन बनती हैं। दस्तावेजीकरण की जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे नियोक्ता या तो योजना के बारे में नहीं जानते, या फिर उन्हें अनुपालन करना अत्यधिक बोझिल लगता है। कई नियोक्ता शहरी, अंग्रेजी बोलने वाले और सामाजिक रूप से प्रभावशाली वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वंचित तबकों के प्रतिभाशाली युवा पीछे हो रहे हैं। यदि इस योजना को सरल बनाया जाए, पात्रता की शर्तों को लचीला किया जाए, स्थानीय भाषा में जानकारी प्रसारित हो, और आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन तथा पंचायत स्तर तक ले जाया जाए, तो यह देश में सतत, समावेशी और सामाजिक न्याय आधारित रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मुनीष भाटिया, मोहाली

कई नियोक्ता शहरी और सामाजिक रूप से प्रभावशाली वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वंचित तबकों के युवा पीछे हो रहे हैं

यमन में निमिषा प्रिया की फांसी टलने से मिली राहत

भारत के केरल राज्य की निवासी 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया अभी यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है। यह ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। मंगलवार की सुबह एक राहत देने वाली खबर आई कि यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा की फांसी यमन के अधिकारियों ने टाल दी है। भारतीय नर्स को बुधवार को फांसी दी जानी थी। केरल के पालक्काड जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली निमिषा जुलाई 2017 में यमन के एक नागरिक की हत्या की दोषी करार दी गई है। कहा जा रहा है कि यमन के एक सूफी विद्वान के नेतृत्व में निमिषा की फांसी रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रयास सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार के कहने पर किए जा रहे हैं। सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों और यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी के परिवार के बीच मंगलवार को धमार में बैठक की खबरें आई थीं। निमिषा प्रिया महदी की हत्या मामले में दोषी साबित हुई है। केंद्र ने भी सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि सरकार अपनी ओर से हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन यमन की स्थिति को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत में कहा था कि सरकार अपने नागरिकों को बचाना चाहती है और इस मामले में हरसंभव प्रयास कर रही है। ऐसे में मंगलवार को सजा टालने की जानकारी मिलना सही मायने में राहत वाली खबर है।

राज कनौजिया, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को कटक में रेवेनशॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करते हुए कहा कि भारत महिला सशक्तीकरण से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है। इस वर्ष विश्वविद्यालय के 27 विभागों में से 21 में छात्राओं ने अपने पुरुष सहपाठियों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो इसका प्रमाण है।

दैनिक जागरण
परिणाम सदैव प्रयास के अनुपात में ही प्राप्त होता है

अभिव्यक्ति की आजादी

सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक एवं भड़काऊ कार्टून बनाने वाले मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट को राहत देते हुए जो चेतावनी दी, वह महत्वपूर्ण है। यह कार्टून केवल इसीलिए आपत्तिजनक नहीं था कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चित्रित किया गया था, बल्कि इसलिए भी था, क्योंकि वह धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने वाला था। संभवतः इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्टूनिस्ट के खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। इस कार्टूनिस्ट के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और दो समुदायों के बीच वैर पैदा करने का मामला दर्ज किया गया था। कार्टूनिस्ट को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। पिछले दिनों इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है और इस अधिकार के नाम पर आनलाइन मीडिया में कुछ भी पोस्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी दो टिप्पणी हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति के मामले को सुनवाई करते हुए भी की थी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं हो सकती। इस अधिकार का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया कहे जाने वाले आनलाइन प्लेटफार्म पर लोग कुछ भी आपत्तिजनक, भड़काऊ कह देते हैं और फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसका बचाव भी करते हैं। कई बार खुद को सेक्युलर एवं लिबरल कहलाने वाले लोग, कथित बुद्धिजीवी एवं नेता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मनमानी व्याख्या करते हैं। ऐसे ही लोग प्राय: ढोंग भी करते हैं। वह किसी से छिपा नहीं कि जब तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बेहद भद्दी और भड़काऊ टिप्पणी की थी तो सेक्युलर नेताओं और बुद्धिजीवियों को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वे उदयनिधि की आलोचना करने को तैयार नहीं थे। ऐसे दोहरे मापदंड वाले लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ अप्रिय कहने का अधिकार देती है, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे को तय करना आसान काम नहीं, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न होने पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना होगा। उचित होगा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश तय करे। यह भी आवश्यक है कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का संचालन करने वाली कंपनियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। कई बार ये कंपनियां भी दोहरे मानदंडों का परिचय देते हुए दिखती हैं।

चिंताजनक कार्यशैली

उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं को सही रूप में क्रियान्वित करने और पात्र व्यक्तियों को उनका लाभ दिलाने के मामले में तंत्र की लापरवाही चिंताजनक है। प्रदेश में जरूरतमंदों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन तंत्र इन्हें अपेक्षित गंभीरता से नहीं ले रहा है। सरकार की सख्ती के बाद भी इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताजा उदाहरण हरिद्वार जिले में आंगनबाड़ी केंद्र में मिले एक्सपायरी दूध और दवा का है।

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिल्क पाउडर और आयरन सीरप दिया जा रहा है। इस केंद्र पर दूध और दवा दोनों ही एक्सपायरी मिले। बड़ा प्रश्न यह कि जिन बच्चों के लिए दवा और दूध आया था, वह बंटा क्यों नहीं। इस पर जिम्मेदारों के होंठ सिले हुए हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून में सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति की जाने वाली दवाएं बाजार में दुकानों पर मिलीं। यानी जरूरतमंदों को मुफ्त में दी जाने वाली दवा कैमिस्ट शाप पर बिक रही थी। यह तो चंद उदाहरण हैं, कल्याणकारी अन्य योजनाओं में भी कुछ इसी तरह की स्थिति सामने आती है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि निगरानी तंत्र कमजोर होने की वजह से इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है या फिर अन्य कोई कारण है? इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। सरकार को जिम्मेदारों के खिलाफ कदम उठाकर सख्त संदेश देना चाहिए, ताकि इस तरह के हालात न बनने पाएं और पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल सके। यह तभी संभव है जब जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, तभी योजना ठीक से उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगी

भारतीयों को सशंकित कर रहा है चीन

हर्ष वी. पंत

भारत-चीन ने तनाव घटाने के कुछ प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि लोगों को रिश्तों में सुधार की उम्मीद कम है

शिवम शेखावत

अवधेश राजपूत

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की दोबारा कमान संभालने के बाद से वैश्विक ढांचे में अस्थिरता-अनिश्चितता का भाव निरंतर बढ़ने पर है। नीति निर्माण से जुड़े उनके मनमाने एवं एकतरफा रवैये का असर अमेरिका के दोस्तों के साथ ही उसके प्रतिद्वंद्वियों पर भी समान रूप से पड़ रहा है। यूक्रेन-रूस युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी टकराव, दक्षिण एशिया में आतंक का बढ़ता प्रकोप और चीन की आक्रामकता में हो रही वृद्धि जैसे पहलू भी अंतरराष्ट्रीय मामलों की दशा-दिशा पर अपना असर डाल रहे हैं। समय के साथ वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका भी बढ़ी है, तो वैश्विक ढांचे की नया आकार देने में भारतीयों की आकांक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन-ओआएफ ने एक सर्वे के जरिये इन आकांक्षाओं को थाह लेने का प्रयास किया है। इसमें कुछ दिलचस्प संकेत उभरते हैं। इस बार ओआएफ का विदेश नीति संबंधी सर्वे चीन की चुनौतियों के संदर्भ में युवा भारत के मन की थाह लेने पर केंद्रित है। आखिर देश का युवा विदेश नीति संबंधी निर्णयों एवं चुनौतियों को किस रूप में देखता है। इस सर्वे में देश के 19 शहरों में 11 भाषाओं के जरिये 18 से 35 वर्ष की आयु के पांच हजार से अधिक युवाओं से संवाद किया गया। चूंकि यह सर्वे पिछले वर्ष 22 जुलाई से 26 सितंबर के बीच हुआ, इसलिए इसमें ट्रंप के दोबारा अमेरिका की कमान संभालने के प्रभाव से लेकर पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में आपरेशन सिंदूर जैसे अभियान एवं भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव पर नजरिया सामने नहीं आ सका, लेकिन इसकी व्यापक झलक जरूर मिलती है कि बर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और उनके प्रति भारत के दृष्टिकोण को लेकर हमारा युवा वर्ग क्या सोचता-समझता है। सबसे प्रमुख पहलू तो यह उभरा कि भारत की विदेश नीति के प्रति समर्थन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और करीब 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं का रवैया इसे लेकर सकारात्मक है। बर्तमान परिस्थितियों से निपटने में भारत की सफलता को लेकर यह बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। चीन को लेकर भावनाओं का आकलन करना था तो उत्तरदाताओं के बीच भी इस मुद्दे की महत्ता बखूबी महसूस हुई। 89 प्रतिशत ने माना कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 86 प्रतिशत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दूसरी, जबकि 85 प्रतिशत ने पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को तीसरी सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में चिह्नित किया।

भले ही भारत-चीन ने तनाव घटाने की दिशा में कुछ प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि रिश्तों में सुधार को लेकर उम्मीद बहुत कम है। एक साल पहले चीन को लेकर भरोसे की जो कमी थी, वह और ज्यादा बढ़ गई। गलवन के हिंसक संघर्ष के पांच साल बाद भी चीन के प्रति दुराव कम नहीं हुआ है। अधिकांश युवा उसके उभार को लेकर चिंतित होने के साथ ही उसे एक सैन्य खतरे के रूप में भी देखते हैं। इनमें 81 प्रतिशत तिब्बत पर अवैध कब्जे को रिश्तों में बड़ा अवरोध मानते हैं। करीब 84 प्रतिशत युवा आर्थिक साझेदारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जो चीन से आयात घटाने के हिमायती हैं। वहीं, 79 प्रतिशत युवाओं का मानना है कि चीन की बीआरआइ परियोजना से दूर रहने का फैसला हमारे लिए हितकारी है।

भारत के लोगों और खासकर युवाओं के बीच रणनीतिक परिदृश्य पर हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। इसके बाद दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बारी आती है। इसमें सामुद्रिक मोर्चे पर चीन के बढ़ते दखल की चिंता झलकती है। भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति को भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। सर्वाधिक 72 प्रतिशत युवा नेपाल को सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में देखते हैं। इसके बाद भूटान एवं श्रीलंका का स्थान आता है। बांग्लादेश को लेकर भरोसा 2022 से लगातार घटने पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रति सर्वाधिक संशय बना हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर नजरिया पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुधरा है, जबकि पहलगाम घटना और आपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान को लेकर भावनाएं यकीनन और तल्ख हुई होंगी।

चाहे क्वाड जैसे संगठन में सहयोगियों से रिश्तों को प्रगाढ़ बनाना हो या रूस जैसे सदाबहार दोस्त को साधे रखना, रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर भारत के प्रयासों को युवा वर्ग की सराहना मिल रही है। सबसे अधिक सकारात्मक रवैया अमेरिका को लेकर दिखा, जिसमें 86 प्रतिशत युवा उसके साथ रिश्तों को संतोषजनक मानते हुए अगले दस वर्षों में उसे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। चूंकि ये भावनाएं पिछले कुछ समय में परवान चढ़ रहे रिश्तों के आधार पर नपनी हैं, इसलिए ट्रंप के रवैये को देखते हुए आगामी दिनों में कुछ अलग तस्वीर दिख सकती है। हालांकि 54 प्रतिशत युवा अभी भी मानते हैं कि चीनी चुनौती की काट के लिए भारत को अमेरिका के साथ अपनी जुगलबंदी और बेहतर करनी चाहिए। जहां क्वाड को लेकर उत्साह है, वहीं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ को लेकर संदेह है, क्योंकि इसमें चीन का दबदबा है। अधिकांश युवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है तो एक बड़ा वर्ग जी-7 जैसे समूह में भी भारत को नियमित सदस्य के रूप में देखना चाहता है, ताकि इसमें शामिल अन्य विकसित देशों के साथ सक्रियता बढ़ाकर अपने हितों को पोषित किया जा सके। सर्वेक्षण के साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों में सजग भारतीयों की रुचि यह दर्शाती है कि भारत के समक्ष चुनौतियों को लेकर उनमें और खासकर युवाओं में गहरी समझ है। आने वाले समय में उनके दृष्टिकोण में कुछ बदलाव भी प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आकार ले रही हैं, उसमें उनके मनोभावों को और मजबूती ही मिलेगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि चीन-पाकिस्तान की खतरनाक होती जोड़ी को लेकर वे पहले से ही सतर्क हैं। यह भी ध्यान रहे कि चीन-अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता पहले से ही भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने का केंपास बनी हुई है।

(पंत आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष और शेखावत जूनियर फेलो हैं)
response@jagran.com

निराश-हताश करती नौकरशाही

राजीव सचान

सरकारी कामकाज में सुधार से इंकार नहीं, पर कुछ क्षेत्रों में स्थिति जस की तस और चिंतित करने वाली है

नौकरशाही के भ्रष्टाचार का नतीजा। प्रेट्र

नौकरशाही के कार्य-व्यवहार को जानने के लिए चंद दिनों की कुछ चर्चित घटनाओं पर चर्चा करते हैं। कुछ दिनों पहले गुजरात में दो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक पुल गिर गया। महिसागर नदी पर बने गंभीरा पुल के दो हिस्सों में टूटने से उस पर चल रहे कई वाहन नदी में गिर गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। इस हादसे के बाद शोक संवेदना, जांच, कार्रवाई के वैसे ही स्वर सुनाई दिए, जैसे सुनाई देते रहते हैं। पुल गिरने के लिए कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इन निलंबित अधिकारियों को देर-सबेर बहाल कर दिया जाए तो बड़ी बात नहीं। यह पुल 40 साल पुराना था, लेकिन इतना पुराना पुल बहुत पुराना नहीं होता। आमतौर पर पुल सौ साल तक चल जाते हैं। देश में अंग्रेजों के बने कई पुल कायम हैं, लेकिन भारतीयों के बनाए पुल बनने के पहले ही गिर जाते हैं।

गुजरात में पुल गिरने की घटना की विपक्षी दलों ने खूब निंदा-आलोचना की। उन्हें भाजपा, गुजरात सरकार और मोदी सरकार की आलोचना करने का अवसर मिला था। उन्होंने इसे अच्छे से भुनाया। ऐसा अवसर भाजपा को मिलता है तो वह भी उसे भुनाती। राजनीति में ऐसा होता ही है, लेकिन यदि नेताओं, नौकरशाहों, ठेकेदारों के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी तो आगे भी पुल गिरते रहेंगे। सड़कें भी टूटती-धंसती और जल भराव का शिकार होती रहेंगी। ऐसा मुंबई, बेंगलुरु और यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी होगा। होगा क्या, हो रहा है। थोड़ी सी बरसात में बड़े महानगरों की सड़कें भी जलमग्न हो जाती हैं। अब तो लोगों ने यह मान लिया है कि बरसात में सड़कों और यहां तक कि हाईवे में भी अतिरिक्त ट्रैफिक जाम का सामना करना उनकी नियति है। देश में न तो सड़कों और पुलों का घटिया निर्माण रुक रहा है और न ही सड़क दुर्घटनाओं में मरने एवं घायल होने वालों की संख्या में कमी आ रही है। इन दिनों जहां भी सामान्य से तनिक अधिक बारिश हो जा रही है, वहां वह मुसीबत बन जा रही है। पहाड़ों में तो ऐसा खास तौर पर हो रहा है। जब कोई बड़ी घटना घटने के साथ जनहानि हो जाती है तो मुआवजे की भी घोषणा कर दी जाती है, लेकिन सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार पर रोक के प्रभावी उपाय देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे उपाय न तो केंद्र सरकार की निर्माण परियोजनाओं में देखने को मिल रहे हैं और न ही राज्य सरकारों की परियोजनाओं में। जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार आज के भारत की एक कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार केवल कुछ राज्य सरकारों अथवा केंद्र सरकार तक सीमित है। यह एक राष्ट्रीय सरकारी बीमारी है। यह सही है कि देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। बुनियादी ढांचे का सरकारी निर्माण होने के साथ निजी क्षेत्र में भी निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार में सरकार और निजी क्षेत्र में कोई भेद नहीं दिखता। यदि नया बना कुछ टिकेगा ही नहीं, तो नया भारत कैसे बनेगा? देश में तेजी से बहुत कुछ बन रहा है तो वह गिर भी क्यों रहा है? इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार केवल निर्माण कार्यों में ही है।

भ्रष्टाचार शासन-प्रशासन के अन्य अंगों में भी है और कहीं-कहीं तो इस हद तक है कि वह देश के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में मिला। यहां एक कथित फकीर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर हिंदू युवतियों को छल-बल से इस्लाम में ला रहा था। इस पीर-फकीर को विदेश से भी पैसा मिल रहा था। अपने देश में भारत के इस्लामीकरण की सनक से ग्रस्त और भी जलालुद्दीन होंगे और वे भी विदेश से पैसा पाते होंगे, लेकिन बलरामपुर के मामले में सबसे घातक बात यह है कि छांगुर को कुछ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त था। यह संरक्षण केवल गुनाह ही नहीं, एक तरह से देश से गद्दारी भी है। इस मामले की जांच हो रही है और शायद उसकी तह तक भी पहुंचा जाए और सभी दोषी लोगों को समय रहते सजा भी मिल जाए। उत्तर प्रदेश के इस मामले में ऐसा होने की उम्मीद भी है, लेकिन अन्य राज्यों और विशेष रूप से सेक्युलर दलों की ओर से शासित राज्यों में तो ऐसा कुछ होने के बारे में सोचना भी कठिन है। यह हैरानी है कि अभी तक कथित सेक्युलर नेताओं और लिबरल लोगों ने यह नहीं कहा कि बेचारे छांगुर को बिना बात परेशान किया जा रहा है।

यदि कोई यह कहे कि केंद्र अथवा राज्यों के स्तर पर नौकरशाही के कामकाज में कहीं कोई सुधार नहीं हुआ और सब कुछ पहले की तरह है तो यह भी सही नहीं होगा। समय के साथ राज्यों से लेकर केंद्र की नौकरशाही के स्तर पर काफी कुछ उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधार हुए हैं और लोगों को उनसे राहत भी मिली है, लेकिन यह समझा जाए तो बेहतर कि अभी नौकरशाही में बहुत सुधार की आवश्यकता है। नौकरशाही में बगैर जरूरी सुधार लाए देश को अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिन नेताओं और नौकरशाहों ने सरकारी तंत्र में सुधार लाने में योगदान दिया है और दे रहे हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जिन्होंने योगदान नहीं दिया, उनकी पहचान भी होनी चाहिए।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सच्चरित्र का महत्व

समाज में पवित्र, निर्मल और सदाचार की आधारशिला पर ही सफल जीवन भवन का निर्माण संभव हो सकता है। उत्तम चरित्रवान लोग ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक उत्कृष्ट चरित्र वाली विभूतियों के उदाहरण हैं, जिनके कार्य-व्यवहार को देखकर-सुनकर सामान्य जन भी वैसा ही बनने और करने का सफल प्रयास करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र जैसा सत्यनिष्ठ, महाराज शिबि जैसे शरणागत रक्षक, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसा प्रणवीर, नेताजी सुभाष जैसा देशभक्त, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकार, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा विनम्र विद्वान, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना और सती सावित्री जैसी पतिव्रता आदि के पावन चरित्र से हमारा देश धन्य हुआ है। यथार्थ ही कहा गया है कि धन नष्ट हुआ तो कुछ न बिगड़ा, स्वास्थ्य गया तो कुछ बिगड़ा और यदि चरित्र गिरा तो सब बिगड़ा। व्यक्ति में चरित्र का निर्माण परिवार, समाज और विद्यालय आदि से निर्मित होता है। सृष्टि के उत्थावान से ही भारतीय समाज में चरित्र के महत्व का गुणगान किया गया है। व्यक्ति के चरित्र में दोष आने का सबसे बड़ा कारण कुसंग है। सौभाग्य, समाज में बढ़ते दुराचार का मुख्य कारण भावनात्मक सहयोग का अभाव है। भावना का मूल है-पारदर्शी निर्मल चरित्र। पाश्चात्य जगत की नकल करके हम अपनी समृद्धत सनातन संस्कृति से स्वयं ही दूर हो रहे हैं। संचार के आधुनिक साधनों ने भी चरित्र को कलुषित करने का काम किया है।

सच्चरित्र के अभाव में मानवता रुदन कर रही है। हम सभी अपनी संस्कृति-सभ्यता के अनुरूप अपने चरित्र को बनाएं, जिससे सर्वत्र पवित्रता, निर्मलता और पारस्परिक सद्भाव आलोकित हो। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें सच्चरित्र के महत्व को समझाना चाहिए।

आचार्य नारायण दास

सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की चुनौती

सुधीर कुमार

सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अब केवल पांच वर्ष शेष हैं, इसलिए हमें तेजी से काम करने की जरूरत है

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की प्रगति पर वार्षिक विकास रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अब केवल पांच वर्ष शेष हैं, इसलिए हमें तेजी से काम करने की जरूरत है, तभी निर्धारित लक्ष्यों के करीब पहुंचा जा सकता है। दरअसल 10वें वार्षिक सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2025 से प्रतीत होता है कि मौजूदा गति से 2030 तक सतत विकास से जुड़े सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल कर पाना संभव नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत की थी, जिसके तहत 2030 तक मूल रूप से 17 और कुल 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इनमें गरीबी और भुखमरी को शून्य करना, स्वास्थ्य सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच, जलवायु कार्रवाई, शांति और न्याय जैसे लक्ष्य शामिल हैं। हालांकि 10 वर्ष का लंबा समय बीतने के बाद भी इस लक्ष्य को हासिल करने में दुनिया बहुत पीछे रह गई है। ऐसे में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (2000-2015) की तरह सतत विकास लक्ष्य के अधूरे रह जाने की आशंका अब गहराने लगी है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) का उद्देश्य 2015 तक मूलतः आठ विकास लक्ष्यों को हासिल करना था, परंतु लक्ष्य से दूर रहने के कारण ही संयुक्त राष्ट्र ने आगामी 15 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा तैयार की थी। अद्यतन वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, लाखों लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, अपर्याप्त आवास और बुनियादी सेवाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। हरेक 10 में से एक व्यक्ति अत्यधिक निर्धनता में रहने के लिए विवश है, जबकि प्रत्येक 11 में से एक व्यक्ति को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में देशों की प्रगति भी चिंतित करती है। वर्तमान गति से 2030 तक पांच में से केवल एक देश ही अपनी राष्ट्रीय गरीबी दर को आधा करने में कामयाब हो पाएगा। आज भी दुनियाभर में दो अरब से ज्यादा लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ये लोग सतत विकास लक्ष्य की पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाए हैं। ऐसे में अन्य 16 लक्ष्यों के करीब तक उन्हें पहुंचाने में लंबा वक्त लग सकता है। दुनिया में आज भी 1.08 करोड़ लोग क्षय, ढाई अरब लोग मलेरिया के शिकार हैं और लगभग 27.2 करोड़ बच्चे और युवा स्कूल से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस और सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सतत विकास समस्त मानवता के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित ऐसी वैचारिकी है, जो न सिर्फ वर्तमान, बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी बल देती है। इसमें सभी देशों और सभी नागरिकों की समान भागीदारी आवश्यक है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

समग्रता में विचार की आवश्यकता

'मताधिकार और नागरिकता का पेचीदा सवाल' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अरविंद जैन द्वारा नागरिकता प्रमाण और मताधिकार के संबंध में प्रस्तुत चिंताएं विचारणीय हैं, परंतु कुछ मूलभूत संवैधानिक और सामाजिक पक्षों की या तो उपेक्षा की गई या उन्हें एक सीमित दृष्टिकोण से रखा गया। लोकतंत्र की व्यापकता केवल द्विपक्ष प्रविधानों में नहीं, बल्कि उसके सामाजिक कार्यान्वयन में भी निहित होती है। अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार उस प्रत्येक भारतीय को है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो, परंतु जब इस अधिकार को नागरिकता के दस्तावेजों से सशर्त जोड़ा जाता है, तब यह संविधान की भावना और समावेशी लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाता है। सीमावर्ती राज्यों और हाशिए पर मौजूद समुदायों के संदर्भ में यह स्थिति और जटिल हो जाती है, जहां लोग पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन औपचारिक कागजी प्रमाणों के अभाव में उनकी भारतीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता सिद्ध करने के लिए बाध्य करना 'निर्दोषता की धारणा' के न्यायिक सिद्धांत के भी प्रतिकूल है, जिसमें यह दायित्व राज्य पर होता है कि वह संदेह को प्रमाण में बदले, न कि नागरिक पर। जब राष्ट्र किसी दस्तावेज के आधार पर ही नागरिकता और अधिकार तय करने लगे, तो वह राष्ट्र गणराज्य नहीं, बल्कि फाइलों का गणतंत्र बन जाता है। यह विषय केवल कानून की व्याख्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र की चेतना से जुड़ा प्रश्न है-क्या हम

प्रतिक्रिया

ऐसे नागरिकों को केवल दस्तावेजों के अभाव में अपने लोकतांत्रिक तंत्र से बाहर करेंगे? जहां अस्तित्व को प्रमाणित करना पड़े, वहां अधिकार स्वतः संदिग्ध हो जाते हैं। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर समग्रता में विचार किया जाए।

awanishg30@gmail.com

कर चोरी बड़ी समस्या

संपादकीय 'आयकर विभाग की छापेमारी' में कर चोरी, टैक्स संबंधी नियमों में सुधार और भ्रष्टाचार में नगदी की रोक का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया है। भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। इस हिसाब से लगभग 6 प्रतिशत लोग ही आयकर रिटर्न भरते हैं, जबकि केवल 1-1.5 प्रतिशत लोग ही वास्तव में इनकम टैक्स भरते हैं। आयकर विभाग के अनुसार कर चोरी भारत में एक बड़ी समस्या है। अनुमानतः 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने योग्य आय होने के बावजूद टैक्स नहीं भरते। 2023-24 में आयकर विभाग ने लगभग 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी पकड़ी। आम तौर पर कर चोरी राजनीतिक चंदे (चुनावी बांड), नकद लेन-देन, संपत्ति खरीद-बिक्री (अघोषित आय), व्यवसाय में फर्जी खर्च दिखाने और फर्जी कंपनियों के माध्यम से होती है। यह आश्चर्यजनक है कि तमाम कानून और तामझाम होने के बावजूद भ्रष्टाचार पनप रहा है, नेताओं-नौकरशाहों के यहां से छापेमारी में करोड़ों-अरबों का काला धन बरामद हो रहा है। भ्रष्ट लोग कुछ न कुछ जुगाड़ करके कानून का तोड़ निकाल लेते हैं और इनकम टैक्स, जीएसटी से बच जाते हैं, परिणामतः जो पैसा भारत के विकास में उपयोग होना चाहिए, वह आता ही नहीं और भ्रष्ट व्यक्ति खुद का विकास कर लेते हैं। इसे कानून का लचीलापन और आयकर विभाग की लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक भ्रष्ट व्यक्ति करोड़ों रुपये जमा नहीं कर लेता, वे कुछ नहीं करते। जबकि जरूरत इस बात की है कि जिन खातों को आधार बनाकर काला धन जमा हो रहा है उन पर अंकुश लगाया जाए। सत्तासीन शासन-प्रशासन के सहयोग के बिना भ्रष्टाचार फल-फूल नहीं सकता। अतः यदि आज भी भ्रष्टाचार एक ज्वलंत समस्या और चुनौती बनकर उभर रहा है तो इसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य-केंद्र सरकार जिम्मेदार हैं। स्वच्छता केवल बाहर की सफाई से नहीं आती, बल्कि मन, विचार, आचरण और चरित्र भी शुद्ध, पवित्र, उज्ज्वल होना चाहिए।

मोहित सोनी, कुक्षी, मध्य प्रदेश

उस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹ 2 अतिरिक्त।
****

ब्र. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, वेनेट यूनिवर्सिटी

आजकल

अंतरिक्ष में भारत की नई उपलब्धि

इसरो गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के काम को अपने बूते साकार करना चाहता है। अपनी कोशिशों से अगले 15 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना भी चाहता है। इन सभी के लिए हर तरह की सूक्ष्म तैयारियों और परीक्षणों की जरूरत है। एक्सिओम-4 मिशन से शुभांशु शुक्ला का आइएसएस तक जाना और वहां से सफल वापसी करना इन भावी मिशनों की ठोस जमीन तैयार करेगा

भारतीय अंतरिक्षयात्री शुभांशु शुक्ला के अनुभव का इसरो के गगनयान मिशन को मिलेगा लाभ। फाइल

अंतरिक्ष एक जटिल दुनिया है। सदियों से उसे समझने का सिलसिला जारी है, पर अंतरिक्ष का विस्तार ही इतना है कि उसके अनगिनत रहस्यों और उसकी सीमाओं का पता ही नहीं चलता। अंतरिक्ष को जानने की एक कोशिश साढ़े छह दशक पहले तब हुई थी, जब सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल, 1961 को वोस्तोक-1 नामक के यान से अंतरिक्ष में कदम रखा था और पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की थी। दूसरी ऐसी उपलब्धि 20 जुलाई, 1969 की है, जब नासा (अमेरिका) के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। तब कहा गया कि मनुष्य के लिए यह एक छोटा कदम है, पर मानवता के लिए बड़ी छलांग है। ऐसी कुछ उपलब्धियां भारत के खाते में भी दर्ज हैं, लेकिन इनमें सबसे ताजा घटनाक्रम भारतीय अंतरिक्षयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष गमन और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) पर 18 दिन रहकर कई प्रयोग करने के बारे में हैं। शुभांशु शुक्ला के प्रयोगों का एक बड़ा उद्देश्य इसरो के भावी गगनयान और अन्य अंतरिक्ष अभियानों को सफल बनाना है। इन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया कि अंतरिक्ष का वातावरण पौधों और सूक्ष्म जीवों पर कैसे असर डालता है। साथ ही अंतरिक्ष का शून्य अथवा न्यून गुरुत्वाकर्षण (माइक्रोग्रैविटी) का क्या प्रभाव होता है।

प्रयोगों-परीक्षणों का मकसद: भारत के संबंध में बात करें तो शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में गए वैज्ञानिक समूह ने जिन प्रयोगों को अंजाम दिया, वे भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं और पृथ्वी पर जिंदगी आसान करने के उपायों-समाधानों की राह खोल सकते हैं। जैसे, एक प्रयोग का उद्देश्य यह जानना रहा कि अंतरिक्ष की माइक्रोग्रैविटी से उस सूक्ष्म शैवाल (माइक्रोएल्गे) पर क्या असर होता है, जिसे खाने योग्य माना जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य भविष्य की सुदूर अंतरिक्षयात्राओं में अंतरिक्ष में ही भोजन तैयार करना और आक्सीजन के साथ जैव ईंधन उपलब्ध कराना है। सूक्ष्म शैवाल पर प्रयोग करने के पीछे इसकी लचीली संरचना है, जिसकी मदद से पृथ्वी के पार जीवन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। उनका दूसरा अहम प्रयोग दाल एवं मसाले के बिकल्पों (मूंग और मेथी) के बीजों को अंतरिक्ष में उगाने से जुड़ा था। इससे पता चलेगा कि अंतरिक्षयात्रियों के लिए पोषण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने एक पेट्री डिश में 'मूंग' और 'मेथी' के बीजों को अंकुरित करने के लिए आइएसएस के भंडारण फ्रीजर में रख दिया। अंकुरण के दौरान शुभांशु ने सेल्फी लेते हुए लिखा कि इससे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। यह अध्ययन इस बात पर आधारित था कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अंकुरण और पौधों के प्रारंभिक विकास को कैसे प्रभावित करता है।

शुभांशु द्वारा किया गया तीसरा प्रयोग इस अध्ययन पर केंद्रित था कि जीवन का कोई रूप अंतरिक्ष में कैसे जीवित रहता है, कैसे प्रजनन करता है और इसके आरएनए में क्या परिवर्तन आते हैं। चौथा प्रयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर किया। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि कम गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियों को ठीक रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। पांचवें प्रयोग काफी दिलचस्पी वाला रहा। इसमें उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि अंतरिक्ष की माइक्रोग्रैविटी वाली स्थितियों में मनुष्य इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले के साथ कैसे संवाद करते हैं। उनका छठा प्रयोग साइनोबैक्टीरिया की अंतरिक्ष में बढ़वार से संबंधित था। शुभांशु और उनके साथ मौजूद विज्ञानियों के दल ने इस परीक्षण के जरिए यह जानने की कोशिश की है कि यूरिया और नाइट्रेट की मदद से साइनोबैक्टीरिया अंतरिक्ष में कैसे बढ़ते हैं। सातवां परीक्षण खट्टा फसलों के बीजों पर केंद्रित था। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि माइक्रोग्रैविटी में फसलों के बीजों की बढ़ोतरी और पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब प्रयोगों से मिले आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन देश के अलग-अलग इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय करेंगे।

गगनयान और लंबी अवधि के मिशन: शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में आइएसएस पर रहते हुए जो प्रयोग किए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे मिली जानकारी से भारत अंतरिक्ष में मानव जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर पाएगा। वापस आने पर अब उनकी योजना अपने अनुभवों को भारत के गगनयान अभियान के लिए चयनित होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा करने की है। इन प्रयोगों की महत्ता रेखांकित करते हुए भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि शुभांशु शुक्ला के प्रयोग लंबी अवधि के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अंतरिक्ष में किए गए इन प्रयोगों से मिले आंकड़ों की मदद से माइक्रोग्रैविटी वाले माहौल के लिए डिजाइन और विकसित की गई स्वदेशी बायोटेक किट का उपयोग किया जाएगा। यह प्रयास अंतरिक्ष जीव विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र में अहम रोल निभाएगा।

भारत के संदर्भ में इन प्रयोगों-परीक्षणों से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमारा देश गगनयान के जरिए 10 हजार करोड़ रुपये के खर्च वाले उस मानव मिशन योजना पर तेजी से बढ़ेगा, जिससे पहली बार अपने बल पर किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने और सात दिनों तक वहां बनाए रखने के सपने को साकार किया जा सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो गगनयान मिशन नामक जिस स्वदेशी मानव मिशन (वर्ष 2027 तक) और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना (वर्ष 2035 तक) के काम को अपने बूते साकार करना चाहता है, उसमें असीम तैयारियों की जरूरत है। योजना तो इससे भी आगे की है, जब भारत अपनी कोशिशों से अगले 15 वर्षों के भीतर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना चाहता है। इन सभी के लिए हर तरह की सूक्ष्म तैयारियों और परीक्षणों की जरूरत है। कह सकते हैं कि एक्सिओम-4 मिशन से शुभांशु का पहले भारतीय के रूप में आइएसएस तक जाना और वहां से सफल वापसी करना इन भावी मिशनों की ठोस जमीन तैयार करेगा। चूंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु एक्सिओम-4 के मिशन पायलट के रूप में गए थे, इसलिए उनकी भूमिका इस मिशन की लांचिंग, अंतरिक्ष में पहुंचने पर यान की आइएसएस से डाकिंग (यान को आइएसएस से जोड़ना) और पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित प्रवेश और धरती पर कामयाब लैंडिंग तक में रही है। मिशन के दौरान पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल टीमों से संपर्क और संवाद का जिम्मा भी शुभांशु का था। स्पष्ट है कि इन चीजों का अनुभव भारत के भावी अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़े काम का साबित हो सकता है।

इसरो के मानव मिशन के लिए फिलहाल तय की गई शर्तों के मुताबिक इसके लिए भारतीय एस्ट्रोनाट को कम से कम सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहना होगा। इसके लिए बनाए जाने वाले अंतरिक्ष यान- गगनयान में उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्री का चयन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा और उन्हें स्पेस फ्लाइट की ट्रेनिंग विदेश में दी जाएगी। इस अभियान की कुछ अहम शर्तें और हैं। जैसे, इस योजना को सिरे चढ़ाने से पहले मिशन में इस्तेमाल होने वाले राकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल मार्क-3 (जीएसएलवी-एमके-3) से कम से कम दो मानवरहित उड़ानें कराना अनिवार्य है। मार्क-3 पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण होगा। इसरो के मुताबिक वह इसकी कुछ टेक्नोलाजी विकसित कर चुका है। जैसे इसरो ने पहले ही क्रू माड्यूल और स्केप सिस्टम का परीक्षण कर लिया है। शेष तैयारियां अगले कुछ चरणों में पूरी हो जाएंगी। इसरो ने मंगलयान के अलावा अपने राकेटों में भारी विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके जो प्रतिष्ठा हासिल की है, उसे देखते हुए गगनयान से किसी भारतीय को स्पेस में भेजने का उसका सपना नामुमकिन नहीं लगता है।

अंतरिक्ष में मानव मिशन की जरूरत क्यों

इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में दुनिया में स्पेस टूरिज्म और अंतरिक्ष के संसाधनों के दोहन को लेकर हो रही पहलकदमियों पर नजर डालना जरूरी है। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी- स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क, वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपनी कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' के अलावा जी-फोर्स वन, ब्लून, रूसी कंपनी ल्यूशिन-76 एमढीके, स्पेस एडवेंचर, प्रोजेक्ट एम-55एसएस आदि कई निजी कंपनियों के मालिक इस कोशिश में हैं कि स्पेस टूरिज्म के सपने को साकार करते हुए लोगों को अंतरिक्ष भ्रमण कराया जा सके और उसके बल पर अकूत कमाई का रास्ता खोला जा सके। इसी तरह एक मामला अंतरिक्ष की खोज और उसके (संसाधनों के) दोहन का है। अमेरिका और रूस के बाद चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मानव मिशनों को स्पेस में भेज चुका है और आगे चलकर चंद्रमा के खनिजों के दोहन की बात भी उसके जेहन में है। साथ ही, अपने राकेटों से विदेशी सैटेलाइटों के प्रक्षेपण के बाजार में भी वह सेंध लगाना चाहता है, ताकि इस मामले में भारत के इसरो की बढ़त और कमाई को कम किया जा सके। स्पेस मार्केट में दबदबे के लिए जरूरी है कि कोई देश चांद या अंतरिक्ष के मानव मिशनों से अपनी योग्यता एवं क्षमता लगातार साबित करे। भारत के लिए यह राहत की बात है कि पिछले कुछ अरसे में इसरो ने अपनी तमाम कामयाबियों से अपनी क्षमता दुनिया के सामने रखी है। इससे पूरे स्पेस मार्केट में खलबली मची हुई है। अगर भारत इससे आगे बढ़ते हुए स्पेस में मानव मिशन की बात कर रहा है, तो उसका यह नजरिया देश को अंतरिक्ष में लंबे समय तक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का है, ताकि देश की भावी पीढ़ी को ज्ञान से लेकर रोजगार तक में उसका फायदा मिल सके।

खरी-खरी

आभासी दुनिया में जीवन

अंशुमाली रस्तोगी

अक्सर ही लोगों को कहते सुनता हूं कि आज का समय बड़ा आसान है। झट से चीजें यहां से वहां चली जाती हैं। आपस में बातें करना कितना सरल हो गया है। कहीं आने-जाने की जरूरत ही नहीं, बस जहां हैं, वहीं से बैठे-बैठे कुछ भी खरीद लो या बेच दो। कहना न होगा कि इंटरनेट के प्रभाव ने जीवन को 'आरामतलबी' वाला बना दिया है। यही आरामतलबी अब हमारे लिए नासूर बनती जा रही है। पहले दो घड़ी बैठकर जीवन और संबंधों के बारे में सोच-विचार भी लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं है।

मुझे तो अपने आसपास बे-गढ़न लोग ही दिखाई देते हैं। क्या करें, सबकी गर्दनें तो अपने-अपने मोबाइल फोन में घुसी रहती हैं। जो भी बात कहनी-सुननी होती हैं, टच-स्क्रीन पर अंगुलियां ही कहती-सुनती हैं। हालांकि इंटीगेर्ट शोर तो बहुत है, पर यह इंसानों से ज्यादा गाड़ियों का है। पुरानी पीढ़ी के किस्से भी क्या खूब किस्से हुआ करते थे, सीधे उनके जीवन से निकले। जहां जीवन को जाकर खोजना नहीं पड़ता था, वह सक्षात आपके सामने खड़ा रहता था। तरह-तरह के अनुभव देकर जाता था। साहित्य ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। कभी-कभी सोच में पड़ जाता हूं कि हमारी पीढ़ी के पास आगे आने वाली पीढ़ी को देने के लिए क्या है।

जिन रिश्तों को कभी करीबी माना जाता था, उनमें दूरियां बढ़ गईं हैं। हम संबंधों-रिश्तों की परिभाषाएं फेसबुक पर गढ़ने लगे हैं। यहां वह आदमी खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है, जिसके फेसबुक पर हजारों की संख्या में मित्र होते हैं। जिसके लिखे को हजारों लोग लाइक करते एवं टिप्पणी देते हैं। जमीन से निरंतर कटते जा रहे हैं लोग। जब देखो तो हर शख्स किसी गफलत में डूबा-सा नजर आता है। बेचैन रहता है, पर जताता ऐसे है मानो दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही है।

अपनों से कटकर वर्चुअल संसार में जीवन का सुख और आराम खोजने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। उनके चेहरों पर जिस खुशी को आप देख रहे हैं, दरअसल वह खुशी नहीं, उनकी हार है। एक ऐसी हार जिसे वे कभी जीत नहीं सकते।

पोस्ट

लार्ड्स में ऐसा दुर्लभ मैच हुआ, जहां विजेता टीम तो जीतने की पात्र थी ही, लेकिन पराजित टीम भी हारने की हकदार नहीं थी। अंतिम दिन पहले सत्र के शुरुआती आधे घंटे में तीन विकेट गंवाने के बावजूद भारत के नियले क्रम का रवैया अनुकरणीय रहा।
अयाज मेमन@cricketwallah

किसी भी पक्ष के साथ सधि केवल विश्वास की पूंजी पर आगे बढ़ती है और आतंक के साथ तो विश्वास कभी उपज ही नहीं सकता। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करना प्रतिशोध नहीं, पाकिस्तान की करतूतों का ही परिणाम है।
सैयद अकबरुद्दीन@Akbaruddin India

मोटापे के खिलाफ कोई भी अभियान सुनियोजित तरीके से चलाया जाना चाहिए। इस कड़ी में अगर किसी तरह की वेतावनी लाने की कोई योजना है भी तो यह मैकडैनाल्ड और केएफसी के बाहर भी लिखी होनी चाहिए जो डीप फ्राई और अत्यधिक शुगर वाले उत्पाद बेचते हैं। केवल जलेबी और समोसे पर क्यों शिकंजा कसा जाए। क्या केवल इसलिए कि वे 'गरीबों के पकवान' हैं?
संकेत उपाध्याय@sanket

जागरण जनमत

कल का परिणाम

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी पोस्ट करने की आजादी होनी चाहिए?

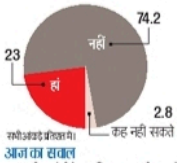

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट को राहत देकर सही किया?

परिणाम जागरण डाटनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ऐसा तब होता नहीं लार्ड्स टेस्ट का अंत,
जाडेजा सा खेलते यदि शुभमन व पंत।
यदि शुभमन व पंत धैर्य रखकर टिक पाते,
तो सिराज क्यों बैठ वहां पर अश्रु बहाते!
मिल जी ही कप्तानन खेली ऐसा-वैसा,
दिला सके जो जीत खेल दिखलाओ ऐसा!!
- ओमप्रकाश तिवारी

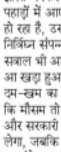

मनोज कुमार
राज्य संपादक, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

अब पंचायत के अखाड़े में पहाड़

हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता बेशक साफ हो गया हो, लेकिन इस बार जिस तरह मानसून झोली भरकर पानी बरसा रहा है और पहाड़ों में आए दिन कोई न कोई हादसा हो रहा है, उससे चुनाव प्रक्रिया के निर्विघ्न संपन्न होने को लेकर कई सवाल भी आ खड़े हुए हैं। साथ ही आ खड़ा हुआ है राजनीतिक दलों के दम-खम का जमीनी परीक्षण। मतलब कि मौसम तो राज्य निर्वाचन आयोग और सरकारी व्यवस्था का इम्तिहान लेगा, जबकि मतदाता दलों का वजन बताएंगे। यह ठीक है कि इन चुनावों में पार्टियों के सिंबल पर वोट नहीं पड़ते, लेकिन गांव की जमीन सियासी तापमान तो बता ही देती है। ऐसे भी उत्तराखंड मैदे तौर पर द्विदलीय ढर्रावे वाला प्रदेश है और यही कारण है कि गांव की प्रधानी से लेकर सांसदी तक हर कहीं आपको किसी न किसी रूप में भाजपा व कांग्रेस ही आमने-सामने खड़ी दिखाई देंगी।

हर बार की तरह इस बार भी बरसात पहाड़ों के लिए परेशानियां लेकर आई है। इन दिनों अतिवृष्टि, पहाड़ दरकने या भूस्खलन जैसी आपदा के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर आवागमन अवरुद्ध हुआ पड़ा है। रास्ते बंद होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय या मैदानी इलाकों से संपर्क कट गया है। विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मरीज अस्पताल। मुख्य मार्गों पर तो ऐसी बाधा तुरंत हटा दी जाती है, लेकिन गांवों तक व्यवस्था की यह तत्परता पहुंचनी अभी बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आगामी 24 और 28 जुलाई को होने जा रहे पंचायत चुनावों में पोलिंग पार्टियां गांवों के बूथ तक और मतदाता अपने घरों से बूथ तक सकुशल कैसे पहुंचेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकारी मशीनरी सब कुछ सकुशल संपन्न कराने के दावे भले कर रहे हों, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। विरल आबादी के चलते एक तो सभी गांवों में पोलिंग बूथ नहीं होते। जहां बूथ होंगे, वहां तक पहुंचने के रास्तों पर बरसात ने मुश्किलों की बौछार कर रखी है। ऐसे में इस बार इस बात पर तमाम निगहें होंगी कि मतदान का प्रतिशत कहां तक जाता है।

बरसाती मौसम परेशानियों के साथ-साथ जहां पहाड़ों को नमी और ठंडक भी दे रहा है, वहीं पंचायत चुनावों के दांव-पेच सियासी तापमान भी बढ़ा रहे हैं। हाई कोर्ट में चुनावों का मामला फंसता दिखाई दिया नहीं कि राजनीतिक बयानबाजी जोर पकड़ने लगी। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा कि ये सारी चुनावी उलझनें और असमंजस जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं, ताकि पंचायतों को भी अपनी मुट्ठी में किया जा सके। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अफसरों और चुनाव आयोग को अपने इशारे पर नचा रही है। भाजपा की ओर से जवाबी हमले भी जारी हैं और पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय के चुनावों में बुरी तरह मुंह खाने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायतों से भी सफाया होने का डर कांग्रेस को दिन-रात सता रहा है।

संगठनिक स्तर पर बात करें तो निस्संदेह यहां भी भाजपा का हाथ ऊपर दिखाई दे रहा है। शहर से लेकर ब्लाक स्तर तक जिस तरह पार्टी की गतिविधियां सक्रिय रूप से चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि पंचायती चुनाव में भी कांग्रेस को मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। भाजपा के लिए अच्छा यह है कि पिछले दिनों उसके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भले ही निर्विरोध संपन्न हो गया हो, लेकिन इस बहाने पार्टी संगठन के कील-कांटे दुरुस्त करने का वांछित अवसर उसे जरूर मिल गया। सत्तारूढ़ होने के चलते संसाधन और प्रभाव की दृष्टि से भी भाजपा को स्वाभाविक रूप से बढ़त मिली हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता गांवों तक भी दो-दो हाथ करने को मुस्तैद हैं। दूसरी ओर, आपसी खींचतान और प्रतिद्वंद्विता ने कांग्रेस संगठन को अंदर से एक हद तक छीज दिया है। एक के बाद एक पराजय से कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह भी कुछ ठंडा-सा नजर आता है। मीडिया में चंद नेताओं की बयानबाजियों को छोड़ दें तो जिला और ब्लाक स्तर पर पार्टी की गतिविधियां शिथिल दिखाई देती हैं। कुछ नेता एकला चलो की राह पर हैं तो कुछ को सामने वाले का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। ऐसे में गांवों की सरहद जमीन वाले चुनावी अखाड़े में वह कितनी मजबूती से उतरती है, यह अगस्त की शुरुआत में पता चल जाएगा।

फिलहाल गांवों में पेशबंदियां शुरू हो गई हैं और चौपालों पर चर्चाओं का दौर भी चल पड़ा है। स्थानीय मुद्दे के अलावा चर्चा में मोदे बनाम राहुल भी हैं। हरेला पर्व के साथ ही अगले पंद्रह दिन पहाड़ों में हरियाली और सियासत के रंग चढ़ेंगे दिखेंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बढ़ा सियासी तापमान। प्रतीकात्मक

मंथन

शेयर बाजार में बढ़ती दिलचस्पी

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

भारत अब लोक कल्याणकारी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौर से आगे बढ़कर सर्व-समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर है

भारत में पिछले एक दशक में कई स्तरों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन 1991 के बाद शुरू हुए जब भारत ने वैश्विक आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप लोगों के आर्थिक व्यवहार में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है। कम ब्याज दरों पर कर्ज और ईएमआइ भुगतान से लेकर शेयर बाजार तक, हर क्षेत्र में एक नई उत्सुकता देखने को मिली है। आज भारत की आर्थिक प्रगति, लोगों के बीच बढ़ती समृद्धि और विकासत्मक अर्थशास्त्र का एक नया परिदृश्य सामने आया है। भारत अब लोक कल्याणकारी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौर से आगे बढ़कर सर्व-समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर है।

हालिया भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत का आर्थिक परिदृश्य उज्ज्वल बन हुआ है। वैश्विक वित्तीय संस्था मार्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स अगले 12 महीनों में एक लाख के आंकड़े को पार कर सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआइ) में समय-समय पर सुधार देखने को मिलता है, लेकिन वैश्विक निवेश बाजार में भारत के प्रति विश्वास का स्तर अभी भी उच्च है। मार्गन स्टेनली का पूर्वानुमान केवल एक आर्थिक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में हो रहे गहरे और बुनियादी परिवर्तनों का भी एक संकेत है।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की आर्थिक सफलता की कहानियां अब केवल मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रह गई हैं। आज हम क्षेत्रीय विकास से आगे बढ़कर राष्ट्रीय विकास के स्वरूप को आकार दे रहे हैं। पहले के दिनों में जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विरोधस्त जैसे आशीष बोस ने बीमारू राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के संदर्भ में विकास की असमानता को रेखांकित किया था। वर्तमान समय में आर्थिक और विकास के संदर्भ में 'बीमारू' राज्यों में बदलाव और विकास की सबसे चमकदार कहानियां लिखी जा रही हैं। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा जारी पांच वर्षों में डीमैट खाताधारकों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन कई रोचक तथ्यों को उजागर करता है। सबसे अधिक 186 लाख इक्विटी निवेशक महाराष्ट्र में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां 130 लाख ऐसे निवेशक हैं। 2020 की तुलना में महाराष्ट्र ने 212.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 470.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। महाराष्ट्र अधिकतम वृद्धि सीमा को छूते हुए थमा पड़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विकास के मोर्चे पर आगे बढ़ा रहा है।

इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात का स्थान है, जिसने इक्विटी निवेशकों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 164.7 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके बाद बंगाल का स्थान है, जहां कोलकाता और हल्दिया डाक ने आर्थिक दृष्टि से कई सफलताएं दिलाई हैं। 2005 की तुलना में वहां इस वर्ष इक्विटी निवेशकों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 68 लाख हो गई है, जो 239 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्थान इस सूची में पांचवें स्थान पर है। यहां पर्यटन एक बड़ा रोजगार क्षेत्र है, जिससे इसकी समृद्धि को केवल बाजार निवेशकों की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। फिर भी, यहां पिछले पांच वर्षों में निवेशकों की संख्या में 394 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है। यहां इक्विटी निवेशकों की संख्या 13 लाख से बढ़कर 66 लाख हो गई है।

बिहार ने भी इन पांच वर्षों में बड़े रूपांतरण के साथ सबको चौंकाया है। यह प्रदेश डीमैट खाताधारकों की सूची में दसवें स्थान पर है। पिछले दो दशकों से वहां राजनीतिक स्थिरता रही है। वर्ष 2020 में महज सात लाख बाजार निवेशक थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 52 लाख पार कर गया है, जो 678.8 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आर्थिक उन्नति केवल बाजार निवेश या उसके सूचकांकों से नहीं मापी जा सकती। यह बदलाव तब अधिक स्थायी और प्रभावी होगा, जब देश के सभी हिस्से इस विकास में समान रूप से भागीदार बनें। समेकित विकास का तर्क और नीति अब बीते दौर की बात हो गई है। इसके स्थान पर आज विकास के सर्व-समावेशी तकाजे को भारत ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे मंचों पर भी स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार भारत में पिछले वर्षों में आए परिवर्तनों का विवेचित यथार्थ न केवल दिलचस्प है, बल्कि यह एक प्रेरक सबक भी प्रस्तुत करता है।

शेयर बाजार को लेकर लोगों में देखने को मिल रही है उत्सुकता। फाइल

****

युवा सशक्तीकरण

कौशल विकल्प नहीं

भारत, हम अपनी जनसांख्यिकी यात्रा के एक बेहद अहम मोड़ पर हैं। इस समय, भारत में बुजुर्गों से ज्यादा युवा हैं, जिसका मतलब है कि देश की उत्पादक आबादी काफी है - जिसे आर्थिक विकास के लिए जरूरी माना जाता है। बेशक, यह उत्साहजनक है, लेकिन यह एक दोधारी हथियार भी है। अगर युवाओं को आगे बढ़ने और काम करने के लिए सही माहौल नहीं दिया जाता, तो यह ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और अराजकता और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अवसर हिंसा, दंगे और अपराध दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार, युवा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका सावधानीपूर्वक दोहन और पोषण किया जाना चाहिए।

15 जुलाई को, दुनिया विश्व युवा कौशल दिवस मनाती है - यह दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और समाज में सार्थक भागीदारी के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के महत्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। भारत, एक ऐसा देश जहाँ 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, के लिए यह अवसर और भी ज्यादा मायने रखता है। आज, देश के पास वह है जिसे अर्थशास्त्री जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं - आर्थिक विकास को गति देने का एक ऐसा अवसर जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिलता है। लेकिन यह लाभांश स्वतः नहीं मिलता। इसे अर्जित करना होगा, और इसका अर्थ है युवाओं को ऐसे कौशल प्रदान करना जो भविष्य की नौकरियों के अनुकूल हों। दुर्भाग्य से, एक हालिया सरकारी अध्ययन ने एक चिंताजनक अंतर उजागर किया है: केवल 47 प्रतिशत स्कूल ही कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, और केवल 29 प्रतिशत छात्र ही उनमें भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समूहों में कौशल का यह अंतर विशेष रूप से व्यापक है।

भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करने के लिए, भारत सरकार ने कई प्रमुख कौशल विकास पहल शुरू की हैं। कौशल भारत मिशन एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है जो विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। लटछ प्रमाणन और नौकरी सहायता के साथ निःशुल्क, उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण प्रदान करता है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित संकल्प और स्ट्राइव, आईटीआई के आधुनिकीकरण और स्थानीय कौशल वितरण में सुधार पर केंद्रित हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को उपकरण, प्रशिक्षण, ऋण और बाजार पहुँच प्रदान करके सहायता करती है। सरकार ने उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग को भी गहरा किया है।

उदाहरण के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (टरव्र) ने हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन (ए१ए) रखरखाव में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शेल इंडिया के साथ साझेदारी की है। भारत इन विविध पहलों में सुसंगतता और दीर्घकालिक हस्तिक्षेप लाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति (2025-2035) का मसौदा भी तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने कौशलिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की दीवार को गिराने का एक साहसिक प्रयास किया है। ये योजनाएँ और पहल, प्रभावशाली होते हुए भी, अभी भी आवश्यकताओं से पीछे हैं। इसके अलावा, इनमें से कई योजनाओं के कार्यान्वयन में अभी भी बहुत कुछ अपेक्षित है। विश्व युवा कौशल दिवस हमें याद दिलाता है कि नवाचार, स्वचालन और वैश्विक एकीकरण से संचालित अर्थव्यवस्था में कौशल ही नई मुद्रा है। भारत के लिए, यह दिन केवल संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का स्मरण करने का नहीं है - यह एक राष्ट्रीय मिशन के प्रति पुनः प्रतिबद्धता का भी दिन है।

डालीकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। बेहतर प्रशिक्षकों, बाजार की माँग पर वास्तविक समय के आँकड़ों और प्रशिक्षण तक अधिक समावेशी पहुँच की आवश्यकता है - विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए। भारत की युवा आबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है - और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। विश्व युवा कौशल दिवस इस बात पर चिंतन करने का अवसर है कि हम कितनी दूर आ गए हैं और हमें कितना आगे जाना है।

ग्लोबल वार्मिंग पर पुनर्विचार जरूरी

जलवायु संकट सिर्फ.एक पर्यावरणीय आपातकाल नहीं है। यह हमारी बेचैन, उपभोग-प्रेरित ज़िंदगी का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन 2030 एक आमूलचूल बदलाव का आह्वान करता है। ज्यादा की चाहत से लेकर समझदारी से चुनाव करने तक, बाहरी संचय से लेकर आंतरिक स्पष्टता तक।

आचार्य प्रशांत
लेखक, एक दार्शनिक हैं।

जलवायु संकट सिर्फ.एक पर्यावरणीय आपातकाल नहीं है - यह हमारी बेचैन, उपभोग-प्रेरित ज़िंदगी का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन 2030 एक आमूलचूल बदलाव का आह्वान करता है। ज्यादा की चाहत से लेकर समझदारी से चुनाव करने तक, बाहरी संचय से लेकर आंतरिक स्पष्टता तक, इससे पहले कि अपरिवर्तनीय क्षति हमारी नई सामान्य स्थिति बन जाए। हमारे समय में कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। ग्रह बदतर होता जा रहा है, और हम ही इसे कगार पर धकेल रहे हैं। जलवायु संकट किसी एक आपदा का नतीजा नहीं है, बल्कि हर दिन लिए जाने वाले लाखों फैसलों का नतीजा है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक आईना है।

हम एक ऐसी दुनिया में पले-बढ़े हैं जिसने हमें और ज्यादा की चाहत रखने को कहा: ज्यादा भौतिक विकास, ज्यादा गति, ज्यादा आराम। और अब, यही चाहत हमें जकड़ रही है। पृथ्वी हमें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बाढ़ और लुप्त होते वन्यजीवों के जरिए चेतावनी दे रही है। लेकिन शायद सबसे जोरदार चेतावनी वह है जिसे हम सुन नहीं पा रहे हैं - हमारे भीतर की असंवेदनशीलता, हमारा वह हिस्सा जो अब इन सब से परेशान नहीं होता। जहां भी हम देखते हैं, धरती बोल रही है, गर्मी बढ़ रही है, जानवर गायब हो रहे हैं, जंगल खामोश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हम पर्यावरणीय अराजकता के इतने आदी हो गए हैं कि यह मुश्किल से ही महसूस होता है। बाढ़, सूखा, आग जो कभी चौंकाने वाली थीं, अब आम लगती हैं।

जितना हम देखते हैं, उतना ही कम हमें बदलाव की जरूरत महसूस होती है। और यही गहरा संकट है। यह सिर्फ. लुप्त होते वन्यजीवों या बिगड़ते मौसम के पैटर्न के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हमने आंतरिक रूप से कैसे समायोजन किया है, कैसे हमारी संवेदनशीलता जो वास्तव में मायने रखती है, फीकी पड़ गई है। धीरे-धीरे, असामान्य सामान्य लगने लगता है। यही से असली नुकसान शुरू होता है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कोई भी कानून, सम्मेलन या नई आकर्षक तकनीक इसे अकेले ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि यह सिर्फ.पर्यावरण के बारे में नहीं है। यह हमारे बारे में है। यह एक बेचैन मन के बारे में है जो हमेशा और अधिक के पीछे भागता रहता है और कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। आप इसे चारों ओर देखते हैं: बढ़ती आबादी में, बढ़ती भौतिक मांगों में, और इस शांत धारणा में कि अधिक चीजों का मतलब अधिक खुशी है। लेकिन क्या इसने कभी सचमुच कुछ दिया है? यदि हम बुद्धिमानी से काम करना चाहते हैं तो हमें पहले स्पष्ट रूप से देखना होगा। इसीलिए प्रणतअद्वैत फाउंडेशन ने ऑपरेशन 2030 शुरू किया है—कोई और नीतिगत समाधान सुझाने के लिए नहीं, बल्कि गहरे सवाल पूछने के लिए। क्या हो अगर असली जलवायु संकट सिर्फ.हमारे बाहर न होकर हमारे भीतर हो? ज्यादा सामग्री के लिए दौड़ करने, जमाखोरी करने, और लगातार और ज्यादा चाहने की हमारी जरूरत में? यह आंतरिक बेचैनी हमारे आसमान में बढ़ते कार्बन में झलकती है। 1750 में, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगभग 270 भाग प्रति मिलियन था। 1900 तक, यह बढ़कर 300 हो गया। लेकिन उसके बाद, सब कुछ बदल गया। 20वीं सदी में तेजी से औद्योगीकरण हुआ और उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि हुई। 1950 के दशक तक, कार्बन का स्तर लगभग 10 पीपीएम प्रति दशक की दर से बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया जो स्पष्ट होता जा रहा था: हमारे उत्सर्जन के साथ-साथ ग्रह भी गर्म हो रहा था।

2000 के दशक की शुरुआत तक, चिंता एक शांत दहशत में बदल गई। इसी बेचैनी के चलते 2015 का पेरिस समझौता हुआ, जिसमें दुनिया इस बात पर सहमत हुई कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बढ़ने से अचानक बदलाव आ सकते हैं: बर्फ पिघलना, मौसम का रिसाव, समुद्री धाराओं में बदलाव। इसलिए, देशों ने 2019 को आधार मानकर 2030 तक उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कटौती करने का संकल्प लिया। लेकिन हम यहीं हैं। वह बाधा पूरा नहीं हुआ। हम 1.5 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तय समय से कई साल पहले। चेतावनियां तो पहले से ही थीं। बस हमने उस शोर के बावजूद ध्यान नहीं दिया। यह क्षण हमसे क्या मांग करता है? कि हम आंकड़ों से आगे देखें और पूछें: उनका असल में क्या मतलब है?

जब हम आपदा सुनते हैं, तो हमारे मन में बाढ़, युद्ध और महामारियाँ आती हैं। लेकिन जो चुपचाप घटित हो रहा है, वह और भी गंभीर और कहीं अधिक स्थायी हो सकता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस पार करना सिर्फ.चार्ट पर दिखाई देने वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ अपरिवर्तनीय शुरू हो गया है। बर्फ की चादरें पिघल रही हैं। जमी हुई जमीन मीथेन छोड़ रही है। समुद्री धाराएँ बदल रही हैं। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम रोक या पीछे ले जा सकें। इनमें अब गति है।

तमाम बातों के बावजूद, 2019 से उत्सर्जन लगभग 58 गीगाटन प्रति वर्ष पर बना हुआ है। पेरिस समझौते ने तीन भविष्य की योजनाएँ रखीं: हरित मार्ग (2030 तक उत्सर्जन को 33 गीगाटन तक कम करना), पीला मार्ग (कुछ हद तक 39 गीगाटन तक बढ़ने देना, लेकिन जोखिम के साथ), और लाल मार्ग, जिस पर हम चल रहे हैं, जहाँ उत्सर्जन बढ़ता रहेगा और तापमान 3त्न तो पार कर जाएगा। अब 2025 है, और उत्सर्जन अभी भी 58 गीगाटन से ऊपर है। हम सब कुछ जानते हुए भी, अभी भी लाल रास्ते पर ही हैं। और बात यह है: यह संकट हमारी रोजमर्रा की बातचीत में शायद ही कभी दिखाई देता है। और जब हम जरूरी बातों पर बात करना बंद कर देते हैं, तो हम इस पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं।

तो असल में इस संकट की जड़ क्या है? लक्ष्यों के भीतर रहने के लिए, पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को 2030 तक प्रति वर्ष 2.1 टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करना चाहिए। 2050 तक, इसे लगभग 0.7 टन तक कम करना होगा। इसका मतलब शून्य उत्सर्जन नहीं है, बल्कि संतुलन है: हम जो उत्सर्जित करते हैं, वह पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली मात्रा के बराबर होना चाहिए। लेकिन दुनिया समान नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत का उत्सर्जन लगभग 1.9 टन प्रति व्यक्ति है, जो सीमा के भीतर है। यूरोपीय संघ 7 पर उत्सर्जन करता है। अमेरिका 16 के आसपास है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए, यह 20 से 25 के बीच है।

और अजीब बात यह है कि सबसे बड़े प्रदूषक अक्सर बदलाव लाने में सबसे धीमे होते हैं। सबसे अमीर देश, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा और विज्ञान है, वे अभी भी सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। और कम से कम कार्रवाई करें। पिछले दस वर्षों में, शीर्ष 1 प्रतिशत उत्सर्जकों ने लगभग 13 लाख असमय मौतें की हैं। उन्होंने अपने हिस्से का 20 गुना से भी ज्यादा इस्तेमाल किया है, जबकि नुकसान ज्यादातर भारत सहित वैश्विक दक्षिण को हुआ है। अति-धनी 0.1 प्रतिशत लोग हर साल प्रति व्यक्ति 1,000 टन से ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। वहीं, दुनिया का निचला आधा हिस्सा, लगभग 4 अरब लोग, उत्सर्जन में केवल 5 प्रतिशत का योगदान करते हैं। फिर भी उन्हें सबसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है: भूख, गर्मी, बाढ़, पलायन। यह सिर्फ.कार्बन का मामला नहीं है। यह न्याय का मामला है। कुछ लोगों को राहत मिलती है। अरबों लोग इसकी कीमत चुकाते हैं। इसलिए हमें पूछना चाहिए: सफलता के नाम पर हम असल में किसका पीछा कर रहे हैं?

जलवायु संकट अपने भीतर एक गहरे शून्य को दर्शाता है जिसे हम अंतहीन उपभोग से भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह शून्य आंतरिक स्पष्टता से भरेगा, बाहरी संचय से नहीं। ऑपरेशन 2030 सफलता की नई परिभाषा गढ़ने का आह्वान करता है, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से लेकर ज्ञान को चुनने तक। यह कोई अव्यावहारिक बात नहीं है। लाखों लोग पहले ही वेदांत की शाश्वत शिक्षाओं और अधिक स्पष्टता के साथ जीवन जीने के माध्यम से अपने जीवन को नया रूप दे चुके हैं। हमें उन लोगों को आदर्श मानने की शिक्षा दी गई है जो सत्ता और उपभोग में पारंगत हैं, लेकिन अक्सर वही लोग जलवायु परिवर्तन के सबसे गहरे निशान छोड़ते हैं। ऑपरेशन 2030 इस सांस्कृतिक भ्रम को चुनौती देता है। यह माँग करता है कि हम उत्सर्जन के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करें। सार्वजनिक हस्तियों और निगमों को अपने कार्बन पदचिह्नों का खुलासा करना चाहिए, ताकि हम सफलता के दिखावे को देख सकें।

छोटी उड़ान या गोमांस खाने की कीमत उनके वास्तविक कार्बन पदचिह्न को नहीं दर्शाती। ऑपरेशन 2030 उत्पाद की लागत को ऐसे स्तर पर लाने पर जोर देता जो वास्तविक पर्यावरणीय नुकसान को दर्शाता हो। जब लोगों को पता चलता है कि वे वास्तव में किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं, तो उनके विकल्प बदल जाते हैं। और जब मांग बदलती है, तो बाजार भी बदल जाता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति शायद ही कभी नेतृत्व करती है। यह जनता के मूड के अनुसार है। इसीलिए ऑपरेशन 2030 में नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। हर खरीदारी, हर क्लिक, हर बातचीत एक राजनीतिक कार्य है। हमारा लक्ष्य लोगों को जागरूकता और क्षमता से लैस करना है, ताकि जलवायु सिर्फ. एक नीतिगत मुद्दा न रहे, बल्कि एक जन आंदोलन बन जाए।

ये हमारे आखिरी साल हो सकते हैं: न सिर्फ. पारिस्थितिक संतुलन को थोड़ा बहाल करने के लिए, बल्कि इस बात पर विचार करने के लिए कि असल में क्या मायने रखता है। हम एक ऐसी दुनिया में पले-बढ़े हैं जिसने हमें और ज्यादा पाने की चाहत दी है: ज्यादा भौतिक विकास, ज्यादा गति, ज्यादा आराम। और अब, यही चाहत हमें जकड़ रही है। पृथ्वी हमें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बाढ़ और लुप्त होते वन्यजीवों के जरिए चेतावनी दे रही है। लेकिन शायद सबसे जोरदार चेतावनी वह है जिसे हम सुन नहीं पा रहे हैं।

कैसे एक व्यक्ति देश बदल सकता है!

जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटरमेरिट्जबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के कारण एम.के. गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो किसने सोचा होगा कि एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या कर सकता है।

अभिषेक जैन
लेखक, हिमाचल प्रदेश के वित्त सचिव हैं।

जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटरमेरिट्जबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के कारण एम.के. गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो उन्होंने सोचा होगा कि एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या कर सकता है। लेकिन उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और 1947 में हमें आजादी दिलाई। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल विकास की पूरी रूपरेखा बदल दी और अंततः भारत के राष्ट्रपति के रूप में लाखों छात्रों को प्रेरित किया। न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से विज्ञान की दिशा बदल दी।

आईंस्टीन ने अपने ईथरबार एमसी स्क्वायर के अपने समीकरण से आधुनिक विज्ञान को बदल दिया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से शासन कला को नया रूप दिया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को एक अरब से ज्यादा भारतीयों का धर्म और सचिन को क्रिकेट का भगवान बना दिया। धोनी ने हमें 2011 में विश्व कप जिताया।

ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड बनकर भारतीय महिलाओं को सुंदरता और व्यक्तित्व के शिखर पर पहुँचाया। हम ऐसे ही लोगों के बारे में सोच सकते हैं - मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, कल्पना चावला, स्टीव जॉब्स, लता मंगेशकर, अमर्त्य सेन।

इस प्रकार, एक व्यक्ति केवल एक संख्या नहीं है; यह एक व्यक्ति की शक्ति है। एक व्यक्ति से, मैं एक रिश्ते की शक्ति पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हम सभी एक माँ की शक्ति को जानते हैं जो हम सभी को इस धरती पर लाती है। एक पिता की शक्ति जो जीवन के हर सुख-दुख में हमारा पालन-पोषण करता है। एक भाई की शक्ति, उदाहरण के लिए, अजीत तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की सफलता में। एक बहन की शक्ति जो हमारी कलाई पर राखी बाँधती है। एक शिक्षक की शक्ति को याद करें जिसकी बजह से हम अपने जीवन में जो भी ऊँचाइयाँ प्राप्त करते हैं। एक मित्र की शक्ति जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ रहता है। एक शुभचिंतक, एक प्रेरक, एक उपलब्धि ढ्ढसिल करने वाले की शक्ति। एक व्यक्ति की शक्ति जो सभी में एक है और किसी के लिए सर्वस्व है। संबंधों की शक्ति हर चीज पर हावी हो जाती है। व्यक्तियों और संबंधों से आगे बढ़ते हुए, आइए हम एक चीज की शक्ति को समझें। कल्पना कीजिए कि एक किताब—मान लीजिए ब्राइबल या गीता—लोगों को प्रभावित करने में कितनी शक्ति रखती है। एक वोट की शक्ति मुख्यमंत्रियों की जीत या हार तक तय कर सकती है।

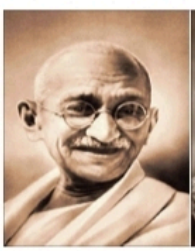

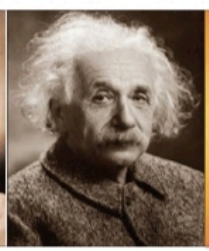

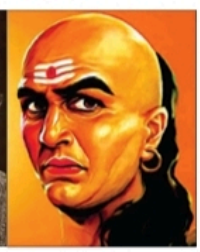

परीक्षा में एक अंक की शक्ति फेल और पास तय कर सकती है। एक मिनट की शक्ति उस व्यक्ति के लिए जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण उड़ान चूक जाता है। एक वायरस—कोरोना—की शक्ति दुनिया भर में तबाही मचा सकती है। एक वैक्सीन—कोवैक्सीन या कोविशील्ड—की शक्ति। डूबते हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए एक हाथ की शक्ति। एक गीत—वंदे मातरम या ए मेरे वतन के लोगों—की शक्ति। एक छोटी सी बात भी मायने रखती है।

मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक की शक्ति को पहचान सकें। वह एक व्यक्ति, एक रिश्ता, एक चीज या एक मूल्य बनें। हम सभी वह एक व्यक्ति हो सकते हैं जिससे दूसरे प्रेरणा, प्रतिबद्धता, मूल्य, कड़ी मेहनत, टीम वर्क, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की उम्मीद करते हैं। हम वह एक व्यक्ति हो सकते हैं जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। एक व्यक्ति दुनिया बदल सकता है और निश्चित रूप से, भारत को भी बदल सकता है। आइए, दूसरों के कहने या करने का इंतजार न करें और न ही अपने देश की सभी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देने की कोशिश करें — बस वह एक व्यक्ति बनें जो काम करता है, जो मायने रखता है। आइए, वह एक प्रेरणा, एक प्रेरणा, एक रिश्ता, एक भावना बनें।

काश मैं एक व्यक्ति के रूप में ऐसा कर पाता, 13 साल की छोटी सी उम्र में बेल्जियम, तुर्की और डॉलैंड में तीन बार वर्ल्ड स्पीड टाइपिंग चैंपियनशिप जीत पाता, और एक प्रशासक के रूप में, चंडीगढ़ में जनगणना के 150 साल के इतिहास में भारत की पहली 'जनगणना गैलरी' स्थापित कर पाता। भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है — आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, आदि — लेकिन आइए हम में से हर कोई वह व्यक्ति बने जो सिर्फ.बातें न करे, बल्कि काम करे।

छह शून्य का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उसके आगे एक लगाने से दस लाख डॉलर हो जाते हैं। एक व्यक्ति का एक छोटा सा कदम शुरुआत हो सकता है। हम सभी में एक की शक्ति है। आइए इसे समझें और एक की शक्ति को उजागर करें।

आप की बात

कुत्तों का आतंक

इंदौर में एक छात्रा परीक्षा देने कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में उसे आवारा कुत्तों के झुंड ने घेर लिया और पैर में काट(नोच) लिया। पिछले साल ही उज्जैन में अपने घर के बाहर साइकिल चला रही 7 वर्ष की बच्ची आवारा श्वान को देख घर की ओर दौड़ी, गिरकर बेहोश हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी जून में यूपी के बुलंदशहर में युवा कबड्डी खिलाड़ी की मौत कुत्ते के पिल्ले द्वारा काटने से हो गई।वाहे गांव हो या कस्बे या शहरों में सड़कों पर विचरण करते आवारा श्वान व मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, कोई घायल होकर जिंदगी से बेबस हो जाता है, तो कई मौत के मुंह में समा जाते हैं। इंदौर के सरकारी हुकुमचंद अस्पताल के रिकॉर्ड अनुसार 1 जनवरी 25 से 13 जुलाई तक 24 हजार से अधिक लोगों को इन आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। एक तरफ से यह राष्ट्रीय समस्या बन गई है। देश की संसद में भी आवारा कुत्तों से परेशान होकर राजस्थावाद से भाजपा के सांसद द्वारा यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने चौंकाने वाले आंकड़े भी दिए थे। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आवारा कुत्तों से परेशानी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए, सरकार से आवश्यक सुरक्षा व नियंत्रण के लिए अगाह किया था। लेकिन इसके बावजूद आवारा कुत्तों व मवेशियों का कोई माकूल निदान नहीं हो पा रहा है।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, उज्जैन

समोसा-जलेबी भी हानिकारक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में लोगों में बढ़ते मोटापे व उससे होने वाली बीमारियों एवं बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के मद्देनजर समोसा,कचोरी, जलेबी, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज,पकोड़े,बड़ापाव, चॉकलेट,पेस्ट्री, सॉफ्ट-ड्रिंक्स, गुलाबजामुन आदि खाद्य पदार्थ में कितना तेल-चीनी की मात्रा होती है। यह दुकानदार व सरकारी/गैरसरकारी माहकमों के पेड व स्टेशनरी-पैकेट्स पर लिखने का आइड किया है, ताकि लोगों में इससे बढ़ने वाले मोटापे व उससे होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके। यह बात सही है कि देश में बच्चों और युवाओं में मोटापे और उनसे से सम्बंधित बीमारियां बढ़ रही है। एक सर्वे के अनुसार २०२१ में देश में मोटापे से १८ करोड़ लोग पीड़ित थे जो अनुमानतः २०५० के ४५ करोड़ तक हो सकते हैं। भारत मोटापे से पीड़ित विश्व में दूसरा देश है। पहला देश चीन है जहाँ ४० करोड़ अधिक लोग मोटापे से परेशान हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका है जहाँ इनकी आबादी १७ करोड़ से ज्यादा है। एक बात और सही है मोटापे से बीमारियां बढ़ रही है और उसपर स्वास्थ्य खर्च भी, इन सभी के मद्देनजर ही सरकार ने स्वच्छ देश और स्वस्थ देश बने इसलिए जनहित में विशेष कदम उठाया है। अब जिस तरह सिगरेट-शराब स्वास्थ के लिए हानिकारक है लिखवाया व सन्देश दिया जाल है। ठीक इसी तरह समोसा-कचोरी-जलेबी का सन्देश लिखना भी निर्णयकताओं को जरूरी हो सकता है।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

धर्मांतरण का नासूर

देश के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन की साजिशों का पदार्फाश होता जा रहा है। इस्लामी जेहादियों द्वारा येन केन प्रकारेण , लालच देकर , मनोवैज्ञानिक शोषण करके बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेला किया जा रहा है। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी से विदित होता है कि विविध धर्मों एवं सम्प्रदायों को मानने वाले देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ यह धर्म परिवर्तन की धोखाधड़ी विदेशों से प्राप्त फंडिंग / हवाला कारोबार के दम पर की जा रही है। जो कि सर्वदा निंदनीय एवं गैर कानूनी गतिविधि है जेहादियों के वित्तीय प्रायोजकों ने हिन्दुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने का बोगस भ्रम पाल रखा है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को विदेशी फंडिंग में नेपाल को रूट बनाया जाना पकड़ा गया है। कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, कश्मीर, केरल, असम, पूर्वोत्तर आदि की जनसांख्यिकी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस सामाजिक धार्मिक संक्रमण से हरियाणा उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रह गया है। देश के बहुसंख्यक हिन्दू समाज को जागृत रहकर धर्मांतरण के नासूर का इलाज करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का सहारा लेना चाहिए।

– **युगल किशोर शर्मा**, फरीदाबाद

प्राथमिक स्कूलों पर ध्यान दें

इतना तो तय है आज 'जम्मू कश्मीर' राज्य, शेष प्रदेशों से अलग दीखता है उसके पीछे एक ही कारण है, चाहे जिन भी कारणों से हो, कश्मीर और कश्मीरियों को, हम अन्य राज्यों के लोग शक के नजरों से देखते हैं। हमें कश्मीर घाटी से बेइन्तहाँ मोहब्बत तो है मगर कश्मीरियों से शख्त नफरत है। हमें कश्मीर चाहिए मगर 'कश्मीरी' नहीं। ऐसा कैसे चलेगा ? चाहे जैसा भी हो,आजादी के बाद, कश्मीर भारत का अटूट भाग है। आगे भी रहेगा। मगर हमें आम कश्मीरियों के दुःख दर्द को भी सुनना पड़ेगा। आखिर भारत तुमा शरीर का वो भी एक अंग है। अगर उस अंग को चोट लग जाये किसी प्रकार का जख्म हो जाए तो उसका इलाज तो भारत सरकार को ही करना होगा। १३ जुलाई को जब कश्मीर में शहीदी दिवस मनाने की प्रथा है तो उस पर रोक लगाने की क्या जरुरत थी ? एक सूबे का सीएम उमर अब्दुल्ला नक्सबंद साहिब कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़े श्रीनगर में 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाना पड़ा क्या यह दृश्य जब शेष विश्व में गया होगा तो क्या इससे भारत का नाम और रौशन होगा ? यह नाटकीय दृश्य अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस व विपक्षी दलों के कई नेताओं को शहीद दिवस मनाने के लिए कब्रिस्तान जाने से रोकने के लिए नजरबंद किए जाने के एक दिन बाद सामने आया।

– **जंग बहादुर सिंह**, जमशेदपुर

अंतरिक्ष में उड़ान का और बढ़ा हौसला

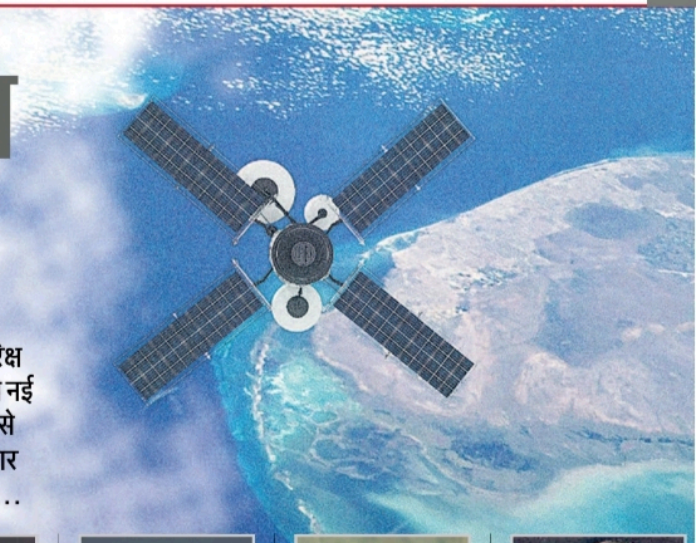

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक यात्रा से भारत में विज्ञान और अंतरिक्ष उद्योग क्षेत्र को बहुत बल मिलेगा। इसरो के साथ निजी उपक्रमों में भी तरक्की की नई बहार आएगी। आज यह देखना बहुत प्रेरक है कि भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स कैसे आगे बढ़कर बेहतर काम कर रहे हैं। यह क्षेत्र देश में संपन्नता लाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। पेश है अंतरिक्ष क्षेत्र का जायजा लेती शौविक दास की खास रिपोर्ट...

आज अपने देश में आर्थिक और सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक का भरपूर उपयोग हो रहा है। इससे अनेक स्टार्टअप्स या उद्यमों को बल मिल रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां भी नए स्टार्टअप्स के साथ सक्रिय होने लगी हैं। इस क्षेत्र में कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं और अपने बनाए उपकरणों व सेवाओं की दूसरी देशों में बिक्री बढ़ाने में जुटी हैं।

अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध शर्मा अपनी कंपनी के बेंगलुरु मुख्यालय में उपग्रह निर्माण के लिए उपक्रम मुंखला स्थापित कर रहे हैं। यह कंपनी पहले से नक्शे बेचने का काम करती आ रही है। नक्शे बेचने का काम पृथ्वी की कक्षा में बढ़ती भीड़ में उपग्रहों की राह सुगम बनाने का उद्यम है। अनिरुद्ध बताते हैं कि हम अपने ग्राहकों को उपग्रह डाटा बेच रहे हैं और हमने यह फैसला पिछले छह महीनों में दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपना अंतरिक्ष रक्षा और निगरानी ढांचा बनाने में बढ़ती रुचि को देखते हुए लिया है।

एक समय वीरान रहा अंतरिक्ष रक्षा सेवा क्षेत्र अब आकाश में निगरानी की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भारतीय कंपनियों को लुभा रहा है। दिगंतरा के अलावा, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सआई, बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस तथा पिक्सल और हैदराबाद स्थित कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज, निगरानी अनुबंध होने की उम्मीद है। भारत की इन गतिविधियों से वैश्विक अंतरिक्ष रक्षा और निगरानी तकनीक के क्षेत्र में अगुआ देश अमेरिका व चीन को हमसे चुनौती मिल सकती है।

> बीते महीनों में भारत एक नए व्यावसायिक क्षेत्र को उभरते देख रहा है। अंतरिक्ष उद्योग का सरकारी और निजी क्षेत्र देश को अपार भू-राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकता है। भारतीय कंपनियां उपग्रह निर्माण में तेजी से आगे आ रही हैं। साथ ही, निगरानी-संबंधी अंतरिक्ष डाटा सेवा मुहैया कराने के लिए दुनिया के अनेक देशों से सौदे या अनुबंध कर रही हैं।

आकाश का बढ़ता महत्व

अनिरुद्ध शर्मा बताते हैं कि उपग्रहों द्वारा पृथ्वी की खींची गई स्पष्ट तस्वीरों की मांग बढ़ती जा रही है। देशों को पृथ्वी के अवलोकन और स्वतंत्र निगरानी के लिए भी हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरों की जरूरत है, जिसे भारतीय कंपनियां पूरी कर रही हैं। पिछली तीन तिमाहियों में यह मांग ज्यादा बढ़ी है। अनिरुद्ध शर्मा बताते हैं कि उनकी कंपनी को अब तक 10 लाख डॉलर से लेकर डेढ़ करोड़ डॉलर तक के अनुबंध मिलने की संभावना बनी है। मांग बढ़ना निश्चित है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही तमाम कंपनियों को वित्तीय लाभ होगा।

गैलेक्सआई इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली दूसरी कंपनी है। पिछले महीने इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुयश सिंह ने दुनिया भर से निगरानी डाटा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई-रिजॉल्यूशनइमेजिंग उपग्रह के बाजार में प्रवेश करने की घोषणा की है। बीती 2 जुलाई को एक अन्य स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस ने भी ऐसा ही किया और एक ऐसा अल्ट्रा-लो- अर्थ उपग्रह पेश किया है, जो कम लागत में जल्दी और बेहतर तस्वीरें तैयार कर देगा। ध्यान रहे, ये दोनों स्टार्टअप्स उस बाजार के लिए होड़ में हैं, जिसमें बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल ने शुरुआत में ही प्रवेश कर लिया था। पिक्सल ने डाटा-अन-ए-सर्विस प्रारूप में देशों को अल्ट्रा-हाई-रिजॉल्यूशन निगरानी उपग्रह प्रदान किए हैं। इस भारतीय कंपनी ने पहले ही अमेरिका में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रखी है और इसने रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी (डारपा) के साथ अनुबंध किए हैं। इस क्षेत्र में भी अनेक दिग्गज कंपनियां हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व इंजीनियर सुब्बा राव पावुलुरी द्वारा संचालित अनंत टेक्नोलॉजीज आज बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में तीन सैटेलाइट मैन्यूफैक्चरिंग लाइन चला रही है। 1992 में स्थापित अनंत टेक्नोलॉजीज की कमान तीन दशकों से इसरो की आपूर्तिकर्ता रही है और इसने निगरानी उपग्रहों का निर्माण किया है। आज यह क्षमता बढ़ाकर वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रह बनाने का दम भर रही है।

अनंत टेक्नोलॉजीज वैश्विक अंतरिक्ष रक्षा की बुनियादी जरूरतों के ऑर्डर के लिए एक अन्य कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज एक एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण कंपनी है, जिसे 2019 में अडानी समूह की शाखा अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने अपने स्वामित्व में ले लिया था। इन बढ़ते मौकों को देखते हुए बड़ी टेक कंपनियां भी मैदान में आई हैं या आ रही हैं।

लगातार बढ़ता पूंजी निवेश

गूगल जून 2023 में ही पिक्सल में निवेश करनेवाले शुरुआती निवेशकों में से एक बन गया था। इसी साल 8 जुलाई को अमेजन वेब सर्विसेज ने अपने स्पेस प्रोग्राम के दूसरे संस्करण की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 40 स्टार्टअप्स को व्यावसायिक संसाधन, विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। अमेजन के अंतरिक्ष स्टार्टअप इनक्यूबेटर अभियान में पांच प्रमुख क्षेत्रों में से दो उपग्रह इमेजरी और भू-स्थानिक अनुप्रयोग हैं, जो उभरते अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेजन एक्सेलरेटर का इस वर्ष का संस्करण चार देशों में उपलब्ध होगा, जो इस उद्योग में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। जबकि 2024 के पहले संस्करण में केवल भारत ही इसकी नजरों में था।

जेएसडब्ल्यू डिफेंस की अमेरिकी साझेदार शील्ड एआई के भारत में प्रबंध निदेशक सर्जन शाह कहते हैं कि देश में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ अंतरिक्ष रक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत करना जरूरी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से काफी बढ़ावा मिला है। सरकार में भी यह धारणा है कि भारतीय रक्षा बल हवाई क्षमताओं में बुनियादी सुधार के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

आगे बढ़ने का सही मौका

अंतरिक्ष उद्योग से लाभ कमाने के लिए भारत में अचानक इतनी हलचल क्यों मच गई है? असल में 2022 से ही इस क्षेत्र में गति तेज हो गई है। तब यूक्रेन पर आक्रमण के चलते अधिकांश यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और विनिर्माण आपूर्ति में कमी आई, क्योंकि रूस उपग्रह निर्माण, खासकर रक्षा और निगरानी के मामलों का गढ़ा हुआ खिलाड़ी रहा है। दूसरी ओर, पिछले नौ महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अप्रैल में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण अधिक से अधिक देश अपने लिए खुदमुख्तार वाला भू-राजनीतिक समाधान चाहते हैं। एक कारण और है कि अमेरिका की अपनी कठोर रक्षा साझेदारी नीति है। इस कारण वह हर देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे में, भारत दुनिया में उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। उदाहरण के लिए, पिछले दो वर्षों में भारत ने आर्मेनिया को रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति शुरू कर दी है। आर्मेनिया पहले रूस पर निर्भर था। ऐसे में, भारत की इस क्षेत्र में ताकत बढ़ी है।

मोटी कमाई की ओर

अंतरिक्ष उद्योग के मोर्चे पर पांच उद्यमों के अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि औसतन एक उपग्रह से प्राप्त निगरानी डाटा की कीमत प्रति सप्ताह 10 से 100 डॉलर प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच होती है। भारतीय कंपनियां भी उपग्रह डाटा की यही कीमत वसूलना चाहती हैं। यह कीमत केवल देश की सीमाओं की निगरानी के लिए है। इसके बाहर की कमाई का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। आज विभिन्न उपयोगों के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन वाले उपग्रह डाटा की मांग दुनिया भर में है। इनमें उदाहरण के लिए, दिगंतरा की कमाई अगले वित्त वर्ष तक तीन करोड़ डॉलर सालाना को पार कर जाएगी। सुयश सिंह बताते हैं कि हमारे उपग्रह के कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद राजस्व में तेजी से वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

दुनिया भर की सेवा

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अंतरिक्ष फेलो चैतन्य गिरि बताते हैं कि वैश्विक मांग के कारण यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देश भारत को विश्वसनीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह आपूर्तिकर्ता के रूप में देख रहे हैं और भारत भी इसके लिए तैयार है। जाहिर तौर पर अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद ही बड़े पैमाने का अनुबंध करता है। चीन हमेशा से संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था रहा है और वह केवल अपने लिए ही निर्माण करता है। ऐसे में, इस क्षेत्र में भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं।

mint

शुभांशु शुक्ला से नया आगाज

भारत के नाम के साथ एक और कामयाबी जुड़ गई है। अभी तक कोई भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर नहीं गया था। इस मोर्चे पर शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। वह 18 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे हैं और जब वह अगले महीने भारत आएंगे, तो उनकी कामयाबी की चर्चा आम लोगों तक पहुंचेगी। इससे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।

सुनीता विलियम्स से प्रेरणा

भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स सफलता और सदा प्रसन्नता की मिसाल हैं। साल 2024-2025 में तकनीकी समस्याओं के कारण उनका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास नौ महीने से ज्यादा बढ़ गया था। वह दुनिया में सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। उन्होंने नौ बार अंतरिक्ष यात्राएं की हैं और वह कुल 62 घंटे 6 मिनट तक यान से बाहर रही हैं।

कल्पना चावला से साहस

करनाल, हरियाणा में जन्मी कल्पना चावला उच्च शिक्षा हासिल करने अमेरिका गई थीं और उनकी योग्यता ने उन्हें वहां भी दुलारी बना दिया। वह अमेरिकी नागरिक के रूप में पहली बार साल 1997 में अंतरिक्ष में गई थीं और 2003 में अंतरिक्ष से लौटते हुए उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कल्पना चावला आज भी भारतीय घरों में चर्चित नाम है और उनसे युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है।

राकेश शर्मा से शुरुआत

भारतीय वायुसेना के अधिकारी राकेश शर्मा के समय अंतरिक्ष में जाना एक सपने की तरह था। तब अंतरिक्ष में शोध के लिए केंद्र स्थापित नहीं हुआ था। यात्री पृथ्वी की कक्षा से ही लौट आते थे। सोवियत संघ की मदद से 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा आज भी जीवित हैं और अंतरिक्ष विषय से लगाव रखने वाले भारतीयों की जुबान पर पहला नाम उन्हीं का आता है।

अंतरिक्ष उद्योग में तेजी से उभरती भारतीय कंपनियां

ऐसे अनेक स्टार्टअप हैं, जो वैश्विक सैटेलाइट अनुबंध के लिए निवेश जुटाने में लगी हैं और उन्हें अब आसानी से निवेश मिलने भी लगा है।

निवेश की राशि (दस लाख डॉलर में)	तारीख	निवेशक
दिगंतरा 10	20 जून 2023	पीक एसवीसी और कलारी कैपिटल
गैलेक्सआई 10	7 नवंबर 2024	स्पेशियल इनवेस्ट इंफ्रोसिस
बेलाट्रिक्स 8	6 जून 2022	बीएसएफ और इंफ्लेक्सर वेंचर्स

स्रोत : स्वयं कंपनियों की घोषणा के अनुसार

अगले एक दशक का लक्ष्य

अंतरिक्ष उद्योग पर नजर रखने वाली भारतीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के अनुसार साल 2033 तक भारत प्रति वर्ष 44 अरब डॉलर को कारोबार करने लगेगा।

अगले एक दशक में अनुमानित राजस्व (राशि अरब डॉलर में)

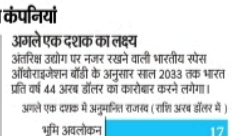

भूमि अवलोकन में जमीनी नेटवर्क, सैटेलाइट के केंद्र और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस शामिल है।

स्रोत : इन-स्पेस डिकेडल विजन, अक्टूबर 2023

अंतरिक्ष में भारत

क्यों बढ़ी जरूरत?

अमेरिका हर देश को अंतरिक्ष-आधारित निगरानी ढांचा या डाटा नहीं देता है। रूस के साथ किसी देश की साझेदारी टिकाऊ नहीं रह गई है। रूस स्वयं संघर्षों में उलझा हुआ है। फ्रांस एक प्रमुख भागीदार था, लेकिन यूरोपीय संघ में विनिर्माण बहुत महंगा है। ऐसे में, भारत एक विकल्प बनकर उभरा है।

अभी क्या हो रहा है?

वानिकी, मौसम पूर्वानुमान, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, रक्षा-सुरक्षा इत्यादि में विश्व भर में अंतरिक्ष सेवाओं की मांग बढ़ी है। एक देश से एक वर्ष के लिए उपग्रह डाटा अनुबंध 10 लाख डॉलर से अधिक का हो सकता है। ऐसे अनुबंध पाने के लिए भारतीय स्पेस कंपनियां लालायित हैं।

क्या किया जाए, अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे रहने के लिए?

भारत को अपने अंतरिक्ष विज्ञान की प्रगति के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अंतरिक्ष सेवाओं के मामले में अपने बुनियादी ढांचा को बहुत मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही, भारतीय कंपनियां ज्यादा नवोन्मेषी हों, मानचित्रण और निगरानी की सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय स्पेस कंपनियां दूसरी की तुलना में कम लागत पर काम करें। दीर्घकालिक योजनाओं के साथ भारत को आगे बढ़ना होगा।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। क्रोध से बचें। नौकरी में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी।

वृष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है।

मिथुन : वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। रुके कार्य पूर्ण होंगे। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कारोबार विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं। माता-पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल होंगे।

कन्या : मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय के बाद किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। वाहन सुख में वृद्धि होगी।

तुला : मन परेशान रहेगा। व्यर्थ के क्रोध से बचें। आत्मसंयत रहें। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

वृश्चिक : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। खर्च भी बढ़ेंगे।

धनु : मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से नया कारोबार शुरू हो सकता है। खाद्य पर भी जा सकते हैं।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र के साथ कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं।

मीन : मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र का आना हो सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

वर्ग पहेली : 8028

बाएं से दाएं

3. एकत्रित करना; सहेजना (4)
6. छिपी बात कह देना; भेद प्रकट कर देना; रहस्य बता देना (3,2)
7. पूरी तरह से; प्रत्यक्ष; बिल्कुल; साक्षात (4)
8. जमी हुई ऊन की तह; पहलू; तह; छेड़ (3)
11. वह स्थान जहां विभिन्न पक्षों के सैनिक युद्ध करते हों; युद्ध भूमि; रणक्षेत्र (3,1,3)
14. अमीर; धनी; संपन्न (3)
15. गरमी या रूखेपन से तिड़कना; फटना; कली खिलना (4)
17. आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी काम में धन लगाना; किसी काम में पूंजी लगाना (2,3)
18. आदमी- औरत; नर और नारी; महिला-पुरुष (2,2)

ऊपर से नीचे

1. अंतःपुर; आमोद प्रमोद करने का स्थान; भोग विलास करने का महल (5)
2. हुक्म; हिदायत; ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र की स्थिति का फल; व्याकरण में अक्षर परिवर्तन (3)
4. ऊपर की ओर गोलाकार कटा हुआ; कमानदार (6)
5. मना करना; रोकना; निषिद्ध करना (1,3)
9. जंग करना; युद्ध करना (3,3)
10. खाने योग्य बनाना; तैयार करना; रांधना (3)
12. नई नई; नवीनतम; नव वधू (2,3)
13. एक प्रकार का बंद गले का कोट; पुरुषों का पहराव (4)
16. कड़ियों से बनी लड़ी; लौह शृंखला; सांकल; गले में पहनने का स्वर्ण आभूषण (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली

(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8027

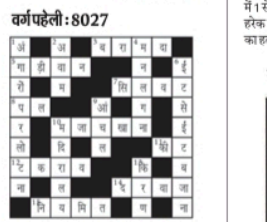

सुडोकू : 8010

* कठिन

	2					3		
	5					7		
3		6		9		5		4
			8	4	7			
2			6		5			9
			3	2	9			
5		9		6		2		7
	4					9		
	6					4		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8009

2	3	1	8	7	6	9	4	5
8	4	9	1	2	5	3	6	7
7	6	5	3	9	4	2	1	8
9	8	7	6	4	3	5	2	1
4	2	3	7	5	1	6	8	9
1	5	6	2	8	9	4	7	3
6	7	2	5	3	8	1	9	4
5	1	4	9	6	7	8	3	2
3	9	8	4	1	2	7	5	6

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

16 जुलाई, बुधवार, शक संवत् : 25 आषाढ़ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 01 श्रावण मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 20 मुहर्रम, 1447, विक्रमी संवत् : श्रावण कृष्ण षष्ठी रात्रि 09.02 मिनट तक। शोभन योग प्रात : 11.57 मिनट तक पश्चात अतिगण्ड योग, चन्द्रमा मीन राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 09.02 मिनट से। श्रावण संक्रान्ति। गण्डमूल रात्रि 04.51 मिनट से। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मैं राजनीति के क्षेत्र में आगे जाना चाहता हूं। कृपया बताएं मुझे क्या करना चाहिए?
– शेखर त्रिपाठी, मेरठ

- आपका घर पूर्व मुखी होना चाहिए या फिर घर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी होना चाहिए।
- आप अपने ऑफिस का मुख्य द्वार भी पूर्व दिशा के शुभ पद की ओर रखें।
- आप जब भी मीटिंग या कोई सभा करें, तो उसमें पूर्व मुखी होकर बैठें।
- ध्यान पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें, ताकि आत्मविश्वास में वृद्धि हो। इससे आपका जनता से भी ज्यादा जुड़ाव होगा, जिससे आपको लाभ होगा। आप अपने बायें हाथ में एक क्लियर क्वार्ट्ज तथा रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनें।

हिन्दुस्तान 1936

शाबाश शुभांशु

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी इस मायने में तो हर्ष का विषय है ही कि इस अभियान के साथ भारतीय प्रतिभा के दमखम की एक सुनहरी दास्तां मुकम्मल हुई है, बल्कि शुभांशु ने वहां जो प्रयोग किए हैं, उनके लिए भी आने वाली नस्लें उन्हें बार-बार याद करेंगी और उनसे प्रेरणा लेंगी। जाहिर है, पूरा हिन्दुस्तान इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उनके मिशन की कामयाबी के लिए लगातार दुआएं मांग रहा था, क्योंकि जिस तरह से सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को नौ महीने तक अंतरिक्ष में रुकना पड़ा था, उसके कारण कई तरह की आशंकाएं थीं। बहरहाल, इसरो, नासा और इस मिशन से जुड़े तमाम वैज्ञानिक व तकनीशियन हमारी प्रशंसा के हकदार हैं कि उन्होंने मानव सामर्थ्य का एक नया अध्याय दुनिया के आगे खोला है। अगले एक हफ्ते के एकांतवास के बाद शुभांशु आम लोगों के बीच आएंगे। मगर क्या वह वही शुभांशु रह गए हैं, जो एक्सिओम-4 मिशन से पहले थे? नहीं! उनके पास अब ऐसे अनुभव हैं, जो उन्हें अरबों की भीड़ से अलग कर देते हैं। इसरो के वैज्ञानिक उनके प्रयोगों-अनुभवों से अंतरिक्ष में आगे की राह तलाशेंगे।

भारतीय अंतरिक्ष अभियान के लिए शुभांशु की इस यात्रा का महत्व इस एक तथ्य से पता चल जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस अभियान के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये का योगदान किया है। उसकी भविष्य की योजनाओं में इस अभियान से अर्जित तथ्य बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। खासकर गगनयान अभियान को इससे बहुत बल मिलेगा। इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेखांकित किया है। शुभांशु को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस और उत्साह से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है और यह हमारे गगनयान की यात्रा की दिशा में मील का पत्थर है।

अब यह वही शुभांशु नहीं हैं, जो एक्सिओम-4 मिशन से पहले थे। उनके पास अब ऐसे अनुभव हैं, जो उन्हें अरबों की भीड़ से अलग कर देते हैं।

निस्संदेह, अगले कई दिनों तक इस युवा वैज्ञानिक के प्रयोगों और अनुभवों पर बहुत कुछ कहा-लिखा जाएगा, मगर आवश्यकता देश के शुभांशुओं को पहचानने, उन्हें सुविधाएं देने और प्रोत्साहित करने की है। तब तो और, जब हमने साल 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने का संकल्प लिया है। बताने की जरूरत नहीं कि इसके लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठतम मस्तिष्क और प्रदर्शन की दरकार होगी। हमारी तरक्की से ईर्ष्या रखने वाले कुछ पड़ोसी देश जिस तरह की दुरभिसंधि रच रहे हैं, इसे देखते हुए अपनी सरहदों की चाक-चौबंद निगरानी के लिए हमें उन्नत सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात करने होंगे। सरकार ने हाल ही में लगभग 50 विशेष रक्षा सैटेलाइट तैनात करने का एलान भी किया है। शुभांशु की इस उपलब्धि से लाभ उठाते हुए हमें देश में एक वैज्ञानिक माहौल बनाना चाहिए। दुर्योग से पिछले कुछ समय में यहां तर्क और वैज्ञानिक चेतना से जुड़े विमर्शों के बजाय कट्टरपंथ की घटनाओं ने कहीं अधिक सुर्खियां बटोरी हैं। यहां विवाद सैकड़ों साल पुराने इतिहास के मुद्दों पर खड़े किए जा रहे हैं, जिनका विकसित राष्ट्र या समाज बनाने में कोई योगदान नहीं होने वाला। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुकाबला किन आर्थिक-वैज्ञानिक ताकतों से है। इसलिए, राष्ट्रीय और सामाजिक एकता के लिहाज से भी वैज्ञानिक सोच को अधिकाधिक बढ़ावा देने में भलाई है। शुभांशु शुक्ला की सफलता पर हर्षित देश का यही संकल्प होना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 16 जुलाई, 1950

कोरिया में रूसी पलड़ा भारी

अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र पर दृष्टि डालते ही हमारी आंख सब से पहले कोरिया की ओर उठती है, जहां आज भी अमरीकी और रूसी सिद्धांतों का विरोध शस्त्र बल से सुलझाया जा रहा है। अंतिम विजय किसकी होगी, अभी से यह बता सकना कठिन है, किन्तु मोर्चों से प्राप्त हुए समाचारों से स्पष्ट है कि पलड़ा अभी रूस का ही भारी है।

यह आश्चर्य की बात है कि अमरीका-जैसा साधन और शक्ति सम्पन्न देश छोटे-से उत्तरी कोरिया के आगे पीठ दिखाता चला आ रहा है। सुवोन में अमरीकी सेनाओं की जैसी छीछालेदर हुई, सबको पता है। उसके बाद उन्होंने जो पीछे भागना शुरू किया, वह अब तक जारी है और युद्ध दक्षिणी कोरिया की अस्थायी राजधानी ताएगोन के द्वार खटखटा रहा है। अमरीका कई बार घोषणा कर चुका है कि उसकी सेनाएं ताएगोन से पीछे नहीं हटेंगी और कुछ दिनों में ही नई कुमुक और युद्ध-सामग्री पहुंच जाने से वे इतनी शक्तिशाली हो जायेंगी कि शत्रु पर प्रत्याक्रमण कर उसे 38 अक्षांश के पार तक खदेड़ा जा सकेगा।

किन्तु वर्तमान गति-विधि को देखते हुए यह बात कुछ अटपटी ही मालूम होती है। सबसे ताजे समाचारों से पता चला है कि साम्यवादी सेनाओं ने कुम नदी के सहारे अमरीकियों की अंतिम रक्षा-पंक्ति को भी भंग कर दिया है और भारी प्रतिरोध के बावजूद वे एक स्थान पर अपनी चौकी स्थापित करने तथा सेनाएं नदी के पार उतारने में सफल हो गयी हैं। ताएजोन पर किसी भी क्षण उनका अंतिम प्रहार हो सकता है।...

यह माना कि अमरीका के सामने अनेक कठिनाइयां हैं। साम्यवादियों के मुकाबले में उसकी सेनाओं की संख्या बहुत कम है और एक सुदूर देश में युद्ध होने के कारण वहां युद्ध-सामग्री पहुंचाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; पर इस सब के बावजूद अमरीकी सेनाएं कोरिया में अधिक कौशल का परिचय दे सकती थीं। वायुसेना भी, जिस पर अमरीका को इतना नाज था, साम्यवादियों की प्रगति को रोकने की बात तो दूर, उसे धीमी तक करने में असफल रही है। अमरीकी सैनिकों का साहस काफी गिर चुका है। शत्रुओं की पहुंच का समाचार ही उनकी भगदड़ के लिए पर्याप्त कहाना है। ऐसी स्थिति में क्या कोरिया में अमरीकी अभियान सफल हो सकेगा?

मतदाता सूची को सावधानी से सुधारें

यहां स्कैन करें

ओपी रावत | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

बिहार में सुधारों का काम विवादों में घिर गया, क्योंकि इसे विधानसभा चुनाव के बिल्कुल करीब जल्दबाजी में शुरू किया गया, जबकि यह कवायद पर्याप्त समय मांगती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने की चर्चा जोरों पर है। अगर ऐसी कुछ योजना है, तो इसका अवश्य स्वागत किया जाना चाहिए। आखिरकार पिछले देशव्यापी मतदाता गहन पुनरीक्षण के 22 साल बीत चुके हैं। हालांकि, इससे पहले बिहार में वह इस किस्म कार्य के सबक आयोग को जरूर याद रखने चाहिए।

बिहार का पुनरीक्षण अभियान इसलिए विवादों में घिर गया, क्योंकि इसे विधानसभा चुनाव के करीब आने पर आनन-फानन में शुरू किया गया है, जबकि यह कवायद पर्याप्त समय मांगती है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य साल 2003 में हुआ था, जबकि विधानसभा चुनाव 2005 में हुए थे। मतदाताओं को वक्त देने से होता यह है कि यदि किसी कारणवश किसी वोटर का नाम प्राथमिक सूची में नहीं आता, तो वह उचित व्यवस्था के तहत अपील कर सकता है। मगर अभी यह शायद ही संभव हो सकेगा।

दूसरी बात, यह काम जल्दबाजी में तभी हो सकता है, जब ऊपर से नीचे तक पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था हो। मगर अपने देश में कर्मचारियों, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के क्षमता-विकास के लिए सरकारों ने पर्याप्त काम नहीं किए हैं। नतीजतन, इन कर्मियों से हम शत-प्रतिशत सटीक योगदान की अपेक्षा नहीं कर सकते। फिर भी, यदि इसे आनन-फानन में करने की मजबूरी थी, तो आयोग को सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और सभी पार्टियों की सहमति लेनी चाहिए थी। मगर यह भी नहीं किया गया।

आयोग दावा कर रहा है कि 80 फीसदी फॉर्म उसके पास आ गए हैं और बीएलओ, यानी बूथ लेवल अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, पर वास्तव में बिहार के कुल 70 से 75 हजार बीएलओ में महज 200-300 प्रशिक्षित हैं। यानी, 'इंडियाइंटरनेशनलइंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ऐंड इलेक्शन मैनेजमेंट' से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों की संख्या काफी कम है। इन चंद बीएलओ के दम पर तमाम अधिकारियों से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा रखना उचित नहीं होगा।

इस पूरे अभियान के लिए जरूरी तैयारियां भी शायद ही की गई थीं। जैसे, 24 जून को पुनरीक्षण अभियान का आदेश जारी किया गया, और मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन और आपत्ति निराकरण की तारीख बता दी गई। मगर मामला तब उलझ गया, जबइसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की इस याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को आधार माना है और जिन-जिन वोटरों के नाम 2003 के बाद सूची में जुड़े हैं, उनकी अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ऐसे लोगों की संख्या करीब तीन करोड़ है। जाहिर है, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन में आयोग पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल नहीं कर सकता था, जबकि करीब आठ करोड़ मतदाता हैं यहां।

हालांकि, सवाल यह भी था कि नागरिकता की पहचान करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा था कि नागरिकता गृह मंत्रालय के अधीन है। लिहाजा, बाद में प्रमाण-पत्रों की बाध्यता को टालना ही आयोग ने बेहतर समझा। इतना ही नहीं, उसने साल 2023 में आधुनिक तकनीक की मदद से देश भर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया था और उन नामों को हटा दिया था, जो दो या अधिक बार या गलत तरीके से जोड़े गए थे। इसी कारण संभवतः पहली बार मतदाताओं की संख्या कम हो गई थी और 2022 में कुल 95.24 करोड़ वोटरों की तुलना में 2023 में 95.06 करोड़ वयस्क मतदाता-सूची का हिस्सा रह बचे थे। ऐसे में, अभी वही काम फिर करने की बाध्यता भी सवालों में है?

जाहिर है, इस कवायद को देश भर में लागू करने से पहले चुनाव आयोग को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना होगा। सर्वप्रथम उसे सभी पार्टियों की एक बैठक बुलानी चाहिए और यह बताना चाहिए कि ऐसे अभियान की जरूरत क्यों है? उनको भरोसे में लेना चाहिए। इन पार्टियों में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा क्षेत्र के बड़े दलों को भी बुलाना चाहिए, जैसे, द्रमुक (तमिलनाडु), तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल), समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश), सीपीएम (केरल) आदि।

इतना ही नहीं, यह अभियान समय लेकर शुरू करना चाहिए, ताकि किसी कारणवश कोई मतदाता यदि सूची का हिस्सा नहीं रहता, तो उसे इतना वक्त मिले कि पूरी प्रक्रिया के तहत वह अपना नाम फिर से जुड़वा सके। बिहार में ही 30 सितंबर की समय-सीमा रखी गई है, जबकि चुनाव अक्तूबर-नवंबर में संभावित हैं, इसलिए किसी मतदाता का नाम सूची से कटने पर उसे दावा करने या उसके निपटारे का शायद ही वक्त मिलेगा!

सुखद है, इन सब कामों में बजट कभी आड़े नहीं आता। अभी ही, जब 'एक देश, एक चुनाव' की चर्चा तेज है, तब चुनाव आयोग को इसके लिए करीब 50 लाख ईवीएम और लगभग इतने ही वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी, जबकि उसके पास अभी करीब 25 लाख ईवीएम और 30 लाख के लगभग वीवीपैट मशीनें हैं। जाहिर है, इन मशीनों के लिए आयोग को पैसों की जरूरत होगी, जो उसे मिल जाएगी। ऐसे में, उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी चुनाव-प्रक्रिया में इतनी पारदर्शिता रखेगा कि किसी को कोई शक न हो।

कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि जब 'एक देश, एक चुनाव' हो रहा है, तो एक मतदाता सूची क्यों नहीं? अभी लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए एक मतदाता सूची का इस्तेमाल होता है, जबकि पंचायत और नगर निकायों के लिए दूसरी। मगर इनमें शायद ही अंतर होता है, क्योंकि लोकसभा व विधानसभा चुनावों की मतदाता सूचियों को ही पंचायत व निकाय चुनावों के लिए वार्ड के हिसाब से बांटा जाता है। चूंकि वार्ड के हिसाब से पंचायत या निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, इसलिए कभी-कभी किसी मतदाता का नाम विधानसभा या लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची में होता है, पर पंचायत या निकाय चुनावों की मतदाता सूची में नहीं।

अच्छी बात यह भी है कि पहले संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम 1 जनवरी की तारीख तक होता था, यानी 1 जनवरी को 18 साल पूरा करने वाला मतदाता वोट डालने के योग्य माना जाता था, पर अब चार तारीखें तय कर दी गई हैं- 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर। लिहाजा, लोगों के पास मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाने के अब कई मौके हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी से उपजी उम्मीदें

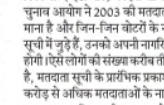

यहां स्कैन करें

संजय बनर्जी | रिटायर्ड कर्नल

पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ जब भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया, तो हमारी मिसाइलों, ड्रोनों व मानवरहित लड़ाकू विमानों ने न केवल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने तबाह किए, बल्कि अग्रिम पंक्ति के कई पाकिस्तानी हवाई अड्डों को भी ध्वस्त किया। जब उसने अपने ड्रोन, मिसाइलों और विमानों से जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, तो भारतीय वायु सेना की रक्षा व ड्रोन-रोधी प्रणालियां बेहतर साबित हुईं और हरेक पाकिस्तानी हमलों को उन्होंने नाकाम कर दिया।

मगर इस पूरे संघर्ष में जिस एक बात ने पाकिस्तान को हताशा से भर दिया और दुनिया भर को चौंकाया, वह थी- भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार। इनमें से ज्यादातर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, वायु रक्षा व ड्रोन-रोधी प्रणालियां 'मेड इन इंडिया' (स्वदेशी) थीं। रक्षा उत्पादन में हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी तरक्की ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। यह सभी जानते हैं कि आधुनिक युद्ध अब बहुत हद तक उच्चतम गुणवत्ता वाले हथियारों की उपलब्धता और तैनाती पर निर्भर करता है, जिसमें प्रभावी निगरानी प्रणाली, हवाई सुरक्षा प्रणाली और ड्रोन-रोधी प्रणाली शामिल हैं।

निजी उद्योगों के जरिये अपने सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक प्रतिभाओं को देश में रोके रखने में हमें सहायता मिलेगी।

अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेना और मित्र देशों की फौजों को गोला-बारूद, उपकरण व सैन्य भंडार उपलब्ध कराने के लिए जिन आयुध कारखानों की स्थापना भारत में की थी, आजादी के बाद वे सब हमारे पास ही रहे। हाल-हाल तक आयुध निर्माणी बोर्ड के तहत ये कारखाने पिस्तौल और राइफल जैसे छोटे हथियार, सैन्य जीप व ट्रक जैसे वाहन, टैंक, तोप जैसे बख्तरबंद वाहन और विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद व विस्फोटक एवं सैन्य उपकरणों का उत्पादन करते थे। आजादी के शुरुआती वर्षों में उपकरण, हथियार व गोला-बारूद आयात करने के लिए रूस (पूर्व सोवियत संघ), फ्रांस, स्वीडन और कुछ अन्य देशों को प्राथमिकता दी गई, जिन्होंने हमें तकनीक मुहैया कराने के साथ-साथ हमारे लोगों को प्रशिक्षित किया और यहां तक कि भारत-भूमि पर उत्पादन में भी उन्होंने हमारी मदद की। हालांकि, भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति पर अडिग रहा, पर रूस ने संकट की स्थितियों में हमारी मदद की है। हमने रूस के साथ अत्यंत प्रभावी ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है, जो हमारे दुश्मनों के लिए ईर्ष्या का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने निर्धारित लक्ष्यों पर अचूक निशाना साधकर कमाल कर दिया।

मगर युद्धक साजो-सामान के मामले में आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों की विफलताएं, हमारे लिए एक बड़ा सबक है कि रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में हमें तेजी से कदम उठाना चाहिए। जो विशेषज्ञता हम अपनी रक्षा-प्रणालियों को विकसित करके हासिल कर सकते हैं, वह विदेशी मूल के उत्पादों से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि भारत इसे नहीं समझता। क्योंकि से हम अपने युद्धक टैंक, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, तोप, मिसाइल और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण डिजाइन और निर्माण करने का प्रयास करते रहे हैं। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख रहते समय हमने नाग, आकाश, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के निर्माण में सफलता पाई है।

ऐसे में, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक स्वागतयोग्य कदम है और इससे इस क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगी। निजी रक्षा उत्पादन उद्योग के जरिये हमारे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग व वैज्ञानिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें देश में रोके रखने में सहायता मिलेगी, जिसका सुफल अनुसंधान, विकास और उत्पादन में हमें प्राप्त होगा। जाहिर है, स्वदेशी उत्पाद न केवल हमारी अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि मित्र देशों को रक्षा उपकरणों के निर्यात से हमें अच्छी कमाई भी करा सकते हैं। रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अग्रणी निजी कंपनियों के साथ स्टार्टअप का सहयोग लेकर हमें रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। और इसके लिए हमें चीन, रूस, अमेरिका और अन्य विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सत्य का प्रचार ऐसे करें

अध्यात्म नितांत व्यक्तिगत विषय है, पर आध्यात्मिक गुरु सदा विश्व-कल्याण की बात करते हैं। क्यों?

दरअसल, सामूहिक कल्याण शिव है। अतः सामूहिक कल्याण का प्रचार शिवत्व की महानता से भरा हुआ होता है और इसीलिए आध्यात्मिक गुरु के लिए यह अनिवार्य है। सामूहिक कल्याण का उनका दृष्टिकोण, बल्कि सभी प्रवृत्तियां सत्य की ओर लक्षित होती हैं, क्योंकि केवल सत्य के प्रचार से सामूहिक कल्याण संभव है। सत्य और शिव आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक-दूसरे के बिना न कोई खड़ा हो सकता है और न ही किसी को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य वह है, जिसके पालन से आप कल्याण की ओर बढ़ेंगे और अंततः आप परम पुरुष से, जिन्हें ऋषियों द्वारा कल्याण-सुंदरम् के नाम से पुकारा गया है, एक हो जाएंगे। जहां सत्य का प्रचार नहीं होता, वहां लोग व्यक्तिगत या समूह-स्वार्थ में लिप्त होते हैं। वहां का उद्देश्य सामूहिक कल्याण से प्रेरित नहीं होता।

अनेक देशों में उच्च आदर्शों का प्रचार कई-कई बार किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस प्रचार ने सत्य की स्थापना में कितना योगदान दिया है? अधिकांश उपदेशक प्रचार-कला में निपुण थे, प्रचार विज्ञान में अनुभवी हाथों की भी कोई कमी नहीं थी, फिर भी जब आकर्षण क्षण भर में समाप्त हो गया, और लोगों ने यह महसूस किया कि उन्हें सत्य का कोई अनुभव नहीं हुआ, तो उन्होंने उन उपदेशकों के नाम को इतिहास के पन्नों से तिरस्कार के साथ हटा दिया। इसलिए, आप केवल सत्य का प्रचार करें। जो कुछ आपने किया है, उसे कारण सहित समझाएं। स्पष्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं?

यही नहीं, सत्य का प्रचार करते हुए आप कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। जब लोग सत्य के आदर्श को महसूस करेंगे और आपकी कर्म-साधना को जानेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी इज्जत करने लगेंगे। यहां तक कि निजी जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, तब भी आपको कोमलता से उसे उसकी जिम्मेदारियां समझानी चाहिए। मगर ऐसे मामलों में आपका व्यवहार मित्रवत हो, न कि शिक्षक जैसा। आपका एकमात्र उद्देश्य उसे अपनी सलाह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने का होना चाहिए। यह विचार कि वह मूर्ख है और आप ज्ञानी, किसी भी तरह से उचित नहीं।

सामूहिक कल्याण शिव है। अतः सामूहिक कल्याण का प्रचार शिवत्व की महानता से भरा हुआ होता है और इसीलिए आध्यात्मिक गुरु के लिए यह अनिवार्य लक्ष्य है।

आध्यात्मिकता का तकाजा यह है कि आपको अपने सभी सार्वजनिक संपर्क साधनों को सत्य के प्रचार में लगा देना चाहिए। प्रचार करते समय आपको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप उपदेश दे रहे हैं, वह इसे उसी तरह समझने की क्षमता रखता है, जैसे आप इसे स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री श्री आनंदमूर्ति

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप काम करके हम टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि, इससे जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक, अभी 35 प्रतिशत ही काम हुआ है। प्रगति संभव है, हमें तत्परता, एकता और संकल्प के साथ कार्य करना होगा।

अनुलोम-विलोम

एअर इंडिया हादसा

गले नहीं उतर रही शुरुआती जांच-रिपोर्ट

अहमदाबाद की दिल दहला देने वाली हवाई दुर्घटना की प्रारंभिक जांच-रिपोर्ट किसी के गले नहीं उतर रही। यह 15 पन्नों की रिपोर्ट प्रारंभिक है, अंतिम नहीं। हो सकता है कि अगली रिपोर्ट में दुर्घटना का वास्तविक व अंतिम सत्य सामने आ जाए। मगर इस रिपोर्ट से तो यही जाहिर होता है कि लीपापोती करने का प्रयास किया गया है। इसमें पायलटों के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया गया है, जबकि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं और अपनी सफाई भी नहीं दे सकते। वैसे भी, वे दोनों कोई पहली बार विमान नहीं उड़ा रहे थे। उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का अच्छा-खासा अनुभव था। निस्संदेह, मानवीय भूल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पायलट इतनी बड़ी गलती शायद ही कर सकते हैं। इंजन को ईंधन की सप्लाई करने वाले स्विच का बंद होना साजिश भी हो सकती है। कहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से विमान संचालन से जुड़ी कंपनी और जो इस विमान के इंजन व अन्य कल-पुर्जे बनाते हैं, उनको बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? विमान के सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ करने की आशंकाएं भी विशेषज्ञ जता रहे हैं। ऐसे में, इस हादसे के अंतिम सत्य को पूरा देश जरूर जानना चाहेगा। यदि यह जांच-रिपोर्ट यहीं तक सीमित रह जाती है, तो यही समझा जाएगा कि लीपापोती हुई है, क्योंकि दांव पर बड़ी विमानन कंपनी और उसके कर्णधार हैं।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

एअर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच-रिपोर्ट कई ऐसे अहम सवालों की अनदेखी करती है, जो इस हादसे की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। एअर इंडिया की तरफ से कहा गया कि विमान में कोई 'मैकेनिकल या मेंटनेंस की खराबी' नहीं थी, जो पूर्व निश्चित निष्कर्ष जान पड़ता है। जब हादसे में पायलटों की जान गई हो, तब इस तरह के बयान सवालों के घेरे में आ जाते हैं। आखिर किस आधार पर इतनी जल्दी तकनीकी खामियों से इनकार किया गया, जबकि जांच अभी शुरुआती चरण में ही है? जांच एजेंसियों का काम हर पहलू की निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है, लेकिन लगता है कि शुरुआती जांच-रिपोर्ट में इसकी अनदेखी की गई है। बोइंग विमानों को लेकर पहले भी तकनीकी और डिजाइन से जुड़ी चिंताएं सामने आती रही हैं, इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि इस दुर्घटना की जांच पूरी ईमानदारी से की जाए। जांच-रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदारियां तय करना होता है, वरना वह महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस बार ऐसा ही होता दिख रहा है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता

अहमदाबाद विमान हादसे (12 जून, 2025) की प्रारंभिक जांच-रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे अपूर्ण या पक्षपातपूर्ण मान रहे हैं। हालांकि, यह कहना कि रिपोर्ट 'झूठी' है, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह प्रारंभिक है और अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है। हमें तथ्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्थिति समझनी चाहिए।

आखिर रिपोर्ट में क्या कहा गया है? 15 पन्नों का यह दस्तावेज बताता है कि विमान के दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति अचानक बंद हो गई थी, जिसके कारण टेकऑफ के 32 सेकंड बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईंधन आपूर्ति इसलिए बंद हो गई, क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच 'रन' से 'कटऑफ' हो गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों या कैसे हुआ? कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (क्लैक कॉकपिट का हिस्सा) में एक पायलट का सवाल दर्ज है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? लेकिन दूसरे पायलट ने इससे इनकार किया। पूरी रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे संदेह बढ़ा है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी क्षतिग्रस्त था, जिससे डाटा निकालना मुश्किल हुआ। इन सबसे पायलटों पर दोषारोपण की बात काटी जाने लगी है। इसे पायलट यूनियनों और विशेषज्ञों ने पक्षपातपूर्ण बताया है। मार्को चान और संजीव कपूर जैसे विशेषज्ञों ने कहा है कि फ्यूल स्विच गलती से बंद होना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें सेफ्टी लॉक होता है। पूरी ट्रांसक्रिप्ट न होने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

फिर भी क्या रिपोर्ट झूठी है? ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट का उद्देश्य केवल तथ्य प्रस्तुत करना है, न कि अंतिम निष्कर्ष देना। हालांकि, यह अधूरी और अस्पष्ट है, जिसके कारण संदेह पैदा हुआ है। विशेषज्ञों और पायलट यूनियनों का मानना है कि जांच की दिशा पक्षपातपूर्ण हो सकती है, खासकर बोइंग और एअर इंडिया को बचाने के लिए। कुछ लोग सिस्टम की लापरवाही (जैसे घिसे टायर, धुंधली रनवे लाइनें) की बात भी उठा रहे हैं, लेकिन ये दावे प्रारंभिक रिपोर्ट से नहीं जुड़े। ऐसे में, यह समझना उचित होगा कि अंतिम रिपोर्ट अगले एक-दो साल में आने की संभावना है, जिसमें हादसे की असल वजह स्पष्ट हो सकती है। फिर, जांच में तकनीकी खराबी, मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी और मानवीय भूल जैसे सभी पहलुओं की गहन छानबीन भी की जाएगी। इसमें बोइंग के दावों पर भी गौर किया जाएगा। ऐसे में, रिपोर्ट को 'गलत' कहने या पूरी तरह खारिज कर देने के बजाय अपूर्ण और अस्पष्ट कहना ज्यादा उचित है। हमें अंतिम निष्कर्ष के लिए और जांच का इंतजार करना चाहिए।

राम प्रसाद शर्मा, टिप्पणीकार

जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, जो इसका आनंद उठाते हैं, उन्हें नहीं, जो केवल सत्ता के लिए इसकी चाह रखते हैं। -मैल्कम फोर्ब्स

बालासोर की बीस वर्षीय बीएड छात्रा की मौत कॉलेज प्रशासन की घनघोर लापरवाही को उजागर करने के साथ बेटियों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन देने में हमारी नाकामी को भी दर्शाती है। पीड़िता को तो नहीं बचाया जा सका, पर दोषियों को कठोर दंड मिले, ताकि बाकी बेटियों में सुरक्षा का संदेश जा सके।

न्याय की अनसुनी पुकार

ओडिशा के बालासोर में एक बीस वर्षीय बीएड छात्रा का यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने से व्यथित होकर आत्मदाह करना और फिर अस्पताल में जिंदगी की जंग हार जाना हृदयविदारक तो है ही, यह घटना एक बार फिर समाज और व्यवस्था की उन गहरी खामियों को उजागर करती है, जिनकी वजह से हमारी बेटियां सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन पाने में नाकाम रहती हैं। बालासोर के फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की यह छात्रा पिछले कई महीनों से अपने विभागाध्यक्ष के कथित उत्पीड़न का शिकार थी। उसने कॉलेज प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दीं, लेकिन उसकी पुकार अनसुनी रही। नतीजा यह हुआ कि हताशा और निराशा में उसने बारह जुलाई को कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली। 95 फीसदी जलने के बावजूद, वह जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन आखिरकार हार गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी अभी जेहन से मिटी भी नहीं थी, कि अब ताजा मामले में बालासोर में कॉलेज प्रशासन की ऐसी घनघोर लापरवाही हैरत में डालने वाली है। विद्या के मंदिर कहे जाने वाले शैक्षिक संस्थानों में इस तरह की वारदात बार-बार होना भी उतना ही दुखद है। सवाल उठता है कि आखिर एक छात्रा को अपनी बात कहने के लिए खुद को आग के हवाले करने की नौबत ही क्यों आई? क्या उसे कोई और रास्ता दिया गया था? क्या हमारी पुलिस और कॉलेज प्रबंधन इतने निष्क्रिय हो चुके हैं, कि वे पीड़िता की पुकार तक नहीं सुन सके? यह घटना हमें कई सबक देती है। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर शैक्षिक संस्थान में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नीतियां हों और संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी हो, ताकि हर पीड़िता को यह भरोसा मिल सके कि उसकी आवाज सुनी जाएगी। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने होंगे, जिनमें प्रशासनिक हस्तक्षेप की गुंजाइश न हो। साथ ही, प्राचार्यों और कॉलेज प्रशासकों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण देना होगा, ताकि वे ऐसी शिकायतों को गंभीरता से ले सकें। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न के मामलों में समयबद्ध जांच और सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। कुल मिलाकर, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जहां किसी भी बेटी को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए इतनी भारी कीमत न चुकानी पड़े। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि हम बेटियों को ऐसा समाज दें, जहां वे बगैर डर के अपने सपनों को पूरा कर सकें। पीड़िता को न्याय तो अब हम क्या ही दिलाएंगे, लेकिन दोषियों को कठोर दंड देने से समाज में एक मजबूत संदेश तो जाएगा ही।

जीवन धारा

ब्लेज पास्कल

अपने मन के सवालों से भागने के बजाय उनका सामना करना ज्यादा जरूरी है। स्वयं से पूछें कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों हैं। ये सवाल हमें असहज करेंगे, पर यही हमें सच्चाई के करीब ले जाएंगे।

कमजोरियां ही हमारा सच्चा दर्पण हैं

इन्सान अपने आप में एक पहेली है। जिन रहस्यों का हम सामना करते हैं, वे आकाश में छिपे हैं या ब्रह्मांडीय धूल में गहरे दबे हैं। सबसे बड़े रहस्यों में से एक हमारे भीतर है। इन्सान के जीवन में सबसे बड़ी ताकत उसके सोचने का तरीका है, पर यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम सोचते हैं, सवाल उठाते हैं और जवाबों की तलाश में भटकते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि यह भटकना ही जिंदगी का मकसद हो सकता है?

जिंदगी का सच यह है कि यह अनिश्चितता से भरी है। हम सुबह उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर क्या हम सचमुच समझते हैं कि हम यहां क्यों हैं? इन्सान का दिल एक अनंत खालीपन से भरा है, जिसे केवल ईश्वर ही भर सकते हैं। हम इन्सान अजीब प्राणी हैं। हम न तो पूरी तरह स्वर्गदूत हैं, न ही पूरी तरह जानवर। हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, पर हमारा शरीर हमें धरती की ओर खींचता है। इस द्वंद्व में हमारी जिंदगी बीत जाती है। इस द्वंद्व को स्वीकार करना चाहिए। मन में कड़ी कि हम ऊंचाइयों को छूकर ही रहेंगे। इसे अपनी ताकत बनाओ। अपनी कमजोरियों को समझो, क्योंकि यही वह दर्पण है, जिसमें हम अपनी सच्चाई देख सकते हैं।

जिंदगी में सुख की तलाश हर इन्सान करता है, पर सुख क्या है? क्या वह धन में है, शोहरत में, या फिर क्षणिक आनंद में? लोग सुख की तलाश में भागते हैं, पर जैसे ही उन्हें लगता है कि वे उसे पकड़ चुके हैं, वह उनके हाथ से फिसल जाता है। सच्चा सुख उस शांति में है, जो हमें तब मिलती है, जब हम अपने आप को, अपने उद्देश्य को और उस अनंत शक्ति को समझ लेते हैं, जो इस सृष्टि को चलाती है। सारी दुखदायी चीजों का कारण यह है कि इन्सान यह नहीं जानता कि अकेले में कैसे शांति से रहा जाए।

कई बार हम जिंदगी की सतह पर ही जीते हैं। हम व्यस्तता में डूब जाते हैं, ताकि हमें अपने भीतर झांकने का समय न मिले। अपने लिए समय निकालें। अपने मन के सवालों से भागने के बजाय उनका सामना करना ज्यादा जरूरी है। स्वयं से पूछें कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों हैं। यह सवाल हमें असहज करेंगे, पर यही हमें सच्चाई के करीब ले जाएंगे। इन्सान की महानता इस बात में है कि वह अपनी सीमाओं को जानने का प्रयास करे और यही हमारे जीवन की आकार देगा। विश्वास और तर्क, ये दोनों जिंदगी के दो पहलू हैं। तर्क हमें बहुत कुछ समझा सकता है, पर वह हमें हर जवाब नहीं दे सकता। कुछ सवालों के जवाब दिल से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं। ईश्वर को समझने के लिए हमें अपने दिल को खोलना होगा। जिंदगी छोटी है, इसे बुद्धिमानी से जियो। अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए प्यार और करुणा रखो। अपने अंदर की उस चिंगारी को जलाए रखो, जो तुम्हें अनंत की ओर ले जाती है।

सवालों का सामना करें

इन्सान एक सोचने वाला प्राणी है। यह सोचना और विचारना ही उसे इस सृष्टि का सबसे अनमोल हिस्सा बनाता है। इसलिए मन में उठने वाले विचारों और उनसे उपजे सवालों से डरने की कतई जरूरत नहीं है। जिंदगी के सवालों का सामना करो और अपने दिल की गहराइयों में उतरो। वहां हमें वह सच्चाई मिलेगी, जो हमें मुक्त करेगी।

सूत्र

जब एक पुल टूटता है, जैसा कि गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता और अनगिनत जगहों पर हुआ, तो यह लोगों के भरोसे को भी तोड़ता है। पुल ढहने या कोई सड़क धंसने के चक्र को तोड़ने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे की उपेक्षा के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाना होगा।

जब एक पुल टूटता है

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

गुजरात में वडोदरा के नजदीक नौ जुलाई को गंभीरा पुल का टूटना, जिसमें करीब 20 लोगों की मौत हो गई, भारत के आधारभूत ढांचे की उपेक्षा की दुखद गाथा का एक ताजा अध्याय है, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता उजागर हुई, जो सुरक्षा की अपेक्षा दिखावे को प्राथमिकता देती है। ऐसे में, शोक-संवेदना व्यक्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह तीखे सवाल पूछने का वक्त है। यह दुर्घटना एक विनाशकारी पूर्वानुमान के साथ सामने आई है, जो विफलताओं की भयावह सूची में शामिल हो गई है। 2022 में गुजरात में मोरबी पुल का गिरना, 2016 में महाराष्ट्र का महाड पुल हादसा और 2016 में कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर का ढहना-ये सभी हादसे नौकरशाही की निष्क्रियता और आम लोगों के प्रति राजनीतिक उदासीनता की कड़वी यादें दिलाते हैं।

चार दशक पुराने गंभीरा पुल पर हादसे का इंतजार किया जा रहा था। स्थानीय निवासी लंबे समय से चेता रहे थे कि वाहनों के गुजरने पर गंभीरा पुल हिलता है और मोरबी हादसे के बाद भी ऐसी चेतावनी दी गई थी। मोरबी की तरह गंभीरा पुल की जर्जरता किसी से छिपी नहीं थी। स्थानीय भाजपा विधायक चैतन्य सिंह झाला की अनुशंसा पर गुजरात सरकार ने नया पुल बनाने की स्वीकृति दी। सर्वेक्षण किए गए, डिजाइन तैयार हुए, फिर भी जीर्ण-शीर्ण संरचना को खुला रखा गया और सतही मरम्मत की गई। जर्जर पुल पर यातायात की अनुमति देने का निर्णय लापरवाही को ही दर्शाता है।

हालिया घटना गंभीर सवाल खड़े करती है : गंभीरा पुल को बंद क्यों नहीं किया गया था? यही सवाल मोरबी हादसे के बाद पूछा गया था, जहां निजी ठेकेदार द्वारा किए गए घटिया रखरखाव पर कोई बंदिश नहीं थी। महाड पुल हादसे के बाद भी ऐसे ही सवाल उठे थे। इनके जवाब प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक सुविधाबाद के घातक संयोजन में निहित हैं। पुल बंद करने पर व्यापक प्रभावित होता और जनता नाराज हो सकती थी-ये ऐसे विचार हैं, जो अल्पकालिक दृष्टिकोण से संचालित प्रणाली में सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

वर्ष 2023 में मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की सड़क धंसने से उसमें एक बस समा गई और यात्रियों को चोटें आई थीं, जबकि 2024 में ऐसा ही हादसा दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में हुआ, जिससे कई दिनों तक यातायात बाधित रहा था। पुल ढहने जैसी ये घटनाएं रखरखाव की लापरवाही और चेतावनियों की अनदेखी को उजागर करती हैं।

भारत में बुनियादी ढांचे का संकट प्रणालीगत है। वर्ष 2017 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 6,500 से ज्यादा पुल 'क्षतिग्रस्त' अवस्था में थे, इनमें सौ साल से भी अधिक पुराने 20 पुलों को तत्काल बंद किया गया। पिछले साल मंत्रालय की ओर से लोकसभा में बताया गया कि 'पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दृश्य और उपकरण-आधारित आवधिक निरीक्षण, मूल्यांकन और निगरानी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न घटकों की संरचनात्मक अखंडता समय पर मरम्मत/पुनर्वास हस्तक्षेप के माध्यम से बनाए रखी जाए।'

मोरबी के झूला पुल या कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर की तरह गंभीरा पुल के बारे में भी पहले से संकट की जानकारी थी। गंभीरा पुल में होने वाला कंपन उतनी ही बड़ी चेतावनी थी, जितनी कि मुंबई की सड़कों के धंसने से पहले आई दरारें। इसका मुख्य कारण कम लागत है। भारत का तीजी से होता शहरीकरण आधुनिक बुनियादी ढांचे की मांग करता है, लेकिन हल्के भार के लिए बने गंभीरा जैसे पुलों का पर्याप्त पुनर्निर्माण शायद ही कभी किया जाता है। मुंबई की सड़कें अक्सर पुरानी जल निकासी प्रणालियों के कारण धंस जाती हैं, जो उपेक्षा को दर्शाती हैं। घटिया निर्माण, बेतरतीब रखरखाव और भ्रष्टाचार इन त्रासदियों में योगदान देते हैं।

मोरबी के बाद की जांच में लापरवाहीपूर्ण निगरानी को दोषी ठहराया गया, फिर भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। गंभीरा हादसे की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, लेकिन आशंका है कि पहले की तरह इसकी रिपोर्ट भी दबा दी जाएगी और जिम्मेदार अधिकारी बच निकलेंगे। राज्य सरकार ने हादसे के तत्काल बाद मुआवजे का एलान कर दिया, ताकि लोगों का ध्यान प्रणालीगत सुधारों से भटक जाए और मौद्रिक महरम-पट्टी पर चला जाए।

राहत की अपेक्षा दिखावे को प्राथमिकता देने की संस्कृति सर्वव्यापी है। मोरबी पुल की तरह गंभीरा पुल को खुला रखने से असुविधा थी तो बचा गया, लेकिन इससे जीवन खतरे में पड़ गया। यह सिर्फ उपेक्षा भर नहीं है, बल्कि नैतिक पतन भी है, जो मुंबई और दिल्ली में सड़क धंसने की घटनाओं में दोहराई गई, जहां स्थानीय लोगों की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस चक्र को तोड़ने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे की उपेक्षा के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाना होगा। सक्रिय रखरखाव-नियमित निरीक्षण, पारदर्शी रिपोर्टिंग और असुरक्षित ढांचों को तत्काल बंद करने पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रियल टाइम ब्रिज सेंसर जैसी तकनीकें, जिनका वैश्विक स्तर पर उपयोग हो रहा है, पुलों के ढहने से पहले के जोखिम के प्रति सचेत कर सकती हैं। इसके साथ ही सड़कों को धंसने से बचाने के लिए उनका नियमित ऑडिट होना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन दबाव की जरूरत है। नागरिकों को जवाबदेही की मांग करनी चाहिए।

मोरबी की भयावहता या मुंबई की डूबती सड़कों की तरह गंभीरा का ढहना, ऐसे दुर्घटना है, जिसे रोका जा सकता था। यह हादसा संवेदना और नकदी से कहीं अधिक और हिसाब-किताब की मांग करता है। बुनियादी ढांचा किसी राष्ट्र द्वारा अपने लोगों से किए गए वादों की रीढ़ है। जब यह टूटता है, जैसा कि गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता और अनगिनत जगहों पर हुआ, तो यह लोगों के भरोसे को भी तोड़ता है। भारत जब तक इस उदासीनता से निजात नहीं पाता, तब तक ऐसे संकट आते रहेंगे और इसके पीड़ितों को उपेक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो इसमें बदलाव लाना होगा।

edit@amarujala.com

भेष बदलकर नगर का हाल जानने निकले राजा बलदेव से राहगीर ने कहा, 'जवानी में बुढ़ापे के लिए और इस जन्म में परलोक के लिए कमाई करनी चाहिए।'

राहगीर ने दी राजा को सीख

राजा बलदेव, जो मदुरा और तिरुनेलवेली जिलों पर शासन करते थे, प्रजा की भलाई के लिए एक रात भेष बदलकर नगर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए राहगीर को देखा और पूछा, 'आप कौन हैं और कहां से आए हैं?' राहगीर ने उत्तर दिया, 'महाशय, मैं कल सेतु नदी में स्नान करेगा। आज रात यहां विश्राम कर रहा हूं।' राजा ने कहा, 'आप विज्ञान और देवादान किए हुए प्रतीत होते हैं। कृपया कोई अनुभव सुझाव करें।'

राहगीर बोला, 'मनुष्य को चाहिए कि वह आठ माह तक परिश्रम करे, ताकि वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक भोजन कर सके, दिन भर मेहनत करे, ताकि रात को सुख की नींद सो सके, जवानी में बुढ़ापे के लिए संग्रह करे और इस जन्म में परलोक के लिए कमाई करे।' राजा ने कहा, 'आपने सत्य कहा। मैंने अब तक संसार के झंझटों में जीवन व्यर्थ किया। यह राजा को भक्ति मार्ग दिखाकर विदा हो गया। अब राजा के हृदय में परम तत्व को जानने की उत्कंठा जागृत हुई।

अंतर्यात्रा
संकलित

उन्होंने देश भर के सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रतिनिधियों को एक सभा में एकत्रित किया। उनमें से राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए 'विष्णुचित्त' जी बोले, 'भगवान नारायण ही सर्वोच्चि हैं और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, कल्याण का एकमात्र यही उपाय है। भगवान नारायण ही हमारे रक्षक हैं। विष्णुचित्त जी के उपदेश से राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्हें अपने गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 16 जुलाई, 1952

अमेरिका को चीन के प्रधानमंत्री की चेतावनी

अमरीका हवाई जहाज मंचूरिया पर भी जा पहुंचे
मुकदमे की सुनवाई की तारीख पेकिन में नियत
व्यापार

चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसके हवाई जहाज ने मंचूरिया में चीनी नागरिकों पर हमला किया है। इससे सुदूर पूर्व में स्थिति गंभीर हो गई है और इसकी जिम्मेदारी उसे ही उठानी होगी।

आंकड़े

रजत अयस्क भंडार

भारत में पाई जाने वाली दुर्लभ खनिज संपदाओं में शामिल रजत अयस्क की सबसे ज्यादा उपलब्धता राजस्थान में है।

आंकड़े रजत अयस्क उपलब्धता के, प्रतिशत में | चीनी : Mines Bureau

स्मृति-शेष

ऐसी ताकत हर किसी को नहीं मिलती

फौजा सिंह
(14.1911 – 14.7.2025)

89 साल की उम्र में गंभीरता से दौड़ना शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज मैराथन धावक कहते थे, 'दौड़ना ईश्वर की इबादत है। इससे मन और शरीर की एकरूपता बढ़ती है और लंबी उम्र मिलती है।'

दुनिया का जीवित अजूबा बने रहने वाले मैराथन धावक फौजा सिंह अब इस दुनिया हमें दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। वह 114 वर्ष के ऐसे बुजुर्ग युवा धावक थे, जो उम्र का मजाक उड़ाने वाले और उड़ती हवा के बुलबुले के साथ वालेपुर को बाट करने वाले एक जादुई शख्सियत थे। 'पगड़ी वाला तूफान', 'सिंग भाव' और 'सुपर सिख' जैसे विशेषणों के साथ मैराथन में धावक कहलाने वाले फौजा सिंह का जन्म 1 अप्रैल, 1911 को जालंधर के पास व्यास गांव में हुआ था। बाद में, वह एक भारतीय मूल के सिख एथलीट के रूप में ब्रिटिश नागरिक बन गए। 2003 में, 92 वर्ष की उम्र में, उन्होंने टोरंटो मैराथन में दौड़कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। खास बात यह है कि उन्होंने 89 साल की उम्र में गंभीरता से दौड़ना शुरू किया था।

गर्व है कि मुझे पारिवारिक रूप से फौजा सिंह के साथ जालंधर में समय बिताने का मौका मिला। जब भी वह हमारे घर आए, परिवार के कई सदस्य की तरह आशीर्वाद दिया। वह बताते थे कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक होने का राज उनकी सादगी और जांबाजपुर का शुक्रगुजार है। वह कहते थे कि दौड़ना ईश्वर की इबादत है। इससे मन और शरीर की एकरूपता बढ़ती है और लंबी उम्र मिलती है। वह कहते थे, 'कोई भी चीज जो करने लायक हो, वह मुश्किल तो होगी ही।' 100 साल की उम्र में उन्होंने टोरंटो वाटरफ्रंट इवेंट में आठ घंटे, 25 मिनट और 16 सेकंड में मैराथन दौड़कर दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाया था। पांच फुट आठ इंच लंबे और करीब 53 किलो वजन के फौजा सिंह कई बार परिवार से छिपकर दौड़ने चले जाते और रिकॉर्ड बनाकर लौट आते। वह कहते थे, 'दौड़ने ने उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का एहसास दिया। मैं उत्साह नहीं लेता। कभी नहीं सुना कि कोई खुशी से मर गया।' 1995 में अपनी पत्नी व बेटे की मृत्यु के बाद वह इंग्लैंड चले गए थे और लंदन में परिवार के साथ 'सादा जीवन' जीते थे।

उनके कोच हरमंदर कहते थे, कि उनकी सेहत की जांच से पता चला था कि उनकी हड्डियां 35 साल के व्यक्ति जैसी थीं। वह खुद कहते थे, 'मैं उतना ही खाता हूं, जितनी जरूरत है : थोड़ी दाल और रोटी, गोभी और चाय। अगर मैं हर वक्त पेट भरकर खाऊं, तो शायद मर जाऊं।' फौजा सिंह रोजाना 10 से 15 किलोमीटर दौड़ते थे। 94 साल की उम्र में वह डेविड बेकहम और जॉनी विल्किंसन के साथ एडिडास के पोस्टर बॉय बने थे। वह कहते थे कि यह जिंदगी वहेंगुरु ने जीने के लिए दी है, तो इसे जियो। वह सचमुच एक लंबी पारी खेलकर इस दुनिया के रंगीन खेल को देखते हुए, दौड़ते हुए चले गए। ऐसी ताकत हर किसी के हिस्से में नहीं आती। इस महान धावक की यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।

-प्रो. कृष्ण कुमार रत्तू

आस्था और अनुशासन

कांवड़ यात्रा, जो अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, में कांवड़ियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह से चुनौतियां भी बढ़ी हैं।

केसी त्यागी, भूतपूर्व सांसद — मुद्दा

भारत में धार्मिक आस्थाएं और उनसे जुड़ी परंपराएं अनादि काल से हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रही हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परंपरा कांवड़ यात्रा है, जो भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, हर साल सावन के महीने में गंगाजल लेने और उसे शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा आस्था और भक्ति का प्रतीक है और श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होती है।

हर साल कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हरिद्वार प्रशासन के अनुसार, कांवड़ यात्रा में पिछले साल लगभग पांच करोड़ लोग हरिद्वार पहुंचे। यह कांवड़ यात्रा लगभग 12 दिन तक चलती है। इन 12 दिनों में पांच करोड़ लोगों का हरिद्वार आना बहुत आश्चर्यचकित कराता है, इस हिसाब से देखें, तो इन 12 दिनों में औसतन 40 लाख

कांवड़िए हर रोज हरिद्वार पहुंचे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 40 लाख लोगों के हरिद्वार पहुंचने पर हरिद्वार और उसके आसपास लगभग 30-40 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्सव-सा माहौल रहता है।

इस उत्सव से स्थानीय लोगों के लिए अस्थायी रोजगार का सर्जन तो होता ही है, वहीं कांवड़ियों की बेताहाशा भीड़ के कारण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। इसके बावजूद स्थानीय लोग पूरी तन्मयता के साथ कांवड़ यात्रा में अपना सहयोग देते हैं। लेकिन, हाल के वर्षों में एक अलग-सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ असाजक और उपद्रवी तत्व भी आ जाते हैं। उनके असाजक व्यवहार, नियमों के उल्लंघन और उद्दंडता से विवाद खड़ा हो जाता है। श्रद्धा की भावना को इससे भारी चोट पहुंचती है।

कांवड़ यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए गंगाजल लाना है। यह यात्रा मुख्य रूप से उत्तर भारत में की जाती है और इसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल होते हैं। श्रद्धालु अपने कंधों पर कांवड़ रखकर यात्रा करते हैं, जिसमें दो तरफा बर्तन होते हैं, जिनमें गंगाजल भरा जाता है। यह यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं होती और इसमें शामिल होने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। आज भी अधिसंख्य कांवड़िए वही हैं, जो सदियों पुरानी स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हैं। समस्या तो उन चंद लोगों के कारण उठ खड़ी हुई है, जिनकी संख्या तो थोड़ी है, लेकिन उनका उत्पात और उच्छृंखल व्यवहार की सभी सीमाएं लांघ जाता है। ऐसी घटनाओं से न केवल धार्मिक यात्रा का पवित्र उद्देश्य खंडित होता है, बल्कि भय और असुरक्षा का माहौल भी बनता है।

कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन और पुलिस की भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उन्हें श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है। जरूरत है संतुलित दृष्टिकोण की, जिससे कांवड़ियों की आस्था का सम्मान भी हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रवियों को रोकने में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है, कांवड़ियों का सहयोग। समाज के अन्य वर्गों को कांवड़ियों के प्रति सहानुभूति और सहयोग का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य और सद्भाव बना रहे। इसके लिए कांवड़ियों और समाज के अन्य वर्गों के बीच संवाद और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे दोनों पक्ष एक-दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझ सकें। कांवड़ यात्रा के दौरान स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, जो श्रद्धालुओं की मदद कर सकें और व्यवस्था को बेहतर बना सकें।

जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक समस्या है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। बेतहाशा भीड़ के कारण हुए कचरे का निस्तारण भी बड़ी समस्या हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार, केवल हरिद्वार में ही पिछले साल 12 दिन की कांवड़ यात्रा के दौरान लगभग 30 हजार मीट्रिक टन कूड़ा पैदा हुआ था। जब केवल हरिद्वार में ही 12 दिनों में इतना कूड़ा एकत्र हो गया, तो यात्रा-पथ के आसपास की चुनौती का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए सामूहिक प्रयास से प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, कचरा प्रबंधन और ध्वनि प्रदूषण का समाधान निकाला जाना जरूरी है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का प्रतीक है। आस्था और अनुशासन एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रशासन, समाज और श्रद्धालुओं के संयुक्त प्रयासों से ही इस पवित्र उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है।

-साथ में विशाल नेहवाल (सामाजिक चिंतक)

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । कानपुर (कानपुर व लखनऊ में एक साथ प्रसारित) । बुधवार, 16 जुलाई 2025

व्यवस्था पर सवाल

ओडिशा के बालासोर में कॉलेज फैकल्टी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा की मौत पूरे सिस्टम की हार है। सरकारी स्तर पर अभी जिस तरह की सक्रियता दिख रही है, अगर वह पहले दिखती, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती।

सुनवाई नहीं । बीएड स्टूडेंट ने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की शिकायत प्रिंसिपल से की थी। अब यह तथ्य सामने है कि खुद को आग लगाने से कुछ दिनों पहले भी उसने एक्स (पहले ट्विटर) पर सार्वजनिक रूप से अपनी शिकायत रखते हुए चेताया था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह जान दे देगी। कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट कमिटी से लेकर प्रिंसिपल तक, वह जहां तक पहुंच सकती थी, गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई।

ओडिशा में छात्रा की मौत

यह कैसी इमेज । आरोप है कि प्रिंसिपल ने पीड़िता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया, क्योंकि उन्हें कॉलेज की 'इमेज' खराब होने की चिंता थी। इस मामले में एक बड़ी भूमिका इस कथित 'इमेज' की है, जिसे बचाने के चक्कर में अक्सर अपराध को छिपाया जाता है। लेकिन क्या किसी शैक्षणिक संस्थान की छवि एक छात्रा के जीवन से बढ़कर हो सकती है और क्या अपराध की शिकायत पर कार्रवाई करने से इमेज दागदार होती है?

बार-बार लापरवाही । ओडिशा का नाम पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाओं में लगातार आया है। इस साल फरवरी में भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलजी (KIIT) में बीटेक थर्ड ईयर की एक नेपाली स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी। वहां भी पीड़िता ने एक छात्र पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और उस केस में भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने लापरवाही बरती थी, जिसकी वजह से मामला भारत-नेपाल के बीच कूटनीतिक स्तर तक पहुंच गया था।

बढ़ते मामले । ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मार्च में विधानसभा में बताया था कि 2020 से फरवरी 2025 के दौरान पूरे राज्य के विभिन्न स्कूल-कॉलेजों में 72 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर के पीछे वजह थी - मेंटल प्रेशर, उत्पीड़न, पढ़ाई का दबाव, घरेलू परेशानियां, डिप्रेशन वगैरह।

औपचारिकता न हो । UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक, हर शैक्षणिक संस्थान में सेक्सुअल हैरेसमेंट की जांच के लिए कमिटी होनी चाहिए। हालांकि यह सबसे शुरुआती जरूरत है। कमिटी तो हो, लेकिन साथ में संवेदनशीलता भी चाहिए - जो स्टूडेंट्स के साथ संवाद और तय समय सीमा के भीतर जांच करे। जांच में दोषी पाए जाने पर उस शख्स को सजा भी मिलनी चाहिए। तभी ऐसे मामलों में इंसाफ हो पाएगा।

कभी-कभी

बारिश नहीं बदलती

ललित वर्मा

उसे केवल पहली बारिश पसंद थी। उमस और गर्मी से शरीर काला पड़ने लगता था तो बारिश उस कालस को धो देती थी। ऐसा उसे लगता था। उसे तो यह भी लगता था कि काला रंग होना ही नहीं चाहिए। बेकार रंग है। कोई भी रंग डालो, उसकी जिद और घमंड हर रंग को बेअसर कर देते हैं। ऐसे ही एक बार की बारिश के बाद अगली बारिश से उसे बादलों का बरसना अखरने लगता। कहीं भी निकलना दूभर हो जाता। शहर की धूल-मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाती। घर में कैद रहना उसे नहीं सुहाता था। एक दिन के लिए भी नहीं।

बालिग होने में एक बरस बाकी था। बरामदे से जब वह बरसात को देखता, तो आसमान भी दिखता, जहां से बूंदें गिरना शुरू होती हैं। और सीमेंट की टीप से जोड़ी ईंटों का भीगा फर्श भी, जहां बूंदें खत्म होती हैं। बीच में बूंदों का सफर कैसा दिखता है, यह कभी नहीं दिख पाता। आंगन में भीगता तुलसी का पौधा दिखता। दूर आले में रखी कांच की बोतल में टंगा मनीप्लांट भी। छोटे पौधे दिखते, बड़े वृक्ष नहीं। घर में खिड़कियां नहीं थीं। जहां छत से आसमान दिखता हो, वहां खिड़कियों का क्या काम। पर वह खिड़कियों से बाहर झांकनें की कल्पना करता। उसने फिल्मों में देखा था। मुंबई में खिड़की से बारिश को निहारती नायिका को, नायक को। उसे खिड़की का महत्व नहीं पता था, नायक-नायिका उसे लुभाते थे।

आज वह खिड़की से बारिश देख रहा है। आज नहीं, एक महीने से देख रहा है। रोज, बाहर बड़े पेड़ दिख रहे हैं और पानी से लबालब पार्क। ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं। 20 से ज्यादा मंजिलें बन जाने के बाद भी एक क्रेन मंजिलें बनाए जा रही है। उसे आसमान छूना है शायद, जहां से गिरना शुरू होती हैं बूंदें। खिड़की से केवल बूंदें दिख रही हैं। न आसमान और न कोई तल, जहां गिरकर खत्म हो रही हैं बूंदें। उनके बीच का सफर दिख रहा है। तुलसी का पौधा भी है, लेकिन बालकनी में। बड़े शहरों में ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। आंगन की जगह बालकनी ले लेती है। आसमान निहारने की जगह खिड़की से बाहर झांकना। घर से निकलना मजबूरी लगने लगता है, इसलिए जितना वक्त बचता है, उसे घर में बिताने का मन करता है। पहली बारिश के बाद भी बारिश अच्छी लगने लगती है। बस एक ख्याल है जो अच्छा नहीं लगता। पहले जो था, वह क्यों नहीं भाता था। जो चाहत थी, वह मिल जाने के बाद वह क्यों याद आता है, जो बहुत पीछे छूट जाता है। बारिश नहीं बदलती, बस मन बदल जाता है।

एकदा

किताबों से खुली राह

साल 1905 में बर्मा (अब म्यांमार) में जन्मी इरावती को 7 वर्ष की उम्र में पुणे के हुजूरपागा बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी मित्रता शाकुंतला परांजपे से हुई। शाकुंतला के पिता, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर.पी. परांजपे ने इरावती को अपनी बेटी की तरह स्नेह दिया। एक दिन परांजपे की लाइब्रेरी में किताबें उलटते हुए इरावती को मानवशास्त्र में गहरी रुचि उत्पन्न हुई। फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे से उन्होंने आगे की पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात रसायन विज्ञान के प्रफेसर दिनाकर कर्वे से हुई। उनसे विवाह करने के बाद इरावती ने बर्लिन से मानव विज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई का फैसला किया। वहां प्रसिद्ध मानव विज्ञानी यूजीन फिशर के मार्गदर्शन में 149 मानव खोपड़ियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने फिशर के नस्लीय सिद्धांतों का खंडन करते हुए अपने निष्कर्ष दिए, जिससे उनकी डिग्री खतरे में पड़ गई, पर उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। भारत लौटकर उन्होंने पुरातात्विक अभियानों में भाग लिया और 15 हजार वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज के लिए महीनों जंगलों में काम किया। वही इरावती कर्वे भारत की पहली महिला Anthroplogist के तौर पर मशहूर हुई।

Subrata Dhar

संकलन : रेनू सैनी

विदेश मंत्री जयशंकर की चीन यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिश के रूप में देखा जा रहा

SCO समिट में चिनफिंग से मिलेंगे मोदी?

हर्ष वी. पंत

भारत-चीन संबंधों के लिहाज से 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, वह एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद भारत ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाया। उसने स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीन सीमा क्षेत्र में शांति बहाल नहीं करता और अपनी फौज को पीछे नहीं हटाता- यानी बॉर्डर पर जो 'यथास्थिति' बदलने की कोशिश की गई थी, उसे पहले की तरह नहीं करता- तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

रिश्तों में नरमी । यह भारत की ओर से एक निर्णायक रुख था। जहां सैन्य स्तर पर चीन को सख्त जवाब दिया गया, वहीं कूटनीतिक स्तर पर यह फैसला लिया गया कि जब तक सीमा पर 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होती, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। इस रुख पर भारत डटा रहा। आखिरकार, जब चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाया और बॉर्डर पर स्थिति को कुछ हद तक पूर्ववत किया, तब जाकर रिश्तों में थोड़ी नरमी आई।

चीन की स्वीकारोक्ति । अक्टूबर 2023 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि गलवान संघर्ष के बाद जो विवादित क्षेत्र बने थे, वहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और 'डी-एस्कलेशन' की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि सेनाएं अब भी सीमा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात हैं और 'डिसएंगेजमेंट' की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन भारत ने जो पक्ष रखा, उसे चीन ने मान्यता दी। चीन यह मानने को मजबूर हुआ कि उसने जो बदलाव लाने की कोशिश की थी, वह असफल रही और द्विपक्षीय संबंधों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा।

बदलता रुख । चूंकि चीन ने अब कुछ हद तक अपना रुख बदला है, भारत ने भी संबंध सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पिछली मुलाकातों में यह बात सामने आई थी कि दोनों देशों को सीमा पर शांति बहाल कर संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। यही विचार अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की हालिया चीन यात्रा में उनकी मुलाकात चीनी समकक्ष वांग यी से हुई। उन्होंने शी चिनफिंग से भी भेंट की। यह इस ओर इशारा करता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आगामी SCO (शंघाई सहयोग संगठन) सम्मेलन के लिए जाएंगे, तो वहां उनकी शी चिनफिंग से एक और मुलाकात हो सकती है।

ट्रंप का प्रभाव । इस संदर्भ में अनिश्चितता की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से जो वैश्विक अस्थिरता आई है, उसका असर जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य पारंपरिक साझेदारों पर भी पड़ा है। इस लिहाज से भारत ने भी अपनी विदेश नीति को री-बैलेंस करने की जरूरत महसूस की है।

कौशलपूर्ण प्रबंधन । ऐसे में भारत-चीन संबंधों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को 'कौशलपूर्ण प्रबंधन' के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव की बुनियादी प्रवृत्तियां अभी भी बरकरार हैं। चीन भले ही नए सिरे से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं यही हैं कि वह हिंद-प्रशांत में प्रमुख शक्ति बनकर उभरे और भारत को केवल दक्षिण एशिया तक सीमित रखे।

बनते-बिगड़ते रिश्ते

- अभी भी चीन-भारत की सेनाएं सीमा पर बड़ी संख्या में तैनात
- ट्रंप के चलते नीति बदलने पर मजबूर हुआ है चीन
- भारत-चीन संबंधों से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं

गहराता तनाव । हाल के उदाहरण इस दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं। मसलन, SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य में भारत की सुरक्षा चिंताओं, जैसे कि पुलवामा, का जिक्र नहीं किया गया था। भारत ने यह स्पष्ट किया कि यदि चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद पर भारत के दृष्टिकोण की अनदेखी करेंगे, तो वह असहयोग का रुख अपना सकता है। इसी तरह, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने की कोशिशें, मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी प्रचार ने यह दिखा दिया कि भारत और चीन के संबंधों में तनाव गहरा है।

आसान नहीं रास्ता । भारत इस तनाव को नियंत्रित रखने की कोशिश करते हुए चाहेगा कि सेना की सहायता से डिफेंस पोजिशनिंग सुदृढ़ रखे और जहां सहयोग की संभावना हो, वहां साझेदारी को बढ़ाए। भारत और चीन ऐसे मुद्दों पर साथ काम कर सकते हैं जहां उनका दृष्टिकोण एक जैसा हो, लेकिन जहां मतभेद हो, वहां उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया जाए। चीन भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती बना रहेगा और उसे संभालना भारत के लिए आसान नहीं होगा। फिर भी, इसकी कोशिश करनी होगी क्योंकि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में यह अनिवार्य है कि भारत और चीन के बीच संवाद के चैनल खुले रहें।

जारी रहे संवाद । गलवान संघर्ष के बाद भी भारत ने यह बात कही थी कि संवाद का माध्यम कभी बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत यह भी चाहता है कि चीन उसकी संवेदनाओं और हितों को समझे और उनके विरुद्ध काम न करे। आने वाला समय ही बताएगा कि भारत की यह कूटनीतिक पहल कितनी सफल होगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत अपनी रणनीति में संतुलन, दृढ़ता और चतुराई बनाए रखकर आगे बढ़ रहा है।

(लेखक लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

कितना काम कितना आराम

दिन में काम के कितने घंटे हों, बेंगलुरु के एक उद्यमी के X पर किए गए पोस्ट के बाद इस पर फिर से बहस तेज हो गई है। उधर, तेलंगाना सरकार ने व्यावसायिक यूनिट्स के लिए रोजाना 10 घंटे काम को मंजूरी दी है तो कर्नाटक सरकार भी यही सोच रही है। क्यों जताई जा रही है इसकी जरूरत और क्या है इसे लेकर बहस, आइए समझते हैं :

मांग के तर्क

- वर्ल्ड लेवल प्रॉडक्टिविटी के लिए है जरूरी
- जॉब माइंडसेट से निकल कर और क्रिएटिव बनें युवा
- देश में गरीबी और अल्प विकास का जोखिम
- ज्यादा काम, ज्यादा उत्पादन, तो फिर ज्यादा मुनाफा

कानूनी घंटे

- **10** घंटे की शिफ्ट को मंजूरी दी तेलंगाना ने कमर्शल यूनिट्स में
- **48** घंटे की सीमा, वीकली पेड ओवरटाइम
- **10** घंटे पर कर्नाटक में विचार, ओवरटाइम के साथ 12 घंटे
- **12** घंटे की शिफ्ट का प्रावधान भारत के नए श्रम कानूनों में
- **48** घंटे की वीकली लिमिट अभी भी लागू

यूनियनों की प्रतिक्रिया

- KITU ने कर्नाटक प्रस्ताव का विरोध किया
- यूनियनों ने मॉडर्न स्लेवरी का आरोप लगाया

बहस क्यों

गेमिंग स्टार्टअप के को-फाउंडर मोहन कुमार X पर बोले : उनके कर्मचारी हफ्ते में 6 दिन / रोजाना **12** घंटे काम करते हैं

इससे पहले इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने सप्ताह में **70** घंटे काम की वकालत की थी

दुनिया का हाल

77% — 63.4% — 50.5%

(ILO, इकनॉमिक)

- हफ्ते में 49 घंटे या उससे अधिक काम
- कर्मचारी बर्न आउट सिंड्रोम से गुजरे

बदलता नजरिया

भारतीय वर्कफोर्स में बदली हैं काम की प्राथमिकताएं:

- **52%** नौकरी में लचीलापन नहीं, तो नौकरी नहीं करनी
- **60%** मैनेजरों से अच्छे संबंध नहीं तो नौकरी छोड़ने को तैयार

(रैंडस्टैड वर्कमॉनिटर 2025)

बैलेंस पथ

- **1926** फोर्ड में 40 घंटे सप्ताह शुरू
- **1970** वर्क-लाइफ बैलेंस शब्द उभरा
- **2010** गूगल-माइक्रोसॉफ्ट में रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल
- **40%** बढ़ी प्रॉडक्टिविटी
- **2000** में फ्रांस में 35-घंटे वीकली लागू, बेरोजगारी घटी
- कोविड-19 में आया रिमोट वर्क कल्चर
- **22%** वर्कफोर्स अभी तक रिमोट पर है
- बर्न आउट व डिजिटल थकान बढ़ी

आठ घंटे की शिफ्ट दुनिया भर के कामगारों को काफी संघर्ष के बाद मिली है। शिफ्ट का समय बढ़ाने पर बेरोजगारी भी बढ़ती है। इसलिए शिफ्ट का समय बढ़ाना सही नहीं है। – दीपा सिन्हा, अर्थशास्त्री

बैलेंस इंडेक्स

इसी महीने जुलाई में रिमोट ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स आया:

नंबर 1 न्यूजीलैंड स्कोर: 86 | **33 घंटे काम हफ्ते में**

टॉप 10 में 7 देश यूरोप के: आयरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन

42 भारत का स्कोर — छुट्टियां ज्यादा, हेल्थकेयर, वेतन, सुरक्षा कमजोर

59 US का स्कोर — कमजोर लीव सिस्टम, लंबी शिफ्ट, प्राइवेट हेल्थकेयर

ग्राफिक्स: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक्स: गौरव

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

जीवन यात्रा में सिर्फ़ नाविक नहीं, कोलंबस बनिए

निर्मल जैन

अच्छाई मनुष्यों में पाई जाने वाली भावनाओं में सबसे सकारात्मक भावना है। अच्छाइयों के पकवान परोसेंगे तभी तो जिंदगी में मिठास का स्वाद आएगा। मन में जब अच्छाइयों का उजास चमक उठेगा, तो अवगुणों की कालिमा उड़नछू हो जाएगी। अभिमान, क्रोध और आक्रोश जैसी बुराइयों की विदाई हो जाएगी। जीवन का उत्थान अच्छाई पर आधारित है। बुराई न केवल विकास में अवरोध उत्पन्न करती है, बल्कि प्राप्त सुखों को भी नष्ट कर देती है। मन में अगर अच्छाइयों की मूर्ति स्थापित हो जाए तो समझो जीवन मंदिर है। अगर यही मन कूड़ेदान बन जाए तो जानना शैतान की सैरगाह सरीखा है। अशुभ भाव में प्रवेश होना ही बुराई है।

नाव के छोटे-से छेद की तरह बुराई का एक छोटा-सा अवशेष भी हमारी जीवन नौका को डूबो देता है। बुराई अकेली नहीं आती उसके पीछे उसकी सारी टीम आती है। झूठ के पीछे चोरी, चोरी के साथ हिंसा और हिंसा के साथ आतंक आदि अमानवीय शक्तियों का सिलसिला चल पड़ता है। अच्छाई को बुद्धि से हृदय तक पहुंचने में देर लगती है, किंतु बुराई तुरंत बुद्धि से हृदय की ओर दौड़ती है। यही कारण है कि मन बुराई में शीघ्र प्रवेश करता है और अच्छाई के लिए सोच-विचार करता है। जीवन-यात्रा में कदम-कदम पर अच्छाई के साइन बोर्ड मिलते हैं। जो इन्हें पढ़ कर अनुसरण कर लेते हैं, वे कोलंबस बन जाते हैं, नहीं तो मात्र नाविक होकर रह जाते हैं।

बुराइयां कितना भी आस-पास मंडराएं, अच्छा बने रहने के लिए दो बातों को कभी न भूलें - खिलता हुआ चेहरा और होठों पर मुस्कुराहट। होठों पर हंसी हो तो चेहरा हसीन नजर आता है, दिल हंसे तो पूरा जहां खूबसूरत नजर आता है। रोशनी भी उसी को है, जो शमा जलाना जानता है। वैसे ही जो मुस्कुराना जानता है, यह खुशनुमा संसार भी उसी का है।

बुराइयों के प्रभाव से बचने के लिए दूसरा सर्वोत्तम समाधान है - चुप्पी यानी मौन। दैनिक जीवन की हलचल के बीच मौन खुद को रिचार्ज करने और स्पष्टता खोजने का अवसर देता है। यह भावनाओं की भूल-भुलैया से बाहर निकलने में एक दिशासूचक यंत्र की तरह मदद करता है। मौन किसी को यह बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्होंने गलत किया है।

शायद यह हममें से किसी के लिए भी संभव नहीं कि हम सब का भला कर दें। लेकिन सबके प्रति भलाई की भाषा तो हमेशा इस्तेमाल कर ही सकते हैं। कम से कम दिन में एक बार उन्हें धन्यवाद अवश्य दे सकते हैं, जिन्होंने अच्छाइयों से हमारे जीवन और वातावरण को महकाया। उनके गुणों का आकार अपने मन के प्रांगण में इतना बढ़ा लें कि बुराई को स्थान ही न मिले। इसी तरह से जिन्होंने कुछ अप्रिय किया, उन तक भी अपने गुणों की महक पहुंचने दें, ताकि वे भी अच्छाई के वातावरण में सांस ले सकें।

आर.एन.आई. नं. UP/LUC/2001/7526 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं विभिन्न डाकघरों के लिए संपादक द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रक, मुद्रित किया। राजधानी प्रिंटर्स, 19/1/1, विभिन्न खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 से प्रकाशित किया गया, लखनऊ में मुद्रित। प्रधान कार्यालय: 5, 6, 7, 8, 9, 10 मंजिल, अर्केडिया प्लेस, नवीन ब्लॉक 226028 टेलीफोन: 0522-2382212, 0522-4104444, संपादक-कार्यालय: 10 मंजिल, पॉलिका हाउस, गोमती नगर, लखनऊ-226010।

स्थानीय कार्यालय: नुकसी निवास (एक अंश पेशकश) अमरुद्दौला कॉलोनी के पास राजाजीपुरम रोड, आर. बी. एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड।

समय के साथ कैसे बदली है RSS की सोच

पूनम पाण्डे

इस साल विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तब से लेकर अगली विजयादशमी तक संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। इस दौरान एक लाख से ज्यादा जगहों पर हिंदू सम्मेलन होने हैं - संघ के स्वयंसेवक घर-घर जाकर अभियान चलाएंगे।

भागवत का संवाद । RSS प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ संवाद करेंगे। पहली बार संघ इस स्तर पर संवाद कर रहा है। तो क्या संघ अब पहले से ज्यादा खुल रहा है?

जुड़ाव का तरीका । इसका जवाब RSS के लोग इस तरह देते हैं कि संघ का जनसंवाद का आयाम नया नहीं है। हां, इसकी आवृत्ति जरूर बढ़ी है। यह विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे स्वयंसेवकों के फीडबैक के आधार पर तय किया जाता है। मोहन भागवत की लेक्चर सीरीज से पहले इस तरह का कार्यक्रम 1974 में हुआ था। तब उस वक्त के सरसंघचालक बालासाहब देवरस ने पुणे की वसंत व्याख्यानमाला में संघ के संदेश और विचारों को रखा था।

सफल प्रयोग । संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर की किताबों में भी उनके समाज के साथ बातचीत का जिक्र है। संघ के लोग कहते हैं कि RSS का काम ही समाज के बीच जाना और संवाद करना है। पहले माना जाता था कि सरसंघचालक तक पहुंच नहीं है और उनसे सीधा संवाद नहीं हो सकता। इसके बाद RSS के संपर्क विभाग ने 2018 में एक प्रयोग के तौर पर सरसंघचालक का दिल्ली में संवाद कराया। संघ के मुताबिक, यह काफी सफल रहा और कई भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिली।

मुस्लिम संवाद । संघ अब ऐसे मुद्दों पर भी आगे बढ़ा है, जिसके बारे में स्वयंसेवक पहले बात नहीं करते थे, जैसे मुस्लिम संवाद। 2012 में संघ के वरिष्ठों की एक

कॉमन रूम

बैठक में सबसे पहले इस पर चर्चा हुई कि मुस्लिम समुदाय से संवाद होना चाहिए। हालांकि पहले भी सर्वपंथ समभाव के नाम से अलग-अलग पहलुओं पर संघ के कुछ संवाद कार्यक्रम हुए थे। लेकिन, उस बैठक के बाद खास तौर पर मुस्लिम संवाद कार्यक्रम ने आकार लिया।

दूरगामी लक्ष्य । पिछले कुछ बरसों से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वह इमामों से मिलने मस्जिद भी गए और मदरसे जाकर बच्चों से भी मुलाकात की। संघ के वरिष्ठ प्रचारकों ने अनौपचारिक बातचीत में साफ किया कि संघ की तरफ से मुस्लिमों से संवाद दूरगामी लक्ष्य के लिए है। संघ चाहता है कि समाज में सभी लोग शांति और सहयोग के साथ रहें। हिंदू-मुस्लिम विवाद ना हो, यह कोशिश संघ लगातार कर रहा है। RSS हिंदू समाज में यह मानसिकता तैयार करना चाह रहा है कि भारत में रहने वाले सभी अपने ही हैं, भले किसी भी धर्म के हों।

समय के साथ बदलाव । संघ में काफी कुछ बदला है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने खुद 2018 में अपने संवाद में कहा था कि वक्त के साथ सोच भी बदलती है। उन्होंने संघ के पूर्व सरसंघचालक की किताब में लिखी बातों के बारे में कहा था कि कुछ बातें परिस्थिति के हिसाब से होती हैं, वे शाश्वत नहीं होतीं। संघ बंद संगठन नहीं है कि संस्थापक हेडगेवार ने जो बोल दिया वही लेकर चलता रहे। वक्त के साथ सोच बदलती है। बदलाव की अनुमति हेडगेवार से ही मिली है।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • बुधवार • 16 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

यदि आप बुद्धिमानी से आज्ञा दें, तो लोग खुशी से उसका पालन करेंगे
-थोमस फुलर

नीयत पर संदेह

चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। कुछ विपक्षी दलों व अन्य लोगों ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। हालांकि जुलाई के अंत तक निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षण पर अंतिम फैसला लेने की भी चर्चा है। अधिकांश राज्यों में 2002 से 2004 के दौरान मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया गया था। आयोग की बेवसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में उपलब्ध सूची 2008 की है, जबकि उत्तराखंड में आखरी गहन पुनरीक्षण 2006 में होने की सूचना है। अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने के विवाद के बाद बिहार में यह बहस गरम हुई। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं,

जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में भी अगले वर्ष होंगे। बूथ स्तर के कर्मचारियों का आरोप है कि घर-घर जाकर की गई जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार के अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में मिले। इस सारी कवायद पर संदेह व्यक्त करने वालों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। साठ फीसद से भी कम नागरिकों के पास पक्का मकान है, केवल 14 वयस्क दसवीं तक पढ़े हैं। सवाल है, बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर रोजगार के सिलसिले में अन्य राज्यों में जा चुके हैं, उनका नाम इस सूची में शामिल करने का जिम्मा कौन लेगा। शहिए पर खड़े लोग, दलितों, वंचितों व गरीबी रेखा के नीचे गुजार करने वालों से दस्तावेजों की सूची मांगना गैरवाजिब है। उस पर भी जिनके नाम पहले ही मतदाता सूची में मौजूद हैं और वे तीन-चार बार अपना मत प्रयोग कर चुके हैं। हैरत है कि इतने व्यापक स्तर पर बनाए गए आधार कार्ड पर सरकार और उसका समूचा तंत्र विश्वास क्यों नहीं कर पाता। सबके लिए एक सामूहिक व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती। देश के हर नागरिक के लिए एकमात्र परिचय पत्र की व्यवस्था हो, जिसके मार्फत समूची जनसंख्या का सटीक अंदाजा भी हो और वही नागरिकता की पहचान बने। उसी को मतदानपत्र, लाइसेंस, पैन, बैंक अकाउंट आदि से जोड़ा जाए। आम नागरिक को तनाव देना व सरकारी महकमों के चक्कर काटने के लिए मजबूर करना या हर कुछ दिनों बाद दस्तावेजों की गड्डियां मुहैया कराना कब तक चलता रहेगा। निःसंदेह सरकार की नीयत पर शक की गुंजाइशें कम नहीं हो रहीं।

डीयू में पढ़ाई महंगी

दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में पढ़ाई महंगी होने जा रही है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में जल्द ही इजाफा हो सकता है। विश्वविद्यालय ने अपने अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की फीस में इजाफा करने का मन बना लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी कोर्स की फीस दो लाख रुपये के पार चली जाएगी। इन दो कोर्सेज की फीस बढ़ा कर दो लाख 8 हजार 550 रुपये की जा सकती है। एमए और पीएचडी कोर्सेज की फीस में भी इजाफा होगा। इसी प्रकार कई अन्य कोर्सेज में भी बढ़ोतरी की जानी है। बेशक, उच्च शिक्षा में इजाफा छात्रों और उनके अभिभावकों पर खासा बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा। वैसे ही हमेशा से उच्च शिक्षा का खर्च आम परिवारों की पहुंच से बाहर ही रहा है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रमों में आम परिवार का छात्र

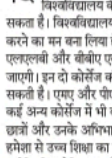

सफल भी रहता है, तो अपनी प्रतिभा के बल पर स्कॉलरशिप आदि पाकर ही सफल हो पाता है। यदि फीस आदि में सहूलियत न मिले तो यकीनन इन पाठ्यक्रमों का शिक्षण व्यय आम परिवार की पहुंच से बाहर है। अब लॉ के अलावा बंगाली जैसी भाषाओं के पाठ्यक्रमों की फीस बढ़ा कर शिक्षा को महंगा करने का फैसला लिया जा चुका है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षण खर्च और एक निजी विश्वविद्यालय में होने वाले पढ़ाई पर खर्च में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। यह समाज के बड़े तबके के हित पर कुठाराघात ही कहा जाएगा। इस प्रकार से फीस में बढ़ोतरी की तैयारी से लगता है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की दिशा में अपने कदम और तेज करने का मन बना लिया है। फीस बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने हरी झंडी दे दी है। संभवतः 2025-26 के सत्र से इसे कार्यान्वित भी कर दिया जाए। एक ऐसे देश में जहां बड़ी आबादी जैसे-तैसे मिनिमम स्तर पर गुजारा कर पा रही है, उसके नौनिहालों के आगे बढ़ने की संभावनाओं को कुंद करना उचित नहीं कहा जा सकता। कहना न होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने महंगे होते बंदोबस्त के नाम पर अपने फैसले को जस्टिफाई करेगा। लेकिन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मात्र इस तर्क के सहारे फीस में बेजा बढ़ोतरी को तार्किक नहीं कहा सकता। सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

कौशल दिवस/योगेश कुमार गोयल

डिजिटल दक्षता ही असल पूंजी

आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में युवाओं के लिए महज पारंपरिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें बदलते समय के साथ तकनीकी, डिजिटल और व्यावसायिक कौशल से भी सुसज्जित होना जरूरी है। इसी संदर्भ में हर वर्ष 15 जुलाई को 'विश्व युवा कौशल दिवस' मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में घोषित किया गया था।

इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर युवाओं के कौशल विकास की आवश्यकता को रेखांकित करना है ताकि वे भविष्य के रोजगार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बन सकें। वर्ष 2025 की थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण', जो इस वर्ष की सबसे प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण वैश्विक आवश्यकता को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस का कहना है कि चूंकि एआई हमारी दुनिया को नया आकार दे रहा है, इसलिए युवाओं को केवल शिक्षार्थी के रूप में नहीं बल्कि एक अधिक न्यायसंगत डिजिटल भविष्य के सह-निर्माता के रूप में देखा जाना चाहिए। तकनीकी क्रांति ने वर्तमान समय में जिस तरह से रोजगार के स्वरूप को बदला है, उसमें अब केवल डिग्री या अकादमिक योग्यता पर्याप्त नहीं रह गई है बल्कि 'चौथी औद्योगिक क्रांति' के युग में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दक्षता युवाओं के लिए सफलता की कुंजी बन गई है। वर्तमान में भारत की तकनीकी शिक्षा प्रणाली और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच एक बड़ा अंतराल है। 'स्किल रिपोर्ट इंडिया 2024' बताती है कि कॉलेज से स्नातक होने वाले छात्रों में केवल 46.2 प्रतिशत ही औद्योगिक मानकों के अनुसार रोजगार योग्य माने जाते हैं, जबकि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, समस्याओं के समाधान, निर्णय लेने, डिजाइन थिंकिंग, नवाचार और टीमवर्क जैसे '21वीं सदी के कौशल' की भी जरूरत है। ऐसे में युवाओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में नेतृत्व करने के लिए एआई, कोडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और साइबर एथिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

विरोध का क्या है औचित्य

मतदाता सूची पुनरीक्षण

अवधेश कुमार

बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण या इंटेंसिव रिवीजन का इलेक्टरल रोल जिस तरह विरोध और हंगामा का विषय बना है वह अनपेक्षित कतई नहीं है। कांग्रेस पार्टी और अनेक भाजपा विरोधी दल, एक्टिविस्ट, पत्रकार, एनजीओ आदि काफी समय से चुनाव आयोग विरोधी तीखा अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी तो पुनरीक्षण आरंभ होने के पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि हेर-फेर कर भाजपा को जिताने का काम चुनाव आयोग करेगा। विरोधी बार-बार आयोग के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय जाते और निराश वापस आते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने इस बार भी पुनरीक्षण प्रक्रिया रोकने की उनकी अपील खारिज कर दिया। हालांकि आगे वह सुनवाई के लिए सहमत हुआ है। सुनवाई के एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की राजधानी पटना में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया गया। चुनाव आयोग का विज्ञापन कहता है कि गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई है और मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त, 2025 को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितम्बर, 2025 को किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि किसी का नाम छूट गया तो दावा करने के लिए एक महीने का समय है।

तो बिना देखे कि किसका नाम जुड़ा, नहीं जुड़ा इस तरह के विरोध का औचित्य क्या है? आयोग पर पहला आरोप है कि वह इतनी जल्दी बड़े पदेश के मतदाताओं की सूची कैसे बना लेगा? जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में पुनरीक्षण हुआ था तब 15 जुलाई से 14 अगस्त यानी वर्तमान के अनुसार ही 31 दिन का समय था। क्या 22- 23 वर्ष के बाद मतदाता सूची की गहनता से जांच-परख नहीं होनी चाहिए? अगर चुनाव आयोग ने इसके लिए आवश्यक जनसंपर्क और आधार कार्ड नहीं लिया तो आलोचना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि पिछले 4 महीने में प्रत्येक विधानसभा, जिला में सर्वदलीय बैठक की गई और लगभग 5 हजार ऐसी बैठकों में 28 हजार लोगों ने भाग लिया। आयोग ने लगभग 80 हजार बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए हैं जो मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी 1.54 लाख बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। भारी संख्या में स्वयंसेवक भी सक्रिय हैं। कुल 16 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म प्रकाशित हुए गए। एक फॉर्म रिसिप्ट के रूप में मतदाता के पास रहेगा और दूसरा बीएलओ रखेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर भी फॉर्म जमा करने की व्यवस्था है।

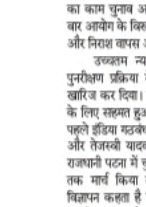

इसलिए यह नहीं कह सकते कि ड्राइव बिल्कुल अव्यावहारिक है। पहाड़ पर सुनिश्चित करने पर चुनाव आयोग के जोर का सबसे तीखा विरोध हो रहा है। पहले कुछ तथ्य पर बात करें। 1 जनवरी, 2003 की सूची में मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 96 लाख थी। वर्तमान में यह संख्या 7 करोड़ 89 लाख है। तो लगभग 2 करोड़ 93 लाख मतदाताओं को ही पहचान सुनिश्चित करनी होगी। जिन मतदाताओं के नाम 2003 में हैं उसके अलावा जिनका नाम आया उनको ही जन्मतिथि, जन्म स्थान आदि साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे।

उनमें भी माता-पिता का नाम 2003 मतदाता सूची में है तो माता-पिता की पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। केवल 2003 वाली मतदाता सूची के उस हिस्से की कॉपी बीएलओ को देनी होगी जिसमें उनके माता-पिता का नाम लिखा है। जिनके नाम 2003 में हैं उन्हें केवल उसकी फोटो कॉपी बीएलओ को फॉर्म जमा करते समय देनी है जिसमें उनका नाम है। क्या 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने वाले के पास अगर जन्मतिथि तथा जन्म स्थान साबित करने के प्रमाण नहीं हो तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा? इसकी आशंका है। पर आयोग का कहना है कि दस्तावेजविहीन व्यक्ति की भारतीय पहचान को सुनिश्चित करने का काम क्षेत्र के एसडीम करेंगे और उनके कागजात का पता लगाने के लिए वालंटियर नियुक्त किए गए हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने यह डरावनी जानकारी दी है कि पुनरीक्षण में ऐसे विदेशी नागरिक मिले जो मतदाता बन चुके हैं। उनकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी जा रही है और नागरिकता सुनिश्चित होने के बाद ही तय होगा कि वे मतदाता रहेंगे या नहीं। राजनीतिक दलों ने इस पर भी तूफान खड़ा कर दिया। निःसंदेह, आधार कार्ड या राशन कार्ड बनवाना आसान नहीं होता। इसलिए चिंता का विषय है कि यह हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार के भारी मुसलमान जनसंख्या वाले चार सीमांचल जिलों में आधार कार्ड के आंकड़े हैरत में डालते हैं।

बिहार में औसत आधार कार्ड आबादी के 94 फीसद है। किशनगंज में 68 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और आधार सैचुरेशन 126 प्रतिशत है, कटिहार (44 %) में 123 %, अररिया (43 %) में 123 %, और पूर्णिया (38 %) में 121 % आधार सैचुरेशन है। आबादी से अधिक आधार कार्ड कैसे बने हुए हैं? पिछले वर्ष अररिया में एक बंगलादेशी घुसपैठिये पकड़ा गया जिसके पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना से बना आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र था। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लड़ाई केवल असम और बंगाल में नहीं बिहार के इन सीमांचल जिलों में भी रही है। क्या विरोधियों के दबाव में उन सबकी जांच नहीं होनी चाहिए? संविधान की धारा 326 चुनाव आयोग को भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में अंकित करने का अधिकार देता है। हालांकि नागरिकता की पहचान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए उसने गृह मंत्रालय को मामला स्थानांतरित किया है।

विरोधी चाहे इसे एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को परोक्ष रूप से लागू करना माने या कुछ और किंतु भारतीय नागरिकों तक ही मतदान की व्यवस्था और पूरी मतदान प्रणाली की शुचिता तथा भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सतर्कता आवश्यक है। एक बार मतदाता सूची का प्रारूप आ जाने दीजिए और देखिए कि कितने लोग पात्र लोग इससे वंचित होते हैं। अगर संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जहां एक भी पात्र नागरिक सूची में स्थान पाने से वंचित नहीं हो वही एक भी अपात्र उसमें शामिल नहीं हो यह भी आयोग, राजनीतिक दलों, प्रशासन और हम सबका दायित्व है।

(लेख में विचार निजी हैं)

विरोधी चाहे इसे एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को परोक्ष रूप से लागू करना माने या कुछ और किंतु भारतीय नागरिकों तक ही मतदान की व्यवस्था और पूरी मतदान प्रणाली की शुचिता तथा भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सतर्कता आवश्यक है। एक बार मतदाता सूची का प्रारूप आ जाने दीजिए और देखिए कि कितने लोग पात्र लोग इससे वंचित होते हैं। अगर संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य का दांतों से भी संबंध

- मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों में दांतों की समस्याएं चार गुना ज्यादा होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडिस यूनिवर्सिटी, लॉ ट्रोब यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्क्सेस्टर्लैंड के शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन समस्याओं में मसूड़ों की बीमारी, दांतों का गिरना और कैविटी शामिल हैं
- रिसर्च में पाया गया कि मानसिक बीमारियों से आत्मविश्वास घटता है, जिससे लोग दांतों की सफाई और डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। गुटका दवाओं से लार कम बनती है, जिससे दांतों में सड़न बढ़ती है।

(मीडिया इन्पुट्स)

सभी दलों के, अधिकांश भारतीय राजनेता, वेशर्म बदमाश और बदमाशों का एक समूह हैं। जिनके पास लोगों के लिए कोई सच्चा प्यार नहीं है। वो केवल ताकत और पैसे की तलाश में रहते हैं और इसके लिए जाति और सांप्रदायिक घृणा फैलाकर समाज में ध्रुवीकरण करते हैं।

पूर्व जस्टिस मार्कंण्डेय काटजू
@mkatju

हिमालय | सुरेश भाई

नहीं चेते तो क्रोध पड़ेगा भारी

हिमालय में बाढ़ और भूस्खलन के चलते पर्यटकों और यात्रियों को बार-बार रोकना पड़ रहा है। गांव में रहने वाले लोग भारी बारिश के चलते राहत यो नहीं पाते हैं। ऐसी भी सैकड़ों बस्तियां हैं जिनके आस्पास विकास के नाम पर चारागाह, जंगल, खेती, पुराने रास्ते, नहरें क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहां से लोग भूस्खलन की डर से सुरक्षित स्थान की तरफ भाग जाते हैं। इस विषम परिस्थिति में गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक तकलीफ में हैं।

पुराने समय में हिमालय के पर्वतीय अंचल में जब बरसात प्रारंभ होती थी तो लोग अपने मवेशियों को लेकर जंगल में घास के बीच में छानियां बनाकर निवास करते थे। जहां से वे दूध, घी, मक्खन बनाकर बेचते थे और उसके बदले उन्हें साल भर की राशन खरीदना होता था। तब उनके चारों ओर आज की जैसी आपदा की स्थिति नहीं थी और बारिश में लोगों को अपनी खेती-बाड़ी में वारहनाजा (एक ही खेत में 12 प्रकार की फसल) की फसलें तैयार होती दिखाई देती थी। हिमालय के नीचे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बरसाती मौसम में नदियों में बहकर जाने वाली उपजाऊ मिट्टी, पानी को अच्छी फसल के संकेत मानते थे। अब वह पुराना समय चला गया है। गत वर्ष 2023-24 में जिस तरह की बाढ़ मध्य हिमालय से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में 500 से अधिक लोग मारे गए थे। उसकी पुनरावृत्ति सन 2025 की शुरुआती बरसात में ही दिख रही है। बरसात के मौसम का प्रभाव उत्तराखंड और हिमाचल पर सबसे अधिक है। केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले वर्षों से सड़क चौड़ीकरण के बाद दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं। जहां पर इस बार भी सोनप्रयाग के पास पहाड़ खिसकने से लगभग 1300 यात्रियों को रेस्क्यू करना पड़ा। जून के अंत में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलाई बैंड के पास निर्माण कार्य में लगे 18 मजदूरों में से 9 मजदूर बहकर लापता हो गये थे। यहां पर बहुत लंबे समय से औजरी, डाबरकोट, कुथनौर, पालीगाड़, सिलाई बैंड, किसाला आदि स्थान भू-धंसाव के लिए संवेदनशील बने हुए हैं। 2023-24 की बरसात में भी यहां पर लगातार निर्माण का मलबा सड़क पर बहकर आया था। इसके बावजूद भी करोड़ों खर्च करने के बाद इस मार्ग को चौड़ीकरण करने से पहले भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए जो वैज्ञानिक उपाय होने चाहिए थे उस पर ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण लंबे

समय से हर बरसात में यह स्थान यमुना नदी की तरफ टूट कर बह जाता है। यमुनोत्री आने-जाने वाले तीर्थयात्री बड़ी मुश्किल से इस भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक 6 किमी के पैदल रास्ते पर भी एक दर्जन ऐसे संवेदनशील स्थान वैज्ञानिकों ने चिह्नित किए हैं जहां भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस बार भी यहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अतः जरूरत है कि बहुत चौड़ी सड़क के स्थान पर जहां से भूस्खलन लगातार हो रहा है उस एरिया तक पहुंच बना करके ट्रीटमेंट करने पर ध्यान देना चाहिए। सड़क मार्ग को इस डेंजर जोन पर अधिक चौड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर स्यानाचट्टी के पास यमुना नदी पर झील बनने का खतरा बना हुआ है। जिस पर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां भूस्खलन क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, बालगंगा उफान पर हैं, लोग भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हिमाचल में पिछले 15 दिनों में लगभग 17 स्थानों पर बादल फटे हैं। अब तक लगभग 100 लोगों की जिंदगी चली गई है और 55 लोग लापता हैं। लगभग 80 हजार की आबादी पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंचते ही हालकार मच गया। ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सिक्किम में भूस्खलन से सेना का एक शिविर दब गया जिसमें तीन जवान शहीद हो गए थे और 6 लोग लापता हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी 10-10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 10 हजार लोग राहत शिविरों में रखे गए हैं। असम और मणिपुर में चार लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

प्रभावित लोग महसूस कर रहे हैं कि हिमालय की भौगोलिक संरचना को नजरअंदाज करके जिस तरह से फोरलाइन मार्गों का निर्माण, वनों का कटान, बहुमंजिली इमारतें, हिमालय की संवेदनशील धरती के साथ विकास के नाम पर अनियोजित छेड़छाड़, वार-वार भूकंप आना, अनियंत्रित पर्यटन और पंचतारा संस्कृति ने अधिक उपभोग करने की चाह में संकट पैदा कर दिया है। निर्माण कार्यों में नई रिक्षा खींचनी होगी और हिमालय पर विकास के नाम पर हो रहे मैदानों के अनुरूप जैसी छेड़छाड़ को रोका जाए।

अनुभव | ओशो

मुल्ला नसरुद्दीन नदी के किनारे गया था तैरना सीखने। जो उस्ताद उसे तैरना सिखाने को थे, वह तो एकदम चौंके, क्योंकि मुल्ला जैसे ही तट पर गया नदी के, पत्थर पर फिसल गया कहीं जमी होगी धड़ाम से

गिरा, एक पैर तो पानी में भी पड़ गया, कपड़े भी भीग गए, एकदम उठा और घर की तरफ भागा। उस्ताद ने कहा कि बड़े मियां, कहां जाते हो? मुल्ला ने कहा कि अब जब तक तैरना न सीख लूं, नदी के पास पैर न रखूंगा। यह तो खतरनाक धंधा है! यह तो उसकी दुआ कहो, यह तो उसकी कृपा कहो। अगर जरा और फिसलकर अंदर चला गया होता, तो उस्ताद, तुम तो खड़े थे बाहर, तुम तो देखते ही रहे, हम काम से गए थे! अगर अब तैरना कहां सीखोगे? कोई गद्दे-तकिए बिछा कर तैरना सीखा जाता है। और गद्दे-तकिए बिछाकर तुम कितना ही तैरने का अभ्यास कर लो, पानी में काम न आएगा, खयाल रखना। तैरना सीखने के लिए भी पानी के पास जाना ही पड़ता है। परमात्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध करोगे? तर्क से? विचार से? तो तो तुम उल्टे काम में लग गए। परमात्मा को जाना है तो लोगों ने निर्विचार से। परमात्मा को जाना है लोगों ने हृदय से। और तुम सिद्ध करने लगे बुद्धि से। नहीं सिद्ध होगा, तो आज नहीं कल तुम कहोगे: है ही नहीं। और एक बार तुम्हारे मन में यह बात गहरी बैठ गई कि है ही नहीं, तो बस अटक गए। तो तुम्हारा विकास अवरूद्ध हुआ। गलत प्रश्न न पूछो! पूछो कि क्या मैं हूं? पूछो कि कैसे मैं जानूं कि मैं कौन हूं? परमात्मा को छोड़ो! परमात्मा से लेना देना क्या है? पहले पानी की बूंद तो पहचान लो, फिर सागर को पहचान लेना। अभी बूंद से भी पहचान नहीं और सागर के संबंध में प्रश्न उठाए! हां, किताबों में इस तरह के प्रमाण दिए हुए हैं, बड़े-बड़े प्रमाण दिए हुए हैं, बड़े पंडित, शास्त्री प्रमाण देते हैं ईश्वर के होने का। और उनके प्रमाण सब बचकाने, दो कौड़ी के! क्योंकि प्रमाण कोई दिया ही नहीं जा सकता। क्या प्रमाण हैं उनके? इस तरह के प्रमाण कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। इसी तरह परमात्मा ने जगत को बनाया, वह कुम्भकार है कुम्हार है। अब जरा कोई इन बुद्धिमानों से पूछे कि अगर घड़े को बनाने के लिए कुम्हार की जरूरत है, तो कुम्हार को बनाने के लिए भी तो किसी की जरूरत है! वह कहते हैं, हां, परमात्मा ने कुम्हार को बनाया। फिर तुम्हारी दलील का क्या होगा? परमात्मा ने संसार बनाया, फिर परमात्मा को किसने बनाया? यही तो बुद्ध ने पूछा, महावीर ने पूछा।

रीडर्स मेल

दब गया असल मामला

9 जुलाई को बिहार में विपक्षी दलों के बिहार बंद के शोर में देश के अम संगठनों का भारत बंद का दव कर रह गया है। श्रमिक आंदोलन के नेताओं ने काफी दिनों से भारत बंद की तैयारी और ऐलान किया हुआ था। बिहार में विपक्ष नेताओं के द्वारा 9 जुलाई को ही बंद के कारण श्रमिक संगठनों की आवाज देश का मुद्दा नहीं बन पाया। यहां तक की समाचार पत्र और टीवी न्यूज चैनल में भी श्रमिक संगठनों के आंदोलन की रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिली थी। इसी कारण श्रमिक संख्याओं के नेताओं ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की आलोचना की है। देश के श्रमिक संगठन चाहते थे कि यदि भारत बंद सफल हो जाता है तो देश में श्रमिक संगठनों की बात सुनी जाएगी और उनकी मांगों पर जिसमें निजीकरण के विरोध में, ठेकेदारी प्रथा के विरोध में, श्रमिक का वेतन 26000 निश्चित करने एवं चार नये श्रमिक कानून के विरोध का मुद्दा चर्चा का विषय बनेगा और सरकार का ध्यान आकर्षित होगा, लेकिन बिहार बंद में उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

राहत भरा फैसला

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लोक सभा, राज्य सभा, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत और जिला पचायत सभी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को है। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर जिस तरह से बिहार के मतदाताओं के सामने संकट खड़ा हो गया है, उसको उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न रिट याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दूर कर दिया। यहां तक कि जिस तरह से घर-घर जाकर इम्यूनेशन फॉर्म वांट रहे थे और उसके साथ-साथ राहत पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन मतदाताओं को न्यायपालिका ने राहत जरूर प्रदान कर दी। निर्वाचन आयोग बिहार के मतदाताओं को यह कहकर मतदाता सूची से नाम नहीं हटा सकता कि उनके पास मूल दस्तावेज नहीं है। इस प्रकार से आधार और राशन कार्ड दस्तावेजों को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाताओं को राहत भरा आदेश जारी किया है। इसका प्रभाव देश के दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। जहां पर वोटर लिस्ट की समीक्षा होगी वहां पर मतदाताओं को यह फैसला राहत प्रदान करेगा।

मीना खानिया, दिल्ली

रोमांचक होगा बिहार चुनाव

नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक दोधारी तलवार बन गए हैं। उनके पास 14-15 फीसदी वोट है जो बिहार में किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी भले ही अकेले 160-170 सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना देखे, लेकिन नीतीश का साथ छोड़ना आसान नहीं। केंद्र में नीतीश के 12 सांसद मोदी सरकार के लिए बैसाखी का काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी न तो नीतीश को नाराज करना चाहती है और न ही उनकी वीमारी को नजरअंदाज कर सकती है। वहरहाल, एनडीए की स्थिरता, महागठबंधन के लोकलुभावन वादे और जन सुराज का सुधारवादी दृष्टिकोण टकराएंगे। एनडीए की जीत बीजेपी और नीतीश की प्रासंगिकता को मजबूत करेगी जबकि महागठबंधन की जीत इंडिया गठबंधन को बल देगी।

रवि शंकर, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक विजय कावरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया केयर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-बाइपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, वीरेन्द्र रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्वामीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6717
आर.एन.आई. नं. - बीआरएनएआई/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी